

करेंट अफेयर्स

Workbook

मार्च 2025



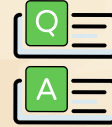
प्रोग्रेस ट्रैकिंग
टेबल



मुख्य परीक्षा हेतु
अभ्यास प्रश्न



एथिक्स
केस स्टडी



MCQs



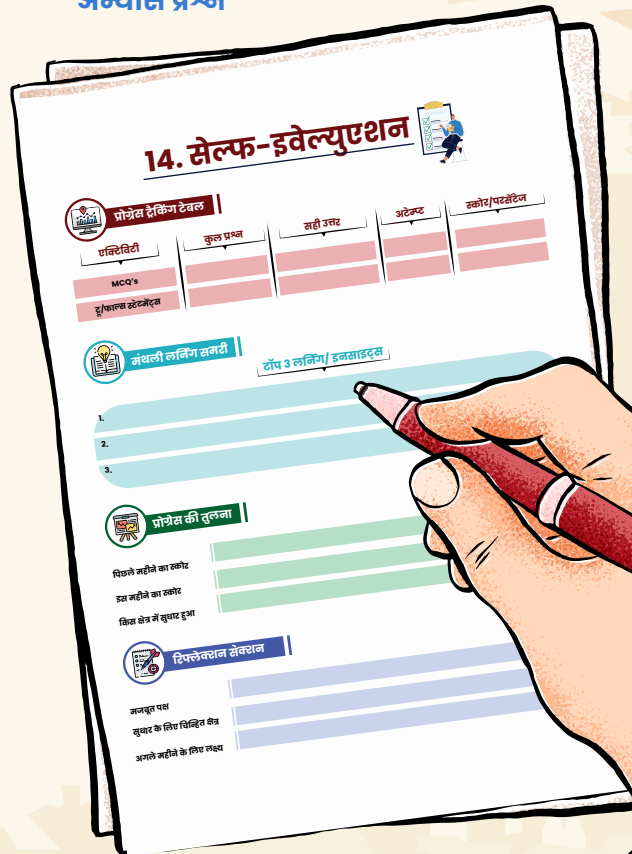
स्मरणीय
तथ्य



सारांश



ट्रू/फाल्स
स्टेटमेंट्स



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज

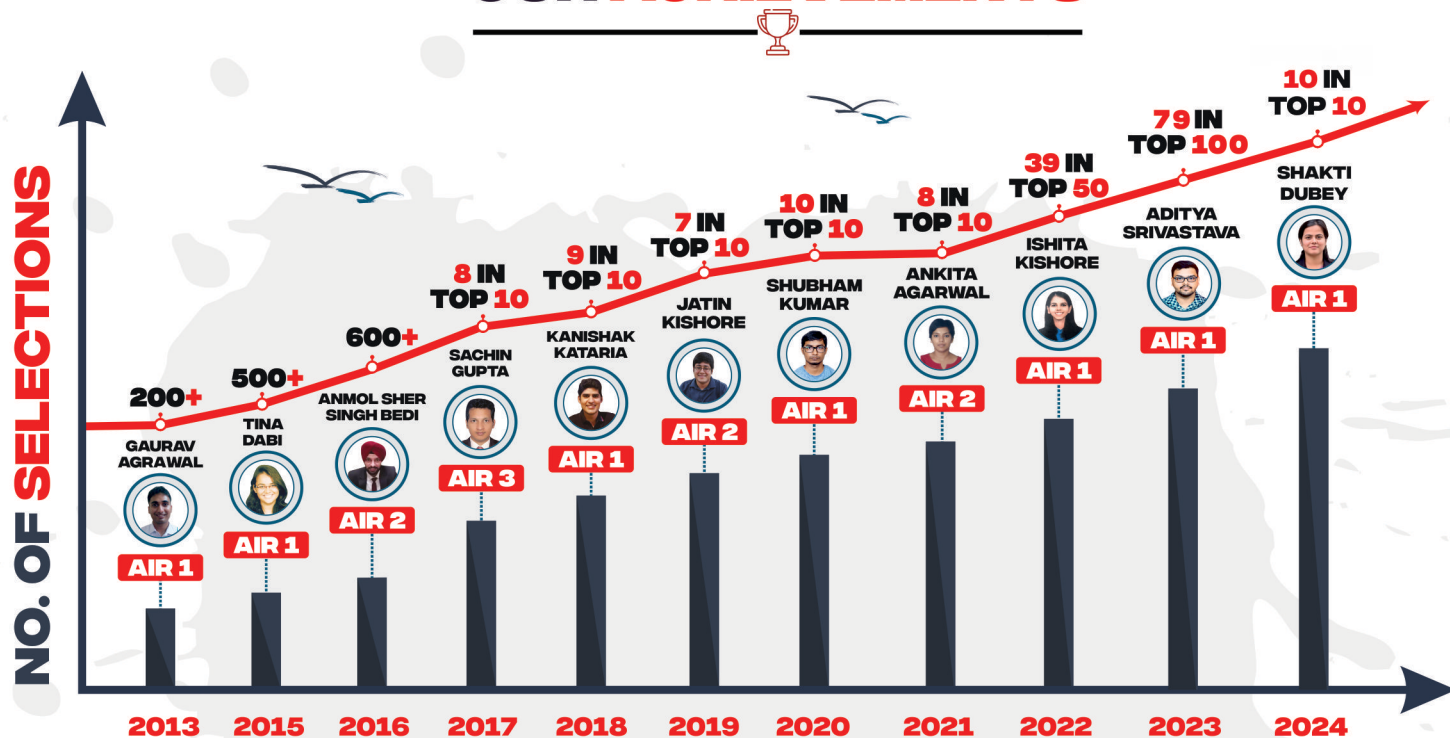


पुणे



राँची

OUR ACHIEVEMENTS



LIVE/ONLINE
Classes Available

www.visionias.in



Foundation Course

GENERAL STUDIES

PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 7 MAY, 8 AM | 8 MAY, 11 AM | 16 MAY, 5 PM
20 MAY, 11 AM | 21 MAY, 2 PM | 29 MAY, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
20 MAY, 11 AM | 27 MAY, 6 PM

AHMEDABAD: 7 JUNE

BENGALURU: 28 MAY

BHOPAL: 26 MAY

CHANDIARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 11 JUNE

JAIPUR: 10 MAY, 18 MAY

JODHPUR: 15 MAY

LUCKNOW: 19 MAY

PUNE: 8 MAY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

► प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 27 मई, 11 AM

JAIPUR : 12 मई

JODHPUR : 30 अप्रैल

प्रवेश प्रारम्भ

BHOPAL | LUCKNOW



Scan the **QR CODE** to download **VISION IAS App**. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.



/visionias.upsc



/c/VisionIASdelhi



/c/VisionIASdelhi



/t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi – 110005 **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

- 1.1. न्यायिक जवाबदेही (JUDICIAL ACCOUNTABILITY) . . . 6
- 1.2. बिग टेक कंपनियों का विनियमन (REGULATING BIG TECH) 7
- 1.3. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) 8

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

- 2.1. द्विपक्षीय निवेश संधि (BILATERAL INVESTMENT TREATY: BIT) 10
- 2.2. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION: IORA) 11
- 2.3. भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध (India-Mauritius Bilateral Relations) 12
- 2.4. भारत - न्यूजीलैंड संबंध (INDIA NEW ZEALAND RELATIONS) 13
- 2.5. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) 13

3. अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

- 3.1. तरलता घाटा (Liquidity Deficit) 15
- 3.2. कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme For Promotion of Low-Value BHIM-UPI Transactions) 16
- 3.3. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance in Electronics Component Manufacturing) 16
- 3.4. प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (Priority Sector Lending) 17
- 3.5. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष (50 YEARS OF MICROFINANCE) 18
- 3.6. भारत को विप्रेषण (REMITTANCES TO INDIA) . . . 19
- 3.7. यूनिफाइड पेंशन स्कीम {UNIFIED PENSION SCHEME (UPS)} 20
- 3.8. इक्विलाइजेशन लेवी (EQUALISATION LEVY). . . . 21
- 3.9. किसान उत्पादक संगठन (FARMER PRODUCER ORGANISATIONS: FPOS). 21
- 3.10. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (INDIA'S BIO-ECONOMY). 22
- 3.11. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NATIONAL

TECHNICAL TEXTILES MISSION: NTTM) 24

3.12. राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 {NATIONAL WATERWAYS (CONSTRUCTION OF JETTIES/TERMINALS) REGULATIONS, 2025}. 25

3.13. भारत के विकास के लिए कोयला क्षेत्रक (COAL SECTOR FOR INDIA'S DEVELOPMENT) 26

3.14. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NATIONAL PROGRAMME FOR DAIRY DEVELOPMENT: NPDD) . . 27

3.15. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) 29

4. सुरक्षा (SECURITY)

4.1. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका (ROLE OF QUANTUM COMPUTING IN NATIONAL SECURITY) 34

4.2. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) 35

5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. जैव ईंधन (BIOFUELS) 37

5.2. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NATIONAL BOARD FOR WILDLIFE: NBWL) 38

5.3. प्रोजेक्ट लायन और IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज (PROJECT LION AND IUCN GREEN STATUS OF SPECIES) 39

5.4. नदी डॉल्फिन (RIVER DOLPHINS) 40

5.5. जंपिंग स्पाइडर्स (JUMPING SPIDERS) 41

5.6. मरीन हीटवेव्स (MARINE HEATWAVES) 42

5.7. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA: GSI). 43

5.8. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts). 43

6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. सिनेमा और समाज (Cinema and Society) 49

6.2. सोशल मीडिया और किशोर (Social Media and Adolescents) 50

6.3. पारिवारिक संस्था में बदलाव (Changing Institution of Family) 51

6.4. महिलाओं के नेतृत्व में विकास (WOMEN-LED DEVELOPMENT) 52

6.5. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) 53

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

7.1. मानव संवर्धन (Human Enhancement) 55

7.2. रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (Strategic Crypto Reserve: SCR) 56

7.3. लाइट सुपरसॉलिड (LIGHT SUPERSOLID) 57

7.4. एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी दवाइयां {ANTI-RETROVIRAL THERAPY (ART) DRUGS}. 57

7.5. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) 58

8. संस्कृति (CULTURE)

8.1. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO WORLD HERITAGE SITES) 62

8.2. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) 67

9. नीतिशास्त्र (ETHICS)

9.1. अनुनय (PERSUASION) 69

9.2. प्रसन्नता/ सुख (HAPPINESS) 70

9.3. परोपकार: सामाजिक भलाई के लिए एक नैतिक अनिवार्यता (PHILANTHROPY: A MORAL IMPERATIVE FOR SOCIAL GOOD) 71

10. सुर्खियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

10.1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RASHTRIYA GOKUL MISSION) 73

11. क्विक फैक्ट्स

12. एक्टिविटी ब्लॉक

12.1. MCQS 80

12.2. टू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (True/false Statements) 82

12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions) 83

12.4. एथिक्स केस स्टडी (Ethics Case Studies) 84

13. उत्तर और व्याख्या

13.1. MCQs के उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explanantion) 85

13.2. टू/फाल्स स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers) 87

13.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण 87

13.4. केस स्टडीज़ के प्रति दृष्टिकोण 89

14. सेल्फ-इवेल्युएशन

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

137 AIR अंकिता कांति	182 AIR रवि राज	412 AIR जितेंद्र कुमारवत	438 AIR ममता	448 AIR सुख राम	483 AIR ईश्वर लाल गुर्जर	509 AIR अमित कुमार यादव
554 AIR विमलोक तिवारी	564 AIR गौरव छिम्वाल	618 AIR राम निवास सियाग	622 AIR आलोक रंजन	651 AIR अनुराग रंजन वत्स	689 AIR खेतदान चारण	718 AIR रजनीश पटेल
731 AIR तेशुकान्त	760 AIR अश्वनी दुबे	795 AIR कर्मवीर नरवाडिया	865 AIR आनंद कुमार मीणा	873 AIR सिद्धार्थ कुमार मीणा	890 AIR सुष्मा सागर	893 AIR अरुण मालवीय
895 AIR अजय कुमार	899 AIR रितिक आर्य	911 AIR अरुण कुमार	921 AIR ममता जोगी	925 AIR विजेंद्र कुमार मीणा	953 AIR राजकेश मीणा	998 AIR इकबाल अहमद

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

मार्च संस्करण की इस वर्कबुक के माध्यम से हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं, अपने उसी उद्देश्य के साथ – आपको समसामयिक विषयों की गहराई से समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करना। जैसे-जैसे प्रारंभिक परीक्षा समीप आ रही है, यह वर्कबुक आपके ज्ञान को सुदृढ़ करने और उसे प्रभावी रूप से अपनाने की क्षमता को निखारने का एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगी।

इस महीने की वर्कबुक उन प्रमुख विषयों पर केंद्रित है जो **राज्यवस्था एवं शासन**, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा परिदृश्य, आदि से जुड़े हैं। राज्यव्यवस्था एवं शासन खंड में न्यायिक जवाबदेही और बिग टेक के विनियमन से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और राज्य नियंत्रण की पारंपरिक परिभाषाओं को नए सिरे से परखने की मांग करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले खंड में, भारत की कूटनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा गया है। इसमें भारत-मॉरीशस रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय निवेश संधि, महासागर, IORA और विस्तारित समुद्री कूटनीति जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह खंड वैश्विक दक्षिण की अग्रणी आवाज के रूप में भारत की उभरती भूमिका और उसके बढ़ते प्रभाव को भी रेखांकित करता है।

अर्थव्यवस्था वाले खंड में, देश में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों की गहराई से पड़ताल की गई है, जिसमें बैंकिंग प्रणाली में तरलता की चुनौतियों से निपटने के प्रयासों से लेकर डिजिटल भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और जैव-अर्थव्यवस्था में नवाचार को प्रोत्साहित करने की पहलें शामिल हैं। एकीकृत पेंशन योजना जैसे कल्याणकारी उपायों और PSL में सुधारों को इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है कि कैसे वित्तीय नीतियां समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास का आधार बनती हैं।

सुरक्षा और प्रौद्योगिकी खंड में, हाल की अहम प्रगतियों को समाहित किया गया है, जिनमें क्वांटम कंप्यूटिंग के रणनीतिक पहलू और कोयला एवं ऊर्जा लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा, सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण, संस्कृति, नीतिशास्त्र और सुर्खियों में रही योजनाएं जैसे अन्य सेक्शन में भी इसी प्रारूप का पालन किया गया है।

वर्कबुक के मुख्य अंशों पर एक नज़र

- मासिक समसामयिकी का सारांश:** इसमें एक माह के मुख्य सुर्खियों, प्रमुख घटनाओं और ट्रेंड्स का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। यह सेक्शन एक्टिविटी से पहले समझ संबंधी फाउंडेशन को तैयार करता है।
- स्मरणीय तथ्य:** महत्वपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और सांख्यिकी का एक संदर्भ तैयार किया गया है, जिससे तेजी से रिवीजन करना और याद रखना आसान हो जाता है।
- एक्टिविटी ब्लॉक:**



MCQs: महत्वपूर्ण टॉपिक्स की समझ का परीक्षण कीजिए।



ट/फाल्स स्टेटमेंट्स: मुख्य तथ्यों की अपनी समझ को सत्यापित कीजिए।



मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: स्पष्टता के साथ टॉपिक्स को समझिए और व्याख्या कीजिए।



एथिक्स केस स्टडी: हालिया घटनाक्रमों को नैतिक दुविधाओं पर लागू कीजिए तथा निर्णय लेने से संबंधित कौशल को बेहतर कीजिए।



उत्तर और व्याख्या: इसमें तत्काल फीडबैक के लिए MCQs और ट/फाल्स प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं।

- प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल:** स्कोर रिकॉर्ड करने और सुधार के क्षेत्रों पर विचार करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है। इसके साथ अपनी प्रगति की निगरानी कीजिए।

हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इस वर्कबुक के साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, प्रत्येक टॉपिक को गहनता से पढ़ें, और इसे अपनी UPSC तैयारी की यात्रा में एक भरोसेमंद माध्यम बनाएं। यदि आपके पास सही रणनीति और मजबूत संकल्प है, तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी।

हार्दिक शुभकामनाएं,
करेंट अफेयर्स टीम,
VisionIAS



“हर दिन किए गए छोटे व समर्पित प्रयास ही अंततः सफलता की भव्य इमारत खड़ी करते हैं।”

- रॉबर्ट कॉलियर



राजव्यवस्था एवं शासन

(Polity and Governance)



1.1. न्यायिक जवाबदेही (JUDICIAL ACCOUNTABILITY)

सुझियों में क्यों?

दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास पर करोड़ों रुपये नकद मिलने से **भारत की उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।**

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रमुख तंत्र

- **पद से हटाया जाना:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 द्वारा शासित।
- **1999 की आंतरिक जांच प्रक्रिया:** यह न्यायिक नैतिकता को नियंत्रित करने वाले दो महत्वपूर्ण चार्टर्स - **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, 1997** और **न्यायिक आचरण संबंधी बेंगलोर सिद्धांत, 2002** पर आधारित है।
 - ➔ **C.J. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त** कर सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतों का निपटान कर सकता है।
 - ➔ **तीन सदस्यीय समिति** शिकायत की जांच करती है और पद से हटाने या आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।
 - ❖ किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में उस हाई कोर्ट को छोड़कर **अन्य हाई कोर्ट्स के दो मुख्य न्यायाधीश तथा एक न्यायाधीश शामिल होता है।**
 - ❖ किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में **सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश तथा अन्य हाई कोर्ट्स के दो मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।**
 - ❖ सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में समिति में **सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीश शामिल होते हैं।**
- **न्यायिक आचरण संबंधी बेंगलोर सिद्धांत:** स्वतंत्रता (Independence), सत्यनिष्ठा (Integrity), समानता (Equality), निष्पक्षता (Impartiality), सजगता/ औचित्य (Propriety), योग्यता और कर्मठता (Competence and Diligence)

भारत में न्यायिक जवाबदेही से संबंधित चिंताएं

- न्यायिक स्वतंत्रता के साथ टकराव
- पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया
- कोई अनिवार्य परिसंपत्ति प्रकटीकरण मानदंड नहीं
- सीमित नियंत्रण और संतुलन: न्यायपालिका अपने अधिकांश पहलुओं जैसे **न्यायाधीशों की नियुक्ति** आदि को स्वयं नियंत्रित करती है।
- जवाबदेही में बाधा डालने वाले अन्य प्रावधान: आपराधिक कार्रवाई से छूट/ उन्मुक्ति, RTI पर प्रतिबंध।

न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक:** इसे 15वीं लोक सभा में पेश किया गया था, लेकिन लोक सभा भंग होने के कारण यह व्यपगत हो गया।
- **राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC):** नियुक्तियों और कदाचार की जांच के लिए **भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट (80वीं व 121वीं)** द्वारा प्रस्तावित।
- **स्थायी अनुशासन समिति।**
- **न्यायिक निरीक्षण:** न्यायाधीशों के लिए एक स्थायी **प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली** विकसित की जा सकती है।

1.2. बिग टेक कंपनियों का विनियमन (REGULATING BIG TECH)

मुख्तियों में कयों?

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति की रिपोर्ट पर जनता से फीडबैक मांगा है।

पृष्ठभूमि

- इस समिति ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की समीक्षा की है।
- बिग टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा-विरोधी पद्धतियों पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं ने गूगल, मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी बिग टेक कंपनियों के लिए मजबूत विनियामक उपायों की मांग की है। जैसे- **मेटा और व्हाट्सएप बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (भारत, 2024-25)** आदि।

बिग टेक कंपनियों के विनियमन की आवश्यकता कयों है?

- संप्रभुता के लिए खतरा:** यूजर डेटा को अवैध रूप से एकत्रित करके और उसे देश के बाहर के सर्वरों पर भेजने से उसके दुरुपयोग का खतरा रहता है।
- नेटवर्क प्रभाव:** बिग टेक कंपनियां नेटवर्क प्रभाव का उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि उनके पास जितने अधिक यूजर्स होंगे, वे उतनी ही मजबूत होंगी। इससे नए प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा।
- राजकोष को राजस्व हानि:** बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर दुरुपयोग के कारण **भारत को प्रतिवर्ष लगभग 10 बिलियन डॉलर का नुकसान** होता है।
- डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिम:** बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण से उसके दुरुपयोग, निगरानी एवं उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है।
- नैतिक चिंताएं:** पारदर्शिता और जवाबदेही, लोक हित बनाम कॉर्पोरेट लाभ, डिजिटल डिवाइड और समानता, नैतिक नीति निर्माण और विनियमन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी।

बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने में चुनौतियां

- विनियामक शून्यता:** प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 एक्स-पोस्ट मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के घटित होने के बाद कार्रवाई की जाती है।
- प्रवर्तन में देरी:** उदाहरण के लिए- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA), 2025 को अभी लागू किया जाना है।
- विनियामक तंत्र का एकसमान न होना:** बड़ी टेक कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती हैं, लेकिन विनियामक प्रतिक्रियाएं अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती हैं।
- टेक्नो-राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद:** इससे देश घरेलू कंपनियों के पक्ष में हो जाते हैं।
- कानून की अस्पष्टता:** एक्स ने आई.टी. अधिनियम की धारा 69A के बजाय धारा 79 (3) (b) को लागू करके सोशल मीडिया पर कंटेंट को हटाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी, **सहयोग पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट का श्रेया सिंघल फैसला**।
- **आई.टी. अधिनियम की धारा 69A:** सरकार अनुच्छेद 19 (2) का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है।

बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिए प्रमुख कानून

भारत में

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA), 2023:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग के लिए प्रावधान करता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) या आईटी नियम, 2021:** भारत में बड़े यूजर आधार वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (SSMIs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002**
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** इसमें भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कंपनियों को दंडित करने का प्रावधान है।

वैश्विक

- यूरोपीय संघ:** डेटा संरक्षण और डिजिटल विनियमन के क्षेत्र में यूरोपीय संघ के प्रमुख कदमों में **जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR), 2016** और डिजिटल सर्विसेज एक्ट पैकेज के तहत प्रस्तावित **डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA)** शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र:** वर्ष 1980 में, संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक प्रथाओं पर आयोजित सम्मेलन के तहत "प्रतिबंधात्मक व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए बहुपक्षीय रूप से सहमत न्यायसंगत सिद्धांतों और नियमों के एक सेट" को स्वीकृति प्रदान की थी।

बिग टेक कंपनियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए आगे की राह

डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- डिजिटल प्रतिस्पर्धा के पूर्व-विनियमन की आवश्यकता।
- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम (SSDE):** मुख्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को नामित करना चाहिए।
- SSDEs के वर्गीकरण के लिए सीमाएं।**
- एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेज़ (ADEs):** उद्यमों को अपने समूह के अंतर्गत उन सभी अन्य उद्यमों की पहचान करनी चाहिए जो मुख्य डिजिटल सेवा की प्रदायगी में शामिल हैं।
- SSDEs के दायित्व:** SSDEs को निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन नहीं करना चाहिए:
 - अपने स्वयं के या संबंधित पक्ष के उत्पादों को प्राथमिकता देना या तीसरे पक्ष के ऐप्स को ब्लॉक करना।
- नियमों को ठीक से लागू करना:** CCI को अपनी तकनीकी क्षमता में सुधार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, तेजी से अपील के लिए NCLAT की एक अलग पीठ गठित की जानी चाहिए।
- दंड:** उल्लंघन करने पर SSDEs के वैश्विक कारोबार के 10% तक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

1.3. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

1.3.1. लोक सभा में 'आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025' पेश किया गया (IMMIGRATION AND FOREIGNERS BILL, 2025 INTRODUCED IN LOK SABHA)

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य **आप्रवास (आव्रजन) और विदेशियों से संबंधित विविध सेवाओं को सुव्यवस्थित** करना है। इसमें भारत में उनका प्रवेश, निकास और रहना शामिल है।

- यह विधेयक आव्रजन और विदेशियों से संबंधित सेवाओं को शासित करने वाले **मौजूदा चार कानूनों को निरस्त करता है**—
 - ➔ विदेशी विषयक अधिनियम, 1946,
 - ➔ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम (1920),
 - ➔ विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम (1939), और
 - ➔ आप्रवास (वाहक-दायित्व) अधिनियम (2000)।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **प्रवेश करने या ठहरने से रोकने के लिए आधार:** यदि विदेशियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोक स्वास्थ्य या विदेशी संबंधों के लिए खतरा माना जाता है, तो उन्हें देश में प्रवेश करने से वंचित किया जा सकता है।
 - ➔ इस संबंध में **आव्रजन अधिकारियों के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी** होंगे।
- **विदेशियों की ट्रेकिंग:** शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम जैसे संस्थानों को विदेशी नागरिकों की सूचना आव्रजन अधिकारियों को देनी होगी।
- **अन्य:** कानून के उल्लंघन पर **कठोर दंड का प्रावधान** किया गया है, जैसे- वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने पर **5 साल की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना** आदि।

1.3.2. दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल (DEDICATED CELL FOR MERCY PETITIONS)

महाराष्ट्र ने **मृत्युदंड** की सजा पाए दोषियों की **दया याचिकाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त सचिव (गृह) के अधीन एक समर्पित सेल** की स्थापना की है। महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय **सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (2024)** का पालन करता है।

दया याचिका (Mercy Petition) के बारे में

- न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद, दोषी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका (mercy petition) दायर करने का अंतिम संवैधानिक उपाय होता है।
- दया याचिका और क्षमा राष्ट्रपति या राज्यपाल की **विवेकाधीन शक्तियों** के अंतर्गत आते हैं, ये कानूनी अधिकार नहीं हैं।
- दया का उपयोग **क्षमादान की शक्ति** के माध्यम से किया जाता है, जिसे माफ़ करने की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है।

क्षमादान की शक्ति

- **राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)**
 - ➔ **क्षमा (Pardon):** सजा से पूर्ण मुक्ति।
 - ➔ **विराम (Respite):** दिव्यांगता या गंभीर स्थिति जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना।
 - ➔ **स्थगन (Reprieve):** कुछ समय के लिए किसी सजा (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है।

- ➔ **परिहार (Remit):** सजा की अवधि कम कर दी जाती है, जबकि इसकी प्रकृति वही रहती है।
- ➔ **लघुकरण (Commute):** सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे- मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
- **राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति** कोर्ट मार्शल के मामलों, संघीय कानूनों के उल्लंघन और मृत्युदंड के मामलों पर लागू होती है।
- **राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161):** राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्तियां हैं, लेकिन ये **मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों तक विस्तारित नहीं हैं**।
- **मरु राम बनाम भारत संघ मामले (1980)** में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि **राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं**।

1.3.3. संसद भाषिणी पहल (SANSAD BHASHINI INITIATIVE)

लोक सभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **AI-संचालित बहुभाषी संसदीय परिचालन के लिए संसद भाषिणी पहल** विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।

संसद भाषिणी पहल के बारे में

- **उद्देश्य:** संसद भाषिणी का उद्देश्य संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विविध भाषाओं की सुविधा प्रदान करने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक इन हाउस AI समाधान प्रदान करना है।
 - ➔ **भाषिणी** MeitY द्वारा निर्मित एक AI-संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है।
- संसद भाषिणी के अंतर्गत प्रमुख AI पहलों में **AI-आधारित अनुवाद, संसद की वेबसाइट के लिए AI-संचालित चैटबॉट** आदि शामिल हैं।

1.3.4. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई (STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ REPORT)

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है कि 2024-25 की तुलना में 2025-26 के लिए बजट अनुमान (BE) संबंधी आवंटन में मामूली वृद्धि की गई है।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख टिप्पणियां एवं सिफारिशें		
आधार	टिप्पणी	सिफारिशें
बजट आवंटन	संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान कम रहने की निरंतर प्रवृत्ति देखी गई है।	यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य फंड संबंधी अपनी मांग को समय पर प्रस्तुत करें तथा आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग करें।
योजनाओं का कार्यान्वयन	प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है; उदाहरण- संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।	ठोस कार्य योजना विकसित करना।

प्रशिक्षित जनशक्ति	सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है।	डिजिटल गवर्नेंस संबंधी पहलों को अपनाना चाहिए।
अनुदान के प्रकार	सशर्त (Tied) अनुदान (आवंटन का 60%) का उपयोग निर्धारित कार्य या योजनाओं के लिए होता है, जबकि बिना शर्त (Untied) वाले अनुदान (40%) का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।	सशर्त और बिना शर्त वाले अनुदान का विलय कर देना चाहिए।
पंचायत चुनाव	अलग-अलग राज्यों में पंचायत चुनावों में देरी देखी जा रही है, जैसे-कर्नाटक।	समय पर चुनाव कराना चाहिए।
राजस्व सृजन	सरकार से मिलने वाले अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है।	पंचायतों को संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य स्थानीय शुल्कों को लगाने का अधिकार देकर उन्हें अपने स्रोतों से राजस्व सृजित करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।

1.3.5. फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 (FUTURE OF FREE SPEECH INDEX 2025)

द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक नए वैश्विक सर्वेक्षण में फ्री स्पीच के समर्थन के मामले में 33 देशों में से भारत को 24वां स्थान दिया गया।

फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 के बारे में

- फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपाती थिंक टैंक है जो वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में स्थित है।
- फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स विवादास्पद भाषण, सरकार की आलोचना, मीडिया की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से इंटरनेट उपयोग की अनुमति देने की इच्छा के बारे में आठ सवालों के जवाबों पर आधारित एक समग्र सूचकांक है।

अन्य प्रमुख बिंदु

- स्वैडिनेवियाई देश (नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन) तथा दो निम्न लोकतांत्रिक देश (हंगरी एवं वेनेजुएला) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री स्पीच) के समर्थन में सबसे उच्चतम स्तर पर हैं।
- कुछ देशों में फ्री स्पीच के समर्थन में गिरावट: जापान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में 2021 के बाद से फ्री स्पीच के समर्थन में काफी गिरावट आई है।
- पारंपरिक मीडिया, सोशल मीडिया और AI कंटेंट जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे फ्री स्पीच को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा **2026**

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसेट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसेट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

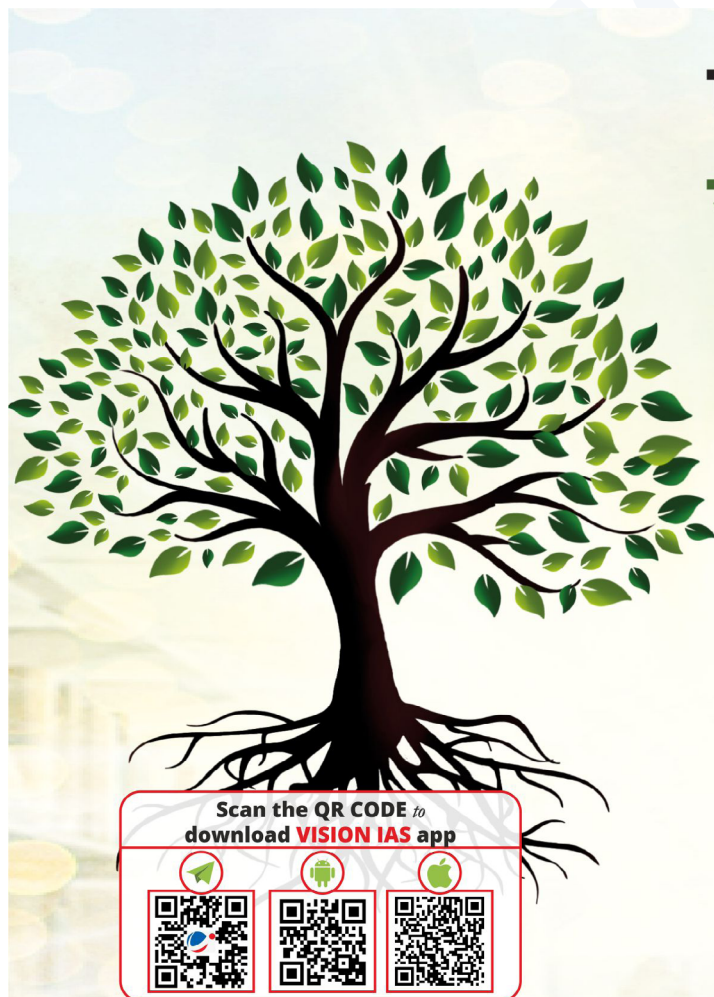
DELHI: 27 मई, 11 AM

JAIPUR: 12 मई

JODHPUR: 15 मई

प्रवेश प्रारम्भ

BHOPAL | LUCKNOW



अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)



2.1. द्विपक्षीय निवेश संधि (BILATERAL INVESTMENT TREATY: BIT)

सुखियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025 में **मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के प्रावधानों में संशोधन** के संबंध में घोषणा की गई थी, ताकि इसे और अधिक **निवेशक-अनुकूल** बनाया जा सके।

द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के बारे में

- **परिभाषा:** मेजबान देशों के विनियामक अधिकारों को संरक्षित करते हुए विदेशी निवेशकों की सुरक्षा करने वाले समझौते।
- **उद्देश्य:** निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) या राज्य-राज्य विवाद निपटान को सक्षम बनाना।
- **भारत का मॉडल BIT 2015:** 1993 के संस्करण को प्रतिस्थापित किया गया; BIT/ FTA वार्ताओं का मार्गदर्शन करता है (उदाहरण के लिए, 2024 में उज्बेकिस्तान व यू.ए.ई. के साथ समझौते)।
- **हाल ही में जिन देशों के साथ BIT पर हस्ताक्षर किए गए:** उज्बेकिस्तान (2024) और यू.ए.ई. (2024)।

मॉडल BIT 2015 की प्रमुख विशेषताएं

- **निवेश की "उद्यम" आधारित परिभाषा:** मेजबान देश के कानूनों के अनुपालन की आवश्यकता है।
- **गैर-भेदभाव और राष्ट्रीय उपचार:** विदेशी/ घरेलू निवेशकों के लिए समान स्तर।
- **एक्सप्रोप्रिएशन (स्वत्वाधिकार) के खिलाफ सुरक्षा:** राष्ट्र द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण को सीमित करता है।
- **कुछ गतिविधियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाना:** जैसे- सरकारी खरीद, कराधान, सब्सिडी, अनिवार्य लाइसेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा।
- **ISDS तंत्र:** कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि के लिए उस देश के स्थानीय विवाद निपटान तंत्र का उपयोग अनिवार्य।

भारत के वर्तमान BIT ढांचे से जुड़ी समस्याएं

- **अस्पष्टता:** "निवेश" जैसे अस्पष्ट शब्द विवादों को बढ़ावा देते हैं (37 नोटिस व 8 सक्रिय मामले)।
- **न्यायिक देरी:** 5-वर्षीय विवाद निपटान नियम स्थानीय अदालतों में और कार्य बोझ बढ़ाता है।
- **ISDS अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध:** उन्हें घरेलू न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के "मेरिट" की समीक्षा करने से रोक दिया गया है।
- **निवेशक प्रतिबंध:** कोई MFN/ निष्पक्ष व समान व्यवहार (FET) धाराएं नहीं; कर-संबंधी विनियामक उपाय शामिल नहीं, जैसे के रूप में मुआवजा आदि।
- **गैर-ICSID सदस्यता:** प्रवर्तन में बाधा (भारत विश्व बैंक के ICSID का हिस्सा नहीं है)।

वैश्विक आर्थिक सद्भाव के लिए द्विपक्षीय निवेश संधियों को बढ़ावा देना



घरेलू माध्यस्थम हब

NDIAC को मजबूत करना और घरेलू माध्यस्थम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशेष वकीलों को प्रशिक्षण देना।



शर्तों में स्पष्टता

संधि के उल्लंघनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, ताकि स्पष्ट समझ और प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके।



लचीला विवाद समाधान

संघर्ष समाधान को सरल और त्वरित बनाने के लिए प्रत्यक्ष माध्यस्थम की अनुमति देना।



संतुलित MFN/FET

निवेशक अधिकारों और राज्य संप्रभुता को संतुलित करने के लिए निवेशकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, BITs में MFN के प्रावधानों को उचित शर्तों के साथ शामिल किया जाना चाहिए।



ICSID अभिवृद्धि और कर सुधार

ISDS अधिकरणों को अपमानजनक या भेदभावपूर्ण कर संबंधी कार्रवाइयों की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए।

2.2. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION: IORA)

मुख्तियों में क्यों?

भारत 2025 में अगले दो वर्षों के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) के बारे में

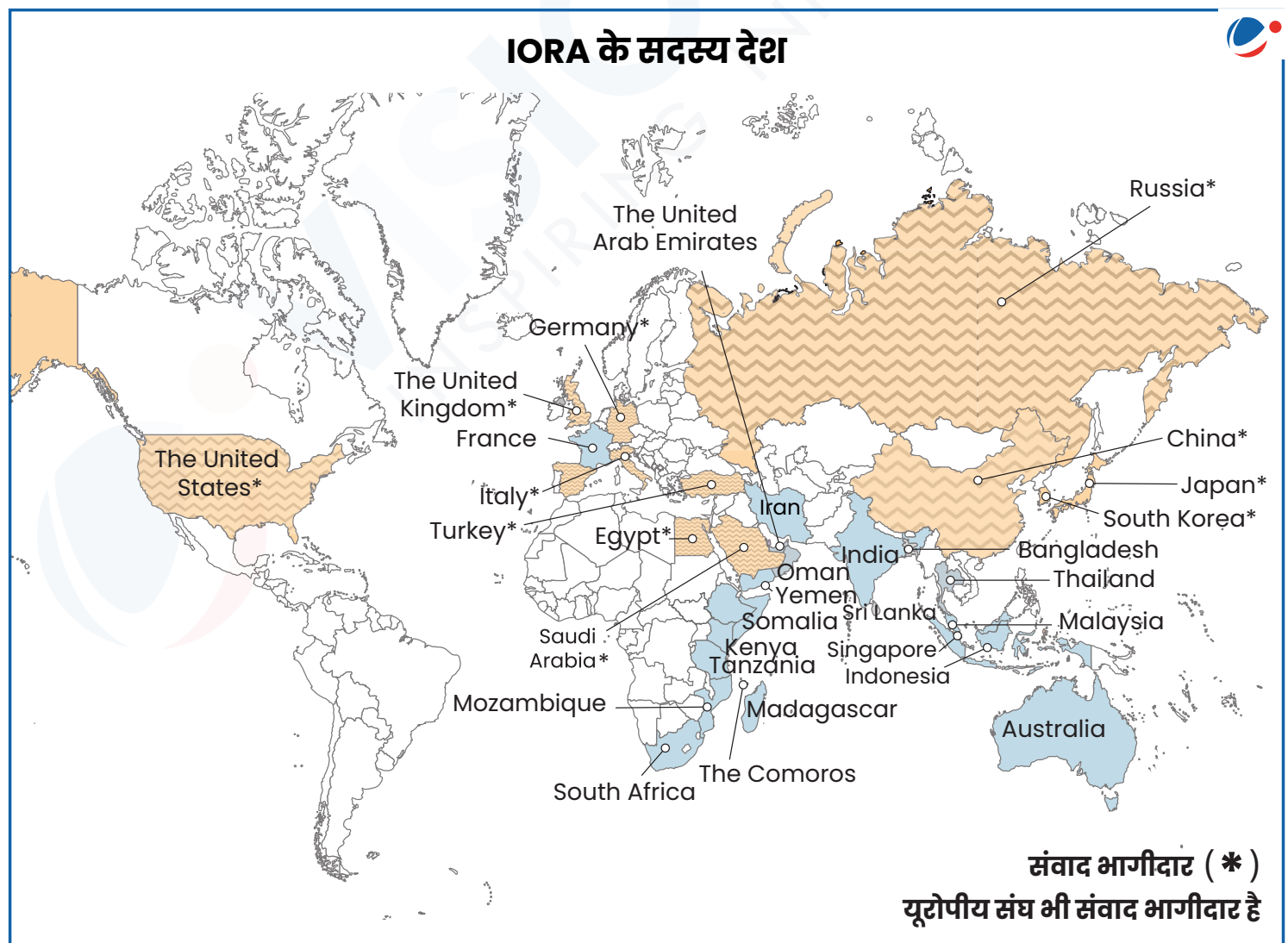
- उत्पत्ति: यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका विज़न 1995 में नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान सामने आया था।
- उद्देश्य: हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करना।
- सचिवालय: मॉरीशस
- सदस्य: 23 सदस्य और 12 संवाद साझेदार

भारत के लिए IORA का महत्त्व

- भू-सामरिक और आर्थिक: वैश्विक व्यापार का 75% परिवहन हिंद महासागर से होता है।
- वैकल्पिक मंच: सार्क/ बिस्मटेक की तुलना में कम विवादस्पद; क्वाड जैसी प्रतिद्वंद्विता से बचता है।
- समुद्री सुरक्षा: UNCLOS को कायम रखता है; समुद्री सुरक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित करता है।

चुनौतियां

- वित्त-पोषण: अपर्याप्त संसाधन; बिस्मटेक/ IONS के साथ प्रतिस्पर्धी
- संस्थागत सीमाएँ: मॉरीशस में सचिवालय की कमजोर क्षमता।
- भू-राजनीति: भारत-पाकिस्तान तनाव, चीन का BRI प्रभाव।
- अन्य मुद्दे: निजी क्षेत्र की भूमिका का अभाव, समुद्री खतरे (समुद्री डकैती, हूती विद्रोहियों द्वारा हमले)।



2.3. भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध (India-Mauritius Bilateral Relations)

सुझियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री की मॉरीशस यात्रा के दौरान, भारत और मॉरीशस ने **उन्नत रणनीतिक साझेदारी के लिए एक संयुक्त विज्ञान** का अनावरण किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- ➔ भारत ने 'ग्लोबल साउथ' के लिए भारत के नए विज्ञान की भी घोषणा की। इसे **"महासागर/ MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति)** नाम दिया गया है।
- ➔ **सेंट ब्रैंडन द्वीप** का एक नौवहन चार्ट भी मॉरीशस को सौंपा गया।

भारत के लिए मॉरीशस का महत्व:

- ➔ भारत ने 1948 में मॉरीशस की स्वतंत्रता से पहले ही उसके साथ **राजनयिक संबंध** स्थापित कर लिए थे।

भारत-मॉरीशस संबंधों में चुनौतियां

- ➔ **चीन का प्रभाव:** प्रमुख अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं का वित्त-पोषण, जैसे- हवाई अड्डा टर्मिनल, बांध, और कूज शिप टर्मिनल।
- ➔ **नृजातीय संलग्नता संतुलन:** विविध समुदायों (भारतीय, अफ्रीकी व यूरोपीय समुदाय) के साथ संलग्न होने की आवश्यकता।
- ➔ **मादक पदार्थों की तस्करी:** मॉरीशस मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र बन गया है, जो भारत के समुद्री हितों के समक्ष जोखिम पैदा कर रहा है।
- ➔ **पर्यावरणीय खतरे:** समुद्र का बढ़ता जलस्तर, चक्रवात, तटीय कटाव आदि।

आयाम	विवरण
सामरिक स्थिति	➔ यह भारत को समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी और अवैध मत्स्यन जैसे मुद्दों से निपटने में मदद करता है।
भू-राजनीतिक महत्व	➔ "हिंद महासागर का सितारा और कुंजी" रूप में जाना जाता है। ➔ चीन ने जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया है, जिससे मॉरीशस की सामरिक भूमिका और बढ़ गई है।
समुद्री सुरक्षा भागीदार	➔ यह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) का हिस्सा है।
सहयोग	➔ भारत ने मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया है।
अफ्रीका के लिए प्रवेश द्वार	➔ अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) का हिस्सा। ➔ भारत-मॉरीशस दोहरा करारान बचाव समझौता (DTAA)।
सांस्कृतिक संबंध	➔ मॉरीशस की लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है। ➔ गिरमिटिया (भारतीय बंधुआ मजदूर) की विरासत भारत और मॉरीशस के बीच एक गहरा ऐतिहासिक संबंध बनाती है।

महासागर/ MAHASAGAR विज्ञान क्या है?

- ➔ **विकास:** ग्लोबल साउथ पर फोकस के साथ SAGAR (2015) का विस्तार।
- ➔ **फोकस क्षेत्र:** व्यापार, सुरक्षा, तकनीक-साझाकरण व वित्तीय सहायता।
- ➔ **नई पहलें:**
 - ➔ **IOS सागर:** IOR के देशों के साथ समुद्री सहयोग।
 - ➔ **AIKEYME:** अफ्रीका-भारत नौसैनिक अभ्यास। संस्कृत में अर्थ 'एकता'।

नोट:

- ➔ **'महासागर':** इसे **भारतीय नौसेना ने 2023 में लॉन्च** किया था। यह भारत के सागर/ SAGAR विज्ञान के अनुरूप है।
- ➔ इसे 10 IOR देशों (मॉरीशस, सेशेल्स, आदि) के साथ **वर्ष में दो बार** आयोजित किया जाता है।

मॉरीशस (राजधानी: पोर्ट लुई)

- भौगोलिक दृष्टि से यह **मैस्करीन द्वीप समूह** का हिस्सा है।
- यह एक **ज्वालामुखीय द्वीप** है और लगभग पूरी तरह से **प्रवाल भित्तियों** से घिरा हुआ है।
- चागोस द्वीपसमूह पर अभी UK का अधिकार है, जबकि मॉरीशस इसे अपना क्षेत्र मानता है।
 - हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को सौंपने की UK की योजना को मंजूरी दे दी है।



2.4. भारत - न्यूजीलैंड संबंध (INDIA NEW ZEALAND RELATIONS)

सूत्रियों में क्यों?

न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री ने भारत की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा की।

यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नज़र

- ➔ न्यूजीलैंड IPOI और CDRi में शामिल हुआ।
- ➔ FTA के लिए भी वार्ता का शुभारंभ किया गया।

द्विपक्षीय संबंधों की समकालीन प्रासंगिकता

- ➔ द्विपक्षीय व्यापार: 1.75 बिलियन डॉलर (2023-24)। भारत का व्यापार अधिशेष 0.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- ➔ न्यूजीलैंड द्वारा निर्यात: ऊन, लोहा व इस्पात, फल एवं मेवे तथा एल्युमीनियम।
- ➔ भारत द्वारा निर्यात: फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, कीमती पत्थर आदि।
- ➔ रक्षा सहयोग: दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त टास्क फोर्स-150 में मिलकर काम कर रही हैं।
- ➔ बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग: दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता की वकालत करते हैं। न्यूजीलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।
- ➔ साझा सामरिक हित:
 - ➔ परमाणु निरस्त्रीकरण, नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक।
 - ➔ न्यूजीलैंड ने 2011 की अपनी "भारत के लिए दरवाजे खोलने" की नीति में भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में मान्यता दी थी।
- ➔ प्रवासी: भारत न्यूजीलैंड में कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।
- ➔ हरित ऊर्जा साझेदारी: न्यूजीलैंड 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का सदस्य बन गया था।
- ➔ घनिष्ठ खेल संबंध: क्रिकेट/हॉकी संबंध; खेल संबंधों के 100 वर्षों को मान्यता देने के लिए 2026 में 'स्पोर्टिंग यूनिटी' कार्यक्रम की योजना।



द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां

- ➔ लंबे समय से विलंबित FTA: 2010-2015 के बीच 10 दौर की वार्ता के बावजूद, भारत-न्यूजीलैंड FTA आर्थिक मतभेदों, विशेष रूप से डेयरी निर्यात और कृषि शुल्कों के कारण रुका हुआ है।
- ➔ सुरक्षा संबंधी चिंताएं: भारत ने न्यूजीलैंड में 'सिख फॉर जस्टिस' समूह द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों और खालिस्तान जनमत संग्रह सहित भारत विरोधी गतिविधियों पर अपनी चिंता जताई है।
- ➔ अन्य चिंताएं: कम द्विपक्षीय व्यापार अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है; न्यूजीलैंड के चीन के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध हैं आदि।

2.5. संक्षिप्त सूत्रियां (NEWS IN SHORTS)

2.5.1. भारत के साथ आर्थिक सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया का नया रोडमैप (AUSTRALIA'S NEW ROADMAP FOR ECONOMIC ENGAGEMENT WITH INDIA)

ऑस्ट्रेलिया का यह महत्वाकांक्षी रोडमैप भारत के साथ अपने व्यापार एवं निवेश संबंधों को और अधिक गहरा करने तथा उन्हें विविध बनाने पर केंद्रित है। इस रोडमैप में "विकास के चार अहम मार्गों" की पहचान की गई है।

रोडमैप के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- ➔ फोकस करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 50 विशेष अवसरों को चिन्हित किया गया है।
- ➔ 'ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार और निवेश प्रोत्साहन निधि'।
- ➔ ऑस्ट्रेलिया-इंडिया बिजनेस एक्सचेंज (AIBX): बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) भागीदारी में तेजी लाएगा।

- ➔ ऑस्ट्रेलिया-भारत CEO फोरम का नवीनीकरण।
- ➔ मैत्री अनुदान कार्यक्रम।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विकसित होते संबंध

- ➔ व्यापार: आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) 2021.
- ➔ परमाणु सहयोग: 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- ➔ रक्षा सहयोग: म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
 - ➔ दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं- ऑस्ट्राहिंद (AUSTRAHIND), ऑसिन्डेक्स (AUSINDEX) और पिच ब्लैक।

2.5.2. फाइव आइज इंटेलिजेंस एलायंस {FIVE EYES INTELLIGENCE (FVEY) ALLIANCE}

हाल ही में, कई देशों के खुफिया अधिकारी दिल्ली में एकत्रित हुए जिनमें फाइव आइज (FVEY) एलायंस के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

फाइव आइज इंटेलिजेंस (FVEY) एलायंस के बारे में

- उत्पत्ति: इसकी नींव 1946 में हस्ताक्षरित BRUSA समझौते के साथ रखी गई थी, जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस (SIGINT) पर केंद्रित था।
- सदस्य: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा (1948), ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड (1956 में शामिल)।
- गवर्नेंस: FIORC (2016) गैर-राजनीतिक खुफिया समीक्षा/ सुरक्षा की देखरेख करता है।

2.5.3. स्क्वाड एलायंस (SQUAD ALLIANCE)

फिलीपींस ने भारत से 'स्क्वाड' एलायंस में शामिल होने का आग्रह किया।

स्क्वाड एलायंस के बारे में

- यह एक अनौपचारिक मिनीलैटरल (लघुपक्षीय) गठबंधन है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं।
- उद्देश्य: हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना, स्थिरता को बनाए रखना आदि।
- यह क्वाड से अलग है, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

2.5.4. ओटावा कन्वेंशन (OTTAWA CONVENTION)

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया रुस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना बना रहे हैं।

ओटावा कन्वेंशन के बारे में

- आधिकारिक नाम: 'कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़, स्टॉकपिलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी-पर्सनल माइंस एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन' है।
- उद्देश्य: यह पक्षकार देशों को किसी भी परिस्थिति में एंटी-पर्सनल माइंस का उपयोग, विकास या भंडारण न करने हेतु बाध्य करता है।
- अंगीकरण व प्रवर्तन: ओस्लो (1997) में अपनाया गया था। ओटावा में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और 1999 में प्रभावी हुआ था।
- हस्ताक्षरकर्ता: 133 देश, भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

2.5.5. रायसीना डायलॉग (RAISINA DIALOGUE 2025)

नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण आयोजित किया गया।

रायसीना डायलॉग के बारे में

- मेजबान: विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।
- इसके बारे में: यह समकालीन भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र मुद्दों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है।
- भागीदारी: 1125 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष व सरकार प्रमुख, शिक्षाविद्, थिंक टैंक, युवा आदि शामिल हैं।
- थीम (2025): "कालचक्र - पीपल, पीस एंड प्लेनेट"।

मासिक समसामयिकी रिवीजन कक्षाएं 2025

GS प्रीलिम्स और मेन्स

हिन्दी माध्यम



English Medium

27 MAY | 2 PM

20 MAY | 2 PM



अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें



► Live/Online Classes are available



3.1. तरलता घाटा (Liquidity Deficit)

मुखियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली में उच्च तरलता घाटा (लिक्विडिटी डेफिसिट) को कम करने के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान लिक्विडिटी डेफिसिट पिछले 15 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

RBI ने निम्नलिखित तरीके से लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास किया है:

- ➔ **खुले बाजार का परिचालन (OMO):** 1,00,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां की खरीद।
- ➔ RBI ने 36 माह की अवधि के लिए **10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की USD/ INR खरीद/ बिक्री स्वैप नीलामी** आयोजित की है।

बैंकिंग तरलता	
परिभाषा	बैंकिंग तरलता से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली को प्रदान की गई आरक्षित निधि (नकदी) से है
फॉर्मूला	बैंकिंग तरलता = चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत निवल उधारी - बैंकों द्वारा प्रबंधित अधिशेष आरक्षित निधि
तरलता घाटा	बैंकिंग प्रणाली RBI का निवल ऋणी है (बैंकिंग प्रणाली की नकदी की मांग धनात्मक है अर्थात बैंकों के पास नकदी की कमी है और वह RBI से उधार ले रहा है)
तरलता अधिशेष	बैंकिंग प्रणाली RBI का निवल ऋणदाता है (बैंकिंग प्रणाली की नकदी की मांग ऋणात्मक है, अर्थात बैंकों के पास अधिक नकदी है और वह RBI को उधार दे रहा है)
चलन में मुद्रा (Currency in Circulation: CIC) से संबंध	$\uparrow \text{CIC} = \downarrow \text{बैंक में आरक्षित निधि} = \downarrow \text{बैंकिंग तरलता}$ $\downarrow \text{CIC} = \uparrow \text{बैंक में आरक्षित निधि} = \uparrow \text{बैंकिंग तरलता}$
वर्तमान स्थिति:	जनवरी 2025 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता घाटा 15 साल के उच्चतम स्तर (3.15 ट्रिलियन रुपये) पर पहुंच गया। फरवरी 2025 में यह घाटा 1.59 लाख करोड़ रुपये था।

तरलता घाटे के लिए उत्तरदायी कारण

- ➔ **कर के लिए धन निकासी:** 3 ट्रिलियन (दिसंबर 2024) रुपये के अग्रिम करों से तरलता में कमी आई।
- ➔ **जस्ट-इन-टाइम SNA-SPARSH ट्रांजिशन:** बैंकिंग प्रणाली में सीमित निधि।
- ➔ **विदेशी मुद्रा बाजार:** FII द्वारा बिकवाली और रुपये को स्थिर करने के लिए RBI द्वारा डॉलर की बिक्री।
- ➔ **त्योहार के लिए बैंक से पैसा निकासी:** दिवाली, क्रिसमस, महाकुंभ 2025 के दौरान नकदी की मांग में वृद्धि।

तरलता घाटे का प्रभाव

- ➔ बैंकों से उधार देने के लिए बैंक उच्च ब्याज दर पर उधार लेकर लोगों को उधार देते हैं, मौद्रिक नीति का लाभ मिलने में देरी, ऋण उपलब्धता में कमी, बैंकों के लाभ में कमी और बाजार में अस्थिरता।

तरलता प्रबंधन के लिए RBI के पास उपलब्ध साधन

- ➔ तरलता समायोजन सुविधा (LAF), खुले बाजार परिचालन (OMOs), बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS), नकद आरक्षित अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) और विदेशी मुद्रा स्वैप।

3.2. कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme For Promotion of Low-Value BHIM-UPI Transactions)

मुख्तियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले BHIM-UPI (P2M) लेनदेन के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

प्रमुख तथ्य

- ➔ **कवरज:** 1,500 करोड़ रुपये के परिव्यय (वित्त वर्ष 2024-25) के साथ UPI पर्सन-2-मर्चेट (P2M) लेन-देन।
- ➔ **प्रोत्साहन:** छोटे व्यापारियों के लिए प्रति लेनदेन 0.15% (2,000 रुपये तक)।
- ➔ **लक्ष्य:** BHIM-UPI को बढ़ावा देना, 20,000 करोड़ लेन-देन प्राप्त करना, टियर 3-6 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में UPI का विस्तार करना ताकि ऋण तक पहुंच बढ़ाई जा सके।

BHIM के बारे में

- ➔ **NPCI द्वारा कैशलेस भुगतान के लिए UPI-आधारित मोबाइल ऐप, 2016 में लॉन्च किया गया।**
- ➔ **विशेषताएं:** मोबाइल, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA), QR कोड के जरिए तत्काल हस्तांतरण; कई भुगतान मोड से बहु-स्रोतों से सत्यापन प्रमाणीकरण प्रणाली (UPI-ID, आधार नंबर) द्वारा सुरक्षित।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के बारे में

- ➔ भारत में **खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों** का प्रबंधन करने वाला एक **अम्बेला संगठन**।
- ➔ इसे **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत **RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA)** द्वारा शुरू किया गया।
- ➔ RuPay, IMPS और अन्य भुगतान प्रणालियों की शुरुआत की गई।

3.3. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance in Electronics Component Manufacturing)

मुख्तियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना अधिसूचित की।

योजना के बारे में

- ➔ **इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला:** 4 खंडों में विभाजित - डिज़ाइन, कंपोनेंट्स, असेंबली और मूल उपकरण विनिर्माण।
- ➔ **योजना का फोकस:** निष्क्रिय/ गैर-अर्धचालक घटक जैसे रेसिस्टर्स और कैपेसिटर्स।
- ➔ **प्रोत्साहन:** टारगेट सेगमेंट के उत्पादन के लिए **निर्धारित वित्तीय सहायता** प्रदान करता है।

पुर्जों के विनिर्माण के अनुकूल परिवेश का विकास	
उद्देश्य	वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) के साथ घरेलू उद्योगों को एकीकृत करके वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना।
प्रमुख रणनीतियां	घरेलू मूल्यवर्धन (DVA) बढ़ाने के लिए वैश्विक/ घरेलू निवेश को आकर्षित करना।
वित्तीय प्रोत्साहन	टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव: 6 वर्ष + 1 वर्ष का अतिरिक्त प्रोत्साहन शुरूआती अवधि के लिए (इन्क्यूबेशन पीरियड) कैपेक्स इंसेंटिव: 5 वर्षों के भीतर निवेश के लिए समर्थन हाइब्रिड इंसेंटिव: टर्नओवर-लिंक्ड और कैपेक्स सहायता का मिश्रण
प्रमुख जानकारी	आधार वर्ष: वित्त वर्ष 2024-25 नोडल एजेंसी: परियोजना प्रबंधन एजेंसी
पात्रता	ग्रीनफील्ड (नई) और ब्राउनफील्ड (मौजूदा), दोनों परियोजनाएं पात्र

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलें

- ➔ **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** यह सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करता है।
- ➔ **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम:** यह स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को बढ़ावा देता है।
- ➔ **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019:** भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग (ESDM) हब बनाने का लक्ष्य।
- ➔ **आईटी हाईवेयर के लिए PLI योजना 2.0:** यह लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी आदि के लिए घटकों/उप-असेंबली का स्थानीयकरण करती है।

- ➔ **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (LSEM) के लिए PLI योजना:** यह मोबाइल फोन विनिर्माण और इसकी मूल्य श्रृंखला में निवेश को बढ़ावा देती है।

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र: अवलोकन

- ➔ **वर्तमान स्थिति:** वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का 4% हिस्सा है, असेंबली पर मुख्य ध्यान है।
- ➔ **घरेलू उत्पादन वृद्धि:** उत्पादन 5 गुना बढ़कर 9.52 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 24) हो गया; भारत में बिकने वाले 99% स्मार्टफोन स्थानीय रूप से निर्मित हैं।
- ➔ **संवृद्धि के चालक:** बड़ा घरेलू बाजार, कम लागत पर कुशल श्रम उपलब्ध होना, सरकारी पहलें (मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया), आदि।
- ➔ **प्रभुत्व:** असेंबली पर उच्च निर्भरता, डिजाइन और घटकों में नवाचार पर कम ध्यान।

भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों है?

- ➔ **राष्ट्रीय सुरक्षा:** विदेशी उपकरणों (कंपोनेंट्स) पर निर्भरता (चीन/हांगकांग से 56%) से डेटा उल्लंघनों का खतरा।
- ➔ अविकसित स्थानीय विनिर्माण के कारण **अधिक आयात।**
- ➔ **रणनीतिक अवसर (चीन+1):** निवेश की क्षमता प्रदान करता है।
- ➔ **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:** कम लागत वाला विनिर्माण (थाईलैंड के न्यूनतम वेतन का 46%, 12 गुना बड़ा श्रम बल - PWC)।

इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माताओं के लिए चुनौतियां

- ➔ **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:** अधिक लीड टाइम, उच्च परिवहन लागत (उदाहरण के लिए, चीन से स्मार्टफोन शिप करने में \$0.80 बनाम भारत से \$8 - PWC)।
- ➔ **वैश्विक अल्पाधिकार:** बाजारों पर जापान (R&D) और ताइवान (अमेरिकी समर्थन) का प्रभुत्व।
- ➔ **अविकसित सहायक उद्योग:** उदाहरण के लिए, रासायनिक उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की कमी।
- ➔ **क्रिटिकल मिनरल्स की कमी:** गैलियम, जर्मेनियम जैसे दुर्लभ खनिज (**चीन-प्रभुत्व**) आपूर्ति संबंधी जोखिम बढ़ाते हैं।
- ➔ **कुशल कार्यबल की कमी:** सरफेस-माउंट टेक्नोलॉजी (SMT) लाइनों जैसी प्रणालियों के मामले में।

निष्कर्ष

नीति आयोग एक आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण तंत्र स्थापित करने के लिए R&D/ डिजाइन को प्रोत्साहित करने, टैरिफ को कम करने, कौशल बढ़ाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम करने और अवसरचना को बेहतर करने की सिफारिश करता है।

3.4. प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (Priority Sector Lending)

सुखियों में क्यों?

RBI ने प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो गए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ➔ **दिशा-निर्देश:** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किए गए।
- ➔ **कवरेज:** सभी वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCB) पर लागू (वेतन अर्जक बैंकों को छोड़कर)।

प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) के बारे में

- ➔ **परिभाषा:** सरकार और RBI द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए चिन्हित 'प्राथमिकता विकास वाले क्षेत्रक'।
- ➔ **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
 - ➔ **1969 - गाइडिल समिति:** एरिया अप्रोच प्रस्तावित किया, जिससे **लीड बैंक योजना** बनी।
 - ➔ **1972 - PSL औपचारिक रूप दिया गया:** उन क्षेत्रकों को ऋण देना जिन्हें इसकी जरूरत है पर उन्हें मिल नहीं पा रहा है।
 - ➔ **1982 - घोष समिति:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक श्रेणियों को संशोधित और पुनर्वर्गीकृत करने का सुझाव दिया।

'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (PSL)' के अंतर्गत श्रेणियां



कृषि



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम



निर्यात ऋण



शिक्षा



आवास



सामाजिक अवसरचना



नवीकरणीय ऊर्जा



अन्य

संशोधित दिशा-निर्देश

- ➔ ऋण सीमा में वृद्धि: शिक्षा (25 लाख रुपये तक), सामाजिक अवसंरचना (8 करोड़ रुपये तक) और आवास और कृषि ऋण जैसे अन्य क्षेत्रक।
- ➔ विस्तारित नवीकरणीय ऊर्जा ऋण: सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए ₹35 करोड़ तक और व्यक्तिगत परिवारों के लिए ₹100 लाख तक।
- ➔ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए संशोधित PSL लक्ष्य:
 - कुल प्राथमिकता क्षेत्रक: 60% (पहले 40%); सूक्ष्म उद्यम: 7.5%; कमजोर वर्ग: 12%
- ➔ विस्तारित 'कमजोर वर्ग' श्रेणी: ट्रांसजेंडर, लघु और सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह (SHG), आदि सहित।

प्राथमिकता क्षेत्रक के लिए लक्ष्य/ उप-लक्ष्य

श्रेणियां	लक्ष्य/ उप-लक्ष्य			
	घरेलू वाणिज्यिक बैंक और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक	20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	लघु वित्त बैंक
कुल प्राथमिकता क्षेत्रक	40%	40% (नियमित ऋण के लिए 32% तक और किसी अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए कम से कम 8%)	75%	75%
कृषि	18%	लागू नहीं	18%	18%
सूक्ष्म उद्यम	7.5%	लागू नहीं	7.5%	7.5%
कमजोर वर्ग	12%	लागू नहीं	15%	12%

नोट: उपर्युक्त प्रतिशत समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (CEOBSE) - इनमें से जो भी अधिक हो, उसके प्रतिशत के रूप में है।

अतिरिक्त प्रावधान

- ➔ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) और आवासन वित्त कंपनियों (HFCs) को दिया गया ऋण अब PSL के तहत शामिल होगा।
- ➔ PSL पात्रता के लिए को-लेंडिंग मॉडल (बैंक + NBFCs) को मान्यता दी गई।
- ➔ NBFC स्वर्ण-समर्थित ऋणों को छोड़कर, प्रतिभूतिकरण मानदंडों को संशोधित किया गया।
- ➔ PSL लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण प्रमाण-पत्र (PSLCs) के व्यापार की अनुमति।
- ➔ सटीक वर्गीकरण करने के लिए अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाण-पत्र (IBPCs) और प्रत्यक्ष असाइनमेंट मानदंडों को अपडेट किया गया।

अन्य हालिया सुधार

- ➔ प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण प्रमाण-पत्र (PSLCs): दक्षता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया।
 - बैंकों को PSL लक्ष्यों को पूरा करने के लिए PSL प्रमाण-पत्र (PSLCs) की खरीद-बिक्री की अनुमति दी गई है। PSLCs एक तरह से खरीद-बिक्री योग्य इंस्ट्रुमेंट्स हैं। इसके तहत जो बैंक अधिक PSLCs प्राप्त करते हैं वे इसे कम PSLCs प्राप्त करने वाले बैंकों से खरीद सकते हैं।
 - प्रकार: PSLC-कृषि, PSLC-MSME, PSLC-सामान्य, PSLC-कमजोर वर्ग।
- ➔ सह-ऋण मॉडल (CLM): यह व्यवस्था 2020 में बैंकों और NBFCs के लिए शुरू की गई थी, ताकि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को मिलकर संयुक्त रूप से ऋण प्रदान कर सकें।
 - हाल ही में, RBI ने सभी विनियमित संस्थाओं के बीच सभी ऋण (PSL ऋण या अन्य कोई ऋण) के लिए को-लेंडिंग व्यवस्था हेतु एक मसौदा फ्रेमवर्क जारी किया है।

3.5. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष (50 YEARS OF MICROFINANCE)

सुखियों में क्यों?

स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) बैंक, जो 1974 में गुजरात में एक सहकारी बैंक के रूप में शुरू हुआ, भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

- ➔ परिभाषा: माइक्रोफाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त संस्थान गरीब ग्रामीण परिवारों और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करता है।
- ➔ सेवाएं: ऋण, बीमा, वित्तीय सलाह आदि।
- ➔ उत्पत्ति: बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनूस की ग्रामीण बैंक (1976) की योजना।

भारत में माइक्रोफाइनेंस का विकास	
(1974-1990) पारंपरिक माइक्रोफाइनेंस	सबसे गरीब लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए SEWA बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की स्थापना।
(1991-1999) आर्थिक सुधार	SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत और महिलाओं और MSMEs के लिए समर्थन।
(2000-2012) परिवर्तन का युग	फॉर-प्रॉफिट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का प्रवेश, जिसने सूक्ष्म वित्त परिदृश्य को बदल दिया।
(2012 के बाद) भविष्य की राह	वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (FIDD) की स्थापना।

भारत में माइक्रोफाइनेंस का महत्व

- ➔ गरीबी उन्मूलन: उदाहरण के लिए, नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने 144 लाख SHGs के माध्यम से 17.8 करोड़ परिवारों को सशक्त बनाया।
- ➔ आर्थिक विकास और उद्यमिता: उदाहरण के लिए, 46% ऋण 20,000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों का समर्थन करते हैं।
- ➔ महिला सशक्तिकरण: उदाहरण के लिए, बैंक से जुड़े 88% SHGs (जैसे केरल का कुदुम्बश्री) महिलाओं के नेतृत्व में संचालित होते हैं।
- ➔ वित्तीय समावेशन: MFIs उन परिवारों को वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं जिन्हें पारंपरिक बैंकों से वित्तीय सेवा प्राप्त नहीं हो रही है।
- ➔ सामाजिक प्रभाव: उदाहरण के लिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की छोटे कदम पहल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) का नवीनीकरण किया।

भारत में माइक्रोफाइनेंस से संबंधित चुनौतियां:

- ➔ अति-ऋणग्रस्तता, उच्च ब्याज दरें (30% तक), कई विनियामक संस्थाओं द्वारा (RBI, राज्य सहकारी समितियां) विनियमित, MFIs की वित्तीय व्यवहार्यता, और बाह्य प्रभाव (प्राकृतिक आपदाएं) से डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है।

माइक्रोफाइनेंस को मजबूत करने के लिए सरकारी पहलें

- ➔ SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम: SHG को अधिक ऋण प्रदान करना, उत्पादन-आधारित गतिविधियों को अपनाने पर बल।
- ➔ प्रधान मंत्री मुद्रा योजना: 20 लाख रुपये तक का कोलेटरल-मुक्त माइक्रो क्रेडिट प्रदान करता है।
- ➔ RBI नीति (2014): NBFC-MFIs को बैंकों के लिए बिजनेस कॉरिस्पोडेंट (BCs) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी।
- ➔ RBI नियामक फ्रेमवर्क (2022): माइक्रोफाइनेंस ऋण से जुड़ी परिभाषाओं और पुनर्भुगतान सीमाओं को स्पष्ट किया।
- ➔ नाबार्ड पुनर्वित्त: MFIs को दीर्घकालिक पुनर्वित्त प्रदान करता है।

आगे की राह

- ➔ ऋणदाताओं को सीमित करना: प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम तीन संस्थाओं से ही ऋण लेने की अनुमति दी जाए। साथ ही एक व्यक्ति को माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से 3 लाख रुपये की बजाय अधिकतम दो लाख रुपये ही ऋण दिए जाए।
- ➔ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का एकीकरण: मशीन लर्निंग मॉडल किसी व्यक्ति के ऋण वापस करने के व्यवहार का विश्लेषण करके संभावित डिफॉल्ट की समय रहते पहचान कर सकते हैं।
- ➔ क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकरण: माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को किफायती आवास, जलवायु परिवर्तन, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य-देखभाल जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।
- ➔ वित्तीय साक्षरता: वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, बीमा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और माइक्रोफाइनेंस उद्योग की वृद्धि में सहायक हो सकती है।
- ➔ सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखना: तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में माइक्रोफाइनेंस वितरण नेटवर्क अच्छी तरह से विकसित हैं। देश के अन्य क्षेत्रों को भी इन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है।

3.6. भारत को विप्रेषण (REMITTANCES TO INDIA)

मुख्तियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले चार वर्षों में अमेरिका और ब्रिटेन खाड़ी देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत में रेमिटेंस के शीर्ष स्रोत बन गए हैं।

भारत में रेमिटेंस अंतर्वाह के मुख्य रुझान

- ➔ रेमिटेंस प्राप्ति: भारत को 2023-24 में 118.7 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ। यह 2011 की तुलना में दोगुना है।
- ➔ पांच देश जहां से भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त हुआ (2023-24): संयुक्त राज्य अमेरिका (27.7%) पहले स्थान पर है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE), यूनाइटेड किंगडम (UK), सऊदी अरब और सिंगापुर का स्थान है।
- ➔ खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देश (38%) उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (> 50%) से पीछे हैं।
- ➔ रेमिटेंस प्राप्त करने वाले भारत के शीर्ष 3 राज्य (2023-24): महाराष्ट्र (20.5%) पहले स्थान पर है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है।

रेमिटेंस प्राप्ति के ट्रेंड में बदलाव की वजहें

- ➔ **रेमिटेंस भेजने की लागत:** डिजिटलीकरण के कारण भारत में रेमिटेंस भेजने की लागत वैश्विक औसत से कम हो गई है।
- ➔ **संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में मजबूत श्रम बाजार:** विशेषकर व्हाइट कॉलर जॉब्स की बढ़ती संख्या।
 - खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) के देशों में ऑटोमेशन, आर्थिक विविधीकरण और राष्ट्रीयकरण नीतियों (जैसे- सऊदी अरब की निताकत और कफाला श्रम नीतियाँ) के कारण अल्प-कुशल श्रमिकों के लिए अवसरों में गिरावट दर्ज की गयी है।
- ➔ **कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का उच्चतर शिक्षा के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहे हैं।** भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 'माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप' (मई 2021) जैसी नीतियों ने भी इस नए ट्रेंड में योगदान दिया है।
 - उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में प्रवास करने वाले भारतीयों की संख्या 2020 की 76,000 से तीन गुना बढ़कर 2023 में 2,50,000 हो गई।

अर्थव्यवस्था के लिए धन-प्रेषण का महत्व

- ➔ **भुगतान संतुलन (BoP):** उदाहरण के लिए, यह भारत के वस्तु व्यापार घाटे का लगभग 50% का वित्त-पोषण करता है।
- ➔ **घरेलू स्तर:** जीवन स्तर में सुधार। उदाहरण के लिए, 2021 में केरल के राज्य घरेलू उत्पाद में 36% का योगदान दिया।
- ➔ **समृद्धि-आर्थिक भूमिका:** उदाहरण के लिए, 2000 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3-3.5% का योगदान देता है।
- ➔ **ऋण स्थिरता:** ऋण लेने के जोखिम और लागत, दोनों को कम करता है।

3.7. यूनिफाइड पेंशन स्कीम {UNIFIED PENSION SCHEME (UPS)}

सुखियों में क्यों?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को शुरू करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का परिचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया गया।

विनियमों से संबंधित मुख्य तथ्य

- ➔ **UPS की प्रयोज्यता:** मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी, 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद शामिल होने वाले नए कर्मचारी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आदि।
- ➔ **लाभों के लिए पात्रता:** अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले कर्मचारी (10 वर्ष की अर्हता सेवा के बाद), केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी आदि।
- ➔ **अंशदान:** व्यक्तिगत कोष (मूल वेतन का 10%); पूल कोष (केंद्र सरकार मूल वेतन का ~8.5% योगदान करती है)।
- ➔ **निधि-आधारित प्रणाली:** अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित भुगतान के लिए नियमित योगदान और निवेश पर निर्भर करती है।
- ➔ **स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN):** केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) प्रणाली के जरिए सभी लेन-देन रिकॉर्ड करने वाली विशिष्ट संख्या।
- ➔ **भुगतान:**
 - **सुनिश्चित भुगतान:** अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% (न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा)।
 - **न्यूनतम गारंटीड भुगतान:** 10 वर्ष की सेवा-अवधि के साथ 10,000/ माह।
 - **आनुपातिक भुगतान:** 10-25 वर्ष की सेवा के लिए।
 - **स्वीकार्य भुगतान:** यदि व्यक्तिगत कोष बेंचमार्क से कम है या निकासी कोष के 60% से अधिक है तो कम किया जाएगा।

सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्रता मानदंड

- ➔ कर्मचारियों को **न्यूनतम 10 वर्ष की अनिवार्य सेवा** पूरी करनी होगी। पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू होता है।
- ➔ **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति:** ऐसे कर्मचारी जो न्यूनतम 25 वर्षों की अनिवार्य सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, तो उनकी मूल सेवानिवृत्ति आयु (यानी, वह आयु जिस पर वे कार्य करना जारी रखते तो सेवानिवृत्त होते) से पेंशन प्राप्त होगी।
- ➔ **पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन):** विधिवत वैवाहिक जीवनसाथी (पति/पत्नी) को जीवन भर के लिए कर्मचारी को देय पेंशन का 60% पेंशन।
- ➔ **महंगाई भत्ता (DR):** देय पेंशन राशि और पारिवारिक पेंशन, दोनों पर लागू।
- ➔ **UPS को लागू करने वाले मध्यवर्ती और संस्थाएं:** नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की संरचना (नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पेंशन फंड, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी, ट्रस्टी बैंक, प्रतिभूतियों के संरक्षक आदि)

UPS से संबंधित चुनौतियां

- ➔ राजकोष पर बोझ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारियों के भुगतान में विलंब, सीमित पारिवारिक पेंशन, राजनीतिक विरोध।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के बारे में

- **स्थापना:** 2003 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा अस्तित्व में आया।
- **PFRDA अधिनियम, 2013** के तहत इसे **वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया।**
- **उद्देश्य:** वृद्धावस्था में आय सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि पेंशन फंड के अंशधारकों के हितों की सुरक्षा की जा सके और संबंधित विषयों का समुचित प्रबंधन किया जा सके।
- **केंद्रीय वित्त मंत्रालय** के तहत कार्य करती है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **संरचना:** अध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य। इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अर्थशास्त्र, वित्त या कानून के क्षेत्र (प्रत्येक क्षेत्र से कम से कम एक सदस्य) में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों में से की जाती है।
- **कार्य:** मध्यवर्तीयों को पंजीकृत करना और विनियमित करना तथा सब्सक्राइबर्स को समयबद्ध सेवा प्रदान करना; मध्यवर्तीयों के बीच के विवाद तथा मध्यवर्ती और सब्सक्राइबर्स के बीच के विवादों का निपटारा करना।
- यह संस्था **अटल पेंशन योजना (APY), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), NPS-वात्सल्य की क्रियान्वयन एजेंसी भी है।**

3.8. इक्विलाइजेशन लेवी (EQUALISATION LEVY)

मुख्तियों में क्यो?

वित्त अधिनियम, 2016 में प्रस्तावित नए संशोधनों के अनुसार, **ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्विलाइजेशन लेवी या डिजिटल कर 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद लागू नहीं होगा।**

इक्विलाइजेशन लेवी के बारे में

- यह **वित्त अधिनियम, 2016** द्वारा शुरू किया गया एक **प्रत्यक्ष कर** है। इसमें विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को **विज्ञापन** से होने वाली डिजिटल आय पर लगाए जाने वाला टैक्स शामिल है।
- **वित्त अधिनियम, 2020** के तहत इस लेवी के दायरे में ई-कॉमर्स **आपूर्ति और सेवाओं** को भी लाया गया है।

इक्विलाइजेशन लेवी के अधीन लेन-देन

- ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं (6%): डिजिटल विज्ञापनों और संबंधित सेवाओं के लिए गैर-निवासियों को किए गए भुगतान पर।
- ई-कॉमर्स द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति (2%): गैर-निवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा प्राप्त राजस्व पर लगाया जाता है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
 - ➔ शर्त: शुल्क आयकर अधिनियम का हिस्सा नहीं है; वैश्विक फर्म अपने देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौतों के तहत कर क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती हैं।

इक्विलाइजेशन लेवी लगाने के कारण

- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा:** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच।
- **कर अंतराल को कम करना:** भारत में विदेशी कंपनियों की शाखाएं नहीं होने के बहाने कर से बचने के प्रयास को रोकना।
- **विदेशी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाना:** यह सुनिश्चित करना कि बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में अर्जित राजस्व पर कर का भुगतान करें।
- **राजस्व के स्रोत बढ़ाने का अवसर:** कोविड-19 के कारण डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का लाभ उठाना।

संबंधित चिंताएं

- अमेरिका के साथ व्यापार विवाद; प्रतिशोधवादी टैक्स लगाने का जोखिम; दोहरा कराधान और अधिक नियमों के अनुपालन का बोझ।

3.9. किसान उत्पादक संगठन (FARMER PRODUCER ORGANISATIONS: FPOs)

मुख्तियों में क्यो?

केंद्र सरकार ने **"10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन"** योजना के तहत **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन** का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

योजना के बारे में

- इस केंद्रीय क्षेत्रक की योजना को **2020 में शुरू किया** गया था। इसके लिए 2027-28 तक **6,865 करोड़ रुपये** के बजट आवंटित किया गया है।
- **उद्देश्य:** 10,000 नए FPOs के गठन के लिए एक अनुकूल व्यवस्था प्रदान करना, ताकि आय अर्जक, स्थायी और संधारणीय कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां (IAs):** इनमें लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC), नाबार्ड, नेफेड जैसी **कुल 9 एजेंसियां** शामिल हैं।

- ➔ **विशेष ध्यान:** लघु, सीमांत किसान, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग सुविधाएं और निर्यात सुनिश्चित किया जा सके।
- ➔ **मुख्य प्रावधान:**
 - ➔ **प्रोडक्ट क्लस्टर एरिया एप्रोच** एवं विशेष कमोडिटी-आधारित एप्रोच के आधार पर FPOs का गठन।
 - ➔ **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक FPO को 3 वर्षों के लिए प्रबंधन लागत हेतु 18 लाख रुपये प्रदान करना।
 - ➔ **इक्विटी अनुदान:** प्रत्येक किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति FPO 15 लाख रुपये है।
 - ➔ **क्रेडिट गारंटी:** प्रति FPO **2 करोड़ रुपये** तक के प्रोजेक्ट लोन की गारंटी।
- ➔ **उपलब्धि:** 4,761 FPOs को **254.4 करोड़ रुपये** का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है और **1,900 FPOs** को 453 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया है।
 - ➔ देश में लगभग **30 लाख किसान** FPOs से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग **40% महिलाएं** हैं।

FPOs के बारे में

- ➔ **परिभाषा:** FPOs का गठन कृषि उत्पादकों (किसानों, दूध उत्पादकों आदि) के समूह द्वारा शेयरधारकों के रूप में किया जाता है।
- ➔ **उद्देश्य:** जीवन स्तर, आय और लाभप्रदता प्रदान करना।
- ➔ **पंजीकरण:** कंपनी अधिनियम, 2013 या सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत एक विशिष्ट पंजीकृत पहचान संख्या (RIC) द्वारा FPO रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है।
- ➔ **सहायता:** कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय) के तहत **लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)** FPO के गठन में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

FPOs का लाभ	
आर्थिक उत्पादन को दक्ष बनाना	उत्पादन और थोक परिवहन में समन्वय के माध्यम से प्रति इकाई लागत को कम करना।
मूल्य संवर्धन को बढ़ाना	कृषि उत्पादों के प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलने से मूल्य-वर्धन में वृद्धि होती है।
किसानों की सौदेबाजी शक्ति बढ़ना	किसानों की सौदेबाजी की क्षमता मजबूत होती है, जिससे वे उत्पादन और प्रसंस्करण में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
मार्केट इंटेलिजेंस	ये संगठन उत्पाद मूल्यों और उत्पादन की मात्रा के बारे आसानी से सूचनाएं उपलब्ध कराकर बाजार स्थितियों के बारे जानकारी प्रदान करते हैं।
कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी	ये उत्पादों के संयुक्त भंडारण और संयुक्त वैल्यू-एडिशन केंद्रों की व्यवस्था करके फसल कटाई के बाद की हानि को कम करने में सहायक होते हैं।

FPOs के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- ➔ **पेशेवर प्रबंधन कौशल का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में FPOs व्यवसाय को पेशेवर रूप से प्रबंधित करने के लिए योग्य CEO की कमी।
- ➔ **फसल कटाई के बाद का नुकसान:** आधुनिक कृषि तकनीकों, भंडारण सुविधाओं एवं परिवहन संबंधी अवसंरचना तक सीमित पहुंच प्रदान करना।
- ➔ **निवेश और ऋण प्राप्ति में चुनौती:** प्रोसेसिंग, भंडारण और कोलेटरल फ्री लोन प्राप्त करने में कठिनाई।
- ➔ **गुणवत्ता संबंधी मानक और प्रमाणन:** छोटे FPOs के लिए जटिल और महंगी प्रक्रिया।
- ➔ **जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता:** जलवायु-अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी।
- ➔ **बाजार में अस्थिरता:** एक ही फसल पर ध्यान केंद्रित करने से फसल के नष्ट होने या बाजार के उतार-चढ़ाव से निपटने में समस्याएं पैदा होना।

आगे की राह

- ➔ **उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी को अपनाना:** प्रिसिजन फार्मिंग, IoT और कृषि प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसी तकनीक को अपनाना।
- ➔ **क्षमता निर्माण:** FPO सदस्यों को आधुनिक, संधारणीय खेती और संसाधन प्रबंधन करने पर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।
- ➔ **स्कोरिंग मॉडल:** संसाधन आवंटन में वित्तीय संस्थानों की मदद करने के लिए FPOs के लिए एक मानकीकृत स्कोरिंग मॉडल विकसित करना।

3.10. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (INDIA'S BIO-ECONOMY)

मुख्तियारों में क्यों?

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) ने अपनी **13वीं वर्षगांठ** पर **“इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2025” (IBER 2025)** जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- ➔ बायोटेक स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **“बायोसार्थी मेंटरशिप इनिशिएटिव”** नामक वैश्विक मेंटरशिप पहल की भी शुरुआत की गई।
- ➔ जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2012 में BIRAC की स्थापना की, जो **सार्वजनिक क्षेत्र का एक गैर-लाभकारी उद्यम** है।
- ➔ फंडिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा प्रबंधन के माध्यम से उद्योग- अकादमिक जगत के बीच समन्वय का कार्य करता है।
- ➔ **प्रमुख पहलें:** बायो-नेस्ट स्कीम, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (BIG), सीड फंड, आदि।

बायो-इकोनॉमी क्या है?

- ➔ इसमें आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को वितरित करने के लिए जैविक संसाधनों का संधारणीय उत्पादन, उपयोग और संरक्षण शामिल है।
- ➔ भारत ने 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था को 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।

जैव अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक	प्रमुख क्षेत्रक	उदाहरण
बायोफार्मा और बायोमेडिकल	कैंसर इम्यूनोथेरेपी, जीन एडिटिंग, प्रेसिजन मेडिसिन	CAR-T सेल थेरेपी, CRISPR-Cas9 तकनीक
बायोएग्री	जेनेटिकली मोडिफाइड फसलें, प्रिंसिजन एग्रीकल्चर, बायो-आधारित उत्पाद	बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंगेन्सिस, ट्राइकोडर्मा
बायोइंडस्ट्रियल	जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक, बायोगैस	इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, कंप्रेस्ड बायोगैस (SATAT योजना)
बायोरिसर्च और बायो IT (बायो सर्विसेज)	क्लिनिकल परीक्षण, बायोटेक सॉफ्टवेयर	बायोकॉन, इंफोसिस लाइफ साइंसेज

भारत के लिए जैव-अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- ➔ **आर्थिक विकास:** जैव-अर्थव्यवस्था का आकार 2014 में 10 बिलियन डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर 165.7 बिलियन डॉलर हो गया। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% है।
- ➔ **उद्यमिता:** एक दशक में बायोटेक स्टार्टअप 50 से बढ़कर 10,000 से अधिक हो गए (IBER 2025)।
- ➔ **ग्लोबल फार्मा हब:** भारत वैश्विक स्तर पर दवाइयों के उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। इसके अलावा, दुनिया की 65% वैक्सीन का उत्पादन करता है।
- ➔ **खाद्य सुरक्षा:** GM फसलों, प्रिंसिजन फार्मिंग, आदि के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार।
- ➔ **रोजगार:** 35 मिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न होने का अनुमान है।
- ➔ **ऊर्जा-सुरक्षा:** उदाहरण के लिए, 2024 में 15% इथेनॉल मिश्रण (2025 तक 20% का लक्ष्य), **कच्चे तेल के आयात और CO2 उत्सर्जन दोनों को कम** करता है।
- ➔ **पर्यावरणीय लाभ:** उदाहरण के लिए, यह **सर्कुलर इकोनॉमी** (कृषि अवशेषों से इथेनॉल) को बढ़ावा देता है और जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और **बायो-रेमेडिएशन** (जैसे, TERI/ टेरी का आयलजैपर) के माध्यम से **प्रदूषण नियंत्रण** करता है।

जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली नीतियां और योजनाएं

- ➔ **BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति 2024:** बायो-मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी, बायो-फाउंड्री क्लस्टर एवं बायो-ए.आई. हब जैसी प्रमुख पहलों समर्थन करती है।
- ➔ **राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग और BIRAC के नेतृत्व में यह वैक्सीन, बायोसिमिलर, चिकित्सा उपकरणों में भारत की क्षमताओं को बढ़ावा देता है।
- ➔ **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (Bio- RIDE) योजना 2024:** जैव-उद्यमिता और उद्योग -अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देती है।
- ➔ **जीनोम इंडिया परियोजना:** भारत की आनुवंशिक विविधता की व्यापक सूची तैयार करने के लिए 2020 में शुरू की गई।
- ➔ **बायोटेक-किसान (बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क):** यह वैज्ञानिक- कृषि नवाचारों के माध्यम से किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है।
- ➔ **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018:** ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रक में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देती है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के विकास में बाधाएं

- ➔ **ओवरलैपिंग विनियमन** (उदाहरण के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यों में टकराव)।
- ➔ **बायो-पाइरेसी की चिंता:** उदाहरण के लिए, अमेरिका में हल्दी पेटेंट मुद्दा।
- ➔ **अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25):** सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.64% है (चीन में लगभग 2%, अमेरिका में लगभग 3%)।
- ➔ **अन्य चुनौतियां:** जीएम फसलों के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं, अपर्याप्त वित्तपोषण, आदि।

आगे की राह

- ➔ **सुधार विनियमन:** राष्ट्रीय जैव अर्थव्यवस्था मिशन और सिंगल-विंडो रेगुलेटरी मैकेनिज्म की स्थापना करनी चाहिए।
- ➔ **संधियों का लाभ उठाना:** उदाहरण के लिए, IP मुद्दों का समाधान करने के लिए **बौद्धिक संपदा पर WIPO की संधि** का उपयोग करना।
- ➔ **निवेश को बढ़ावा देना:** कर प्रोत्साहन, आउटकम-आधारित वित्तपोषण आदि प्रदान करना।
- ➔ **प्रतिभा का विकास:** उत्कृष्टता केंद्र और विशेष पाठ्यक्रम शुरू करना।
- ➔ **बुनियादी ढांचा:** राष्ट्रीय जैविक डेटा भंडार और ग्लोबल कोएलिशन नेटवर्क स्थापित करना।
- ➔ **सेफ्टी सुनिश्चित करना:** प्रोडक्ट डिज़ाइन में ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के सिद्धांत को अपनाना (301वीं संसदीय रिपोर्ट)।

3.11. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NATIONAL TECHNICAL TEXTILES MISSION: NTTM)

मुख्तियों में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन** के शुरुआत के 5 वर्ष पूरे हुए।

तकनीकी वस्त्र सामान्य कपड़ों से अलग होते हैं। इन्हें सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि विशेष खूबियों और बेहतर काम करने की क्षमता के लिए बनाया जाता है। जैसे कि, डॉक्टरों उपकरण, **सुरक्षा गियर और निर्माण सामग्री**।

➔ **तकनीकी वस्त्र** बाजार को उनके उपयोग के आधार पर **12 सेगमेंट्स** में बांटा गया है। (बॉक्स देखिए)

'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' (NTTM) के बारे में

- ➔ **उद्देश्य:** 2025-26 तक 1,480 करोड़ रुपये के बजट के साथ भारत को तकनीकी वस्त्रों के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनाना है।
- ➔ **मंत्रालय:** केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय
- ➔ **चार घटक:**
 - ➔ अनुसंधान, नवाचार और विकास; प्रचार-प्रसार और बाजार का विकास; नियति संवर्धन; तथा ज्ञानवर्धन, प्रशिक्षण और कौशल विकास।
- ➔ **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के उद्देश्य:** तकनीकी वस्त्रों में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए एक बेहतर परिवेश का निर्माण करना।

भारत के लिए तकनीकी वस्त्र क्यों महत्वपूर्ण है?

➔ **अलग-अलग क्षेत्रों में उपयोग:** होमटेक जैसे नवाचार (एंटीवायरल मैट्रेस सुरक्षा)।

➔ **मांग में वृद्धि:** बढ़ती जनसंख्या और वृद्ध नागरिकों की बढ़ती संख्या के कारण उपभोक्ता सक्रिय वस्त्र, चिकित्सा परिधान और स्वच्छ चिकित्सा उपकरण (मेडिटेक) के लिए टिकाऊ, मजबूत तकनीकी वस्त्रों को प्राथमिकता देते हैं।

➔ **औद्योगिक उत्पादन:** इंडटेक, सूचालक कपड़े और 3 डी बनावट वाले वस्त्र जैसे उत्पादों के साथ विनिर्माण का समर्थन करता है।

➔ **पर्यावरण संरक्षण:** जियोटेक और ओकोटेक फ्लोर सीलिंग, एयर क्लीनिंग, जल प्रदूषण की रोकथाम और अपरदन से सुरक्षा में सहायक।

➔ **आपदा प्रबंधन में सहायक:** ऑस्ट्रिया में, हिमस्खलन को रोकने के लिए जियोटेक अवरोधों का उपयोग किया जाता है।

➔ **रक्षा आधुनिकीकरण:** मेक इन इंडिया के तहत प्रोटेक आधारित बुलेट प्रूफ जैकेट और कंपोजिट।

➔ **प्रमुख क्षेत्रों में मददगार:** कृषि, स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, परिवहन और अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, जियोटेक्सटाइल रेलवे ट्रैक का निर्माण (राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन) और जियोमेम्ब्रेन (जल जीवन मिशन)।

तकनीकी वस्त्र के 12 सेगमेंट्स

इंडटेक	औद्योगिक ब्रश, कंप्यूटर प्रिंटर रिबन, आदि।
मोबिटेक	सीट कवर, असबाब, टायर कॉर्ड कपड़े, आदि।
स्पोर्टेक	खेल जाल, पैराशूट, कृत्रिम घास और टर्फ, आदि।
बिल्डटेक	फर्श और दीवार कवरेज, म्यान जाल, शामियाना और छतरियां, आदि।
होमटेक	तकिए, गद्दे, ब्लाइंड, आदि।
मेडिटेक	कॉन्टेक्ट लेंस, बेबी डायपर, आदि।
क्लॉथटेक	इंटरलाइनिंग, लेबल, आदि।
एग्रोटेक	पक्षी सुरक्षा जाल, फसल कवर, आदि।
प्रोटेक	बुलेट-प्रूफ सुरक्षात्मक कपड़े, उच्च दृश्यता वाले कपड़े, आदि।
पैकटेक	टैपिंग फैब्रिक, मुलायम सामान, आदि।
ओकोटेक	अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, पुनर्चक्रण।
जियोटेक	जियो-कंपोजिट, जियो-बैग, जियोग्रिड, जियोनेट।

तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम:

- ➔ **PLI योजना:** घरेलू तकनीकी वस्त्र, मानव निर्मित कपड़े और परिधान उत्पादन को बढ़ावा।
- ➔ **पी.एम. मित्र योजना:** मैन-मेड फैब्रिक (MMF) और तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
- ➔ **समर्थ योजना:** संगठित वस्त्र क्षेत्र और इससे संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए मांग-आधारित कौशल प्रदान करती है।
- ➔ **नए HSN कोड:** 2019 में पहचाने गए 207 वस्तुओं के अतिरिक्त 30 से अधिक नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड जोड़े गए।
- ➔ **अनिवार्य उपयोग:** दस केंद्रीय मंत्रालयों में अनिवार्य उपयोग के लिए 119 तकनीकी वस्त्र उत्पादों की पहचान की गई है।

तकनीकी वस्त्रों का लाभ उठाने में मौजूद चुनौतियां

- ➔ **जागरूकता की कमी:** जानकारी की कमी के कारण इसके लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं।
- ➔ **आयात पर अधिक निर्भरता:** चीन (कम लागत वाले उत्पाद) और अमेरिका/यूरोप (हार्ड-टेक उत्पाद) पर।
- ➔ **कुशल कार्यबल की कमी:** प्रशिक्षण योजनाओं में पारंपरिक वस्त्रों पर ही ध्यान दिया जाता है।
- ➔ **अनुसंधान एवं विकास की कमी:** सीमित विविधीकरण वाला वस्तु-केंद्रित उद्योग।
- ➔ **मानकीकरण से जुड़े मुद्दे:** असंगत HSN कोड और अंतर्राष्ट्रीय मानक व्यापार और गुणवत्ता नियंत्रण को जटिल बनाते हैं।

आगे की राह

- ➔ **अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना:** प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से।
- ➔ **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना:** बाजारों में मांग बढ़ाने के लिए भारतीय मानकों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाना।
- ➔ **सततता पर ध्यान देना:** प्राकृतिक फाइबर तथा एगोटेक नेट जैसे पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- ➔ **विश्व के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों से सीखना:** उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका (स्पोर्टेक), जर्मनी (जियोटेक), आदि की उन्नत तकनीकें।

3.12. राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 {NATIONAL WATERWAYS (CONSTRUCTION OF JETTIES/TERMINALS) REGULATIONS, 2025}

मुख्तियों में क्यों?

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 जारी किए।

विनियम के बारे में

- ➔ **विनियमों का निर्माण:** केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा।
- ➔ **उद्देश्य:** निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करना और भारत के जलमार्ग नेटवर्क के प्रभावी तरीके से उपयोग को बढ़ावा देना।

विनियम के मुख्य प्रावधान

- ➔ **किन पर लागू होगा:** कोई भी इकाई, जिसमें निजी क्षेत्र की इकाई भी शामिल है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग को संचालित करना चाहती है।
- ➔ **अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NoC) की आवश्यकता:** टर्मिनल का निर्माण या उसे संचालित करने के लिए IWAI से प्राप्त करना।
- ➔ **डिजिटल पोर्टल:** दक्षता, पारदर्शी टर्मिनल के अनुप्रयोगों के लिए।
- ➔ **जिम्मेदारियां:** टर्मिनल डेवलपर्स और ऑपरेटर्स तकनीकी डिजाइन और निर्माण का कार्यभार संभालते हैं।

अंतर्देशीय जल परिवहन

- ➔ **परिभाषा:** अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) का तात्पर्य नदियों, नहरों, झीलों और अन्य नौगम्य जलाशयों के माध्यम से यात्रियों और माल के आवागमन से है।
- ➔ **लाभ:** ईंधन का बेहतर उपयोग, विकसित करने में किफायती, परिवहन और रखरखाव, यातायात पर भीड़ को कम करना, पर्यावरण अनुकूल।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की स्थिति

- ➔ **नौगम्य जलमार्ग:** भारत में लगभग **14,500 किलोमीटर** नौगम्य जलमार्ग (नदियां, नहरें, आदि) तथा IWT द्वारा सालाना लगभग **133.03 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कागों** का परिवहन किया जा रहा है।
- ➔ **अन्य देशों से तुलना:** भारत में केवल 3.5% व्यापार जलमार्गों से होता है, जबकि चीन में 47%, यूरोप में 40% और बांग्लादेश में 35% व्यापार जलमार्गों से होता है।

उठाए गए कदम

- ➔ **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):** 1986 में स्थापित यह संगठन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है।
- ➔ **जलमार्ग विकास परियोजना (2014):** विश्व बैंक के समर्थन से IWAI द्वारा; **वाराणसी से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)-1** के 1,390 किलोमीटर खंड की नौगम्यता/ परिवहन क्षमता में सुधार के लिए लागू की जा रही है।
- ➔ **सागरमाला कार्यक्रम (2015):** सड़क/ रेल नेटवर्क पर निर्भरता कम करने के लिए तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- ➔ **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016:** 111 राष्ट्रीय जलमार्गों (5 मौजूदा और 106 नए जलमार्ग) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- ➔ **अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021:** इसे अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के स्थान पर लागू किया गया है जो पोत पंजीकरण, वर्गीकरण, प्रदूषण रोकथाम से संबंधित है।
- ➔ **जलवाहक योजना (2024):** जलमार्गों के जरिए लागत प्रभावी, सुरक्षित और समय पर कागों की डिलीवरी को प्रोत्साहित करता है।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के लिए प्रमुख चुनौतियां

- ➔ **जलमार्गों की कम गहराई:** अधिकांश नदियाँ (लगभग 2 मीटर गहराई) भारी वाहनों के लिए कम-से-कम 3 मीटर की न्यूनतम गहराई की आवश्यकता होती है।
- ➔ **पर्यावरण पर प्रभाव:** जलमार्ग परिवहन के कारण नदी प्रदूषण बढ़ता है, जल के प्राकृतिक अपवाह में व्यवधान और पर्यावास के नष्ट होने का खतरा है।
- ➔ **IWT जहाजों की कमी:** उच्च पूंजी लागत और वित्तपोषण संबंधी कठिनाइयां पोत निर्माण को सीमित करती हैं।
- ➔ **मॉडल एकीकरण:** मल्टीमॉडल कॉरिडोर, जलमार्ग मानचित्रण और परिवहन केंद्रों की कमी है।

निष्कर्ष

अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता को अनलॉक करने के लिए अवसंरचना में सुधार करने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने आदि की आवश्यकता है। उचित नीतियां बनाने और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने से वस्तुओं का परिवहन बढ़ेगा जिससे जलमार्गों को संधारणीय परिवहन का एक प्रमुख आधार बनाया जा सकेगा।

3.13. भारत के विकास के लिए कोयला क्षेत्रक (COAL SECTOR FOR INDIA'S DEVELOPMENT)

सुखियों में क्यों?

भारत ने कोयला उत्पादन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में **20 मार्च, 2025** को **एक बिलियन टन उत्पादन आंकड़ा** को पार किया।

कोयला क्षेत्रक की सफलता में योगदान देने वाली सरकारी पहलें

- ➔ **कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (CMSP एक्ट):** निजी संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी की अनुमति दी गई है, जिसकी पहली नीलामी 2020 में शुरू की गई।
- ➔ **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (MMDR एक्ट):** कैप्टिव कोयला खान के मालिकों को खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने की अनुमति दी गई है।
- ➔ **कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति, 2024:** एक लागत प्रभावी और लचीला कोयला निकासी प्रणाली बनाने के लिए।
- ➔ **पारदर्शी नीलामी व्यवस्था: राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल और माइन क्लोजर पोर्टल** के जरिए दो चरणों वाली ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाती है।
- ➔ **कोयला गैसीकरण योजना (2024):** 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य।
- ➔ **मिशन कोकिंग कोल:** इस्पात क्षेत्र के लिए आपूर्ति को बढ़ावा देना
- ➔ **अन्य उपाय:** राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (NCI), सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति।

भारत के विकास में कोयले का महत्व

- ➔ **प्राथमिक ऊर्जा स्रोत:** उदाहरण के लिए, कोयला, भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 46.88% का योगदान देता है (नवंबर 2024 तक)।
- ➔ **आयात निर्भरता में कमी:** उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2024 में कोयला आयात में 8.4% की कमी आई है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।
- ➔ **बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना:** 2050 तक तीन गुना होने का अनुमान है (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, IEA)
- ➔ **क्षेत्रीय विकास:** कोयला क्षेत्र जीएसटी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड आदि के माध्यम से कोयला उत्पादक क्षेत्रों को सालाना ₹70,000 करोड़ से अधिक का योगदान देता है।
- ➔ **रोजगार सृजन:** देश के 350 से अधिक कोयला खानों में लगभग 5 लाख खनिकों को रोजगार देता है।
- ➔ **अन्य योगदान:** रेलवे के माल ढुलाई राजस्व का आधा हिस्सा (वित्त वर्ष 2022-23 में 49%), बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय और CSR योगदान।

भारत के कोयला क्षेत्र के बारे में अन्य प्रमुख तथ्य

- ➔ विश्व में **पांचवां सबसे अधिक कोयला भंडार** भारत में है। साथ ही, भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
- ➔ **कोयले का कुल अनुमानित भंडार:** 361.41 बिलियन टन (2022 तक)।
- ➔ **शीर्ष कोयला भंडार वाले राज्य:** ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ (भारत के भंडार का लगभग 69%)।
- ➔ **कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973:** कोयला खनन पात्रता निर्धारित करने वाला केंद्रीय कानून है। 2014 में शुरू की गई नीलामी ने निजी कैप्टिव खनन की अनुमति दी, 2020 में वाणिज्यिक खनन निजी कंपनियों के लिए खोला गया।
- ➔ **कोयले के प्रकार:** एन्थ्रेसाइट (उच्चतम ग्रेड), बिटुमिनस (बिजली उत्पादन के लिए कोयले का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है), सब-बिटुमिनस और लिग्नाइट (सबसे निम्न ग्रेड का कोयला, कार्बन की मात्रा सबसे कम)

भारत के कोयला क्षेत्र के लिए प्रमुख चुनौतियाँ

खनन और कोयला उत्पादन उद्योग में	➔ खनन तकनीकों में तकनीकी अप्रचलन ➔ कोयले की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में बेमौसमी और लंबे समय तक बारिश ➔ बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा कोयले के उचित मूल्य का भुगतान न करना और भारी बकाया राशि ➔ कोयला क्षेत्रों में अवसर श्रम/ औद्योगिक संबंध (IR) संबंधी मुद्दे ➔ भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे ➔ भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होना
कोयला चालित ताप विद्युत संयंत्रों से पर्यावरण संबंधी चिंताएँ	➔ हानिकारक गैसें: सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x), कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), पार्टिकुलेट मैटर (PM) ➔ प्रदूषक: प्लंब-पेंथ, लेड (Pb), आर्सेनिक (As), कैडमियम (Cd), पारा (Hg)

3.14. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NATIONAL PROGRAMME FOR DAIRY DEVELOPMENT: NPDD)

सुखियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए राशि आवंटन बढ़ाकर **संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)** को मंजूरी प्रदान की।

संशोधित NPDD के उद्देश्य

- देशभर में **10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन** करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूध की खरीद एवं दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमताओं को बढ़ाना।
- NPDD की चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त विशेष अनुदान सहायता के साथ **दो 'दुग्ध उत्पादक कंपनियों'** का गठन करना।
- रोजगार के 3.2 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित करना जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता देना। डेयरी क्षेत्र के कुल कार्यबल में **70% महिलाएं** हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के बारे में

- यह **केंद्रीय क्षेत्रक योजना 2014** में शुरू की गई। **2021 में योजना का पुनर्गठन**।
- कार्यान्वयन एजेंसी:** केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत **पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD)**।
- उद्देश्य:** दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और कोल्ड चेन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना; डेयरी किसानों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना करना; आदि।
- NPDD के निम्नलिखित दो मुख्य घटक हैं:**
 - घटक A:** डेयरी सहकारी समितियों को दुग्ध शीतलन प्लाट्स, दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं इत्यादि अवसंरचनाओं के विकास में सहायता करना। इन अवसंरचनाओं में और प्रमाणन प्रणाली शामिल हैं।
 - घटक B: सहकारिता के माध्यम से डेयरी:** यह **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA)** से सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 9 राज्यों में दुग्ध उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग अवसंरचना में सुधार करके डेयरी सहकारी समितियों का विकास।

भारत में डेयरी क्षेत्रक

- वैश्विक दूध उत्पादन का 24.76%** (विश्व में प्रथम स्थान)
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान:** 5%
- कृषि की दृष्टि से महत्त्व:** भारत में डेयरी सबसे बड़ी कृषि कमोडिटी है
- संवृद्धि दर: 5.62% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)**, जो कि दूध उत्पादन में **मजबूत वृद्धि है** (2014-24)
- रोजगार: 8+ करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है**, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं।
- दूध की उपलब्धता: 471 ग्राम प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन** (वैश्विक औसत 329 ग्राम प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन) से अधिक
- अग्रणी डेयरी उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु।

डेयरी क्षेत्रक में सहकारी समितियों की भूमिका

- सामूहिक सशक्तिकरण (सहकार से शक्ति):** लघु कृषकों के विकास के लिए **संस्था के रूप में समर्थन प्रदान करती है, उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाती है।**
- किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण (सहकार से समृद्धि):** हितधारकों के बीच अर्जित आय का **न्यायसंगत तरीके से वितरण सुनिश्चित करती है।** उदाहरण के लिए- **अमूल, नंदिनी।**
- सहकारी समितियों के बीच सहयोग (सहकार से सहयोग):** सहकारी समितियों के बीच तालमेल बैठाने में सहायता करती है। जैसे- सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक डायरी सहकारी समितियों (PDCS) के लेनदेन में मदद करती है।

डेयरी क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां:

- कम उत्पादकता:** पशु नस्ल ब्रीडिंग कार्यक्रम अधिक सफल नहीं रहा है, विस्तार सेवाएं (एक्सटेंशन सर्विसेज) सही से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, आधुनिक तकनीकों का कम उपयोग किया जाता है, पशुओं को उपयुक्त आहार और चारा नहीं मिल पाता है।
- अनौपचारिक और असंगठित होना:** भारत में लोग स्थानीय दुग्ध उत्पादकों से ही रोजाना दूध खरीद लेते हैं। इससे सहकारी समितियों के पैकेज्ड दूध की मांग कम हो जाती है।
- दुग्ध की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं:** उदाहरण के लिए दूध में पानी मिलाना, यूरिया का उपयोग आदि।
- पशु स्वास्थ्य:** पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या कम है, पशुओं को टीका लगाने के बारे में भी किसानों में जागरूकता की कमी; खुरपका और मुंहपका (Foot and Mouth Disease) जैसे पशु रोगों के प्रकोप।
- प्रशासन:** राज्य सरकारों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप करने के कारण इनकी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली भी प्रभावित होती है।
- प्रसंस्करण एवं भंडारण की कम क्षमता:** वैल्यू एडिशन (दूध से अलग-अलग उत्पाद बनाना), प्रोसेसिंग, भंडारण और मार्केटिंग जैसी अवसंरचनाओं की कमी है।

डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलें	
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	➤ मवेशियों की आबादी में आनुवंशिक सुधार तथा देशी नस्ल की मवेशियों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के माध्यम से दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।
डेयरी उद्योगिता विकास योजना (DEDS)	➤ नाबाई द्वारा लाभकारी परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान करके डेयरी उद्योग में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का कार्यक्रम।
पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)	➤ रोगनिरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से पशु स्वास्थ्य में सुधार करना।
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)	➤ यह डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन अवसंरचना स्थापित करने के लिए उद्यमियों, निजी कंपनियों से निवेश को प्रोत्साहित निधि है। डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF) को AHIDF में शामिल कर दिया गया है।
श्वेत क्रांति 2.0	➤ 2024 में सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू; इसके उद्देश्यों में डेयरी क्षेत्र में सततता और सर्कुलेरिटी और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना , प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य स्तरीय डेयरी संघ का गठन और देश के 80% जिलों में मिल्क यूनियन गठन करना शामिल है।

डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका

- **सामूहिक सशक्तीकरण (सहकार से शक्ति):** लघु कृषकों के विकास के लिए **संस्था के रूप में समर्थन प्रदान करती है, उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाती है।**
- **किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण (सहकार से समृद्धि):** हितधारकों के बीच अर्जित आय का **न्यायसंगत तरीके से वितरण सुनिश्चित करती है।** उदाहरण के लिए- **अमूल, नंदिनी।**
- **सहकारी समितियों के बीच सहयोग (सहकार से सहयोग):** सहकारी समितियों के बीच तालमेल बैठाने में सहायता करती है। जैसे- सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक डायरी सहकारी समितियों (PDCS) के लेनदेन में मदद करती है।

आगे की राह

- **अवसंरचनाओं का विकास:** दुग्ध उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण और अनुसंधान से संबंधित बुनियादी ढांचे का विस्तार: कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, दुग्ध गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ, आदि।
- **तकनीकों को अपनाना:** किसानों को वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के लिए सलाह, कम कीमत पर नई प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराना, आदि।
- **सहकारिता को बढ़ावा देना:** दूरदराज के क्षेत्रों में सामूहिकता की शक्ति का लाभ उठाना चाहिए और डेयरी कृषकों को सहकारिता के लाभों के बारे में बताना चाहिए।
- **प्रोसेसिंग और मार्केटिंग:** दूध की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना-अधिक मांग वाले **A2 घी, पनीर** जैसे दुग्ध उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन करना; निर्यात को बढ़ावा देना।

अन्य संबंधित सुर्खियाँ: संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

- **अधिक राशि का आवंटन:** अतिरिक्त **1,000 करोड़ रुपये** आवंटित। **2021-22 से 2025-26** के लिए कुल बजट आवंटन **3,400 करोड़ रुपये।**
- **नई पहलें:**
 - ➔ **बछिया (गाय बछिया) पालन केंद्र :** 15,000 बछियों के लिए 30 आश्रय सुविधाएं स्थापित करने में लगने वाले खर्च का 35% एकमुश्त सहायता।
 - ➔ **हाई जेनेटिक मेरिट (HGM) बछिया के लिए सहायता:** हाई जेनेटिक मेरिट-इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन बछिया खरीदने के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर **3% ब्याज छूट।**
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियाँ**
 - ➔ **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP):** इसका उद्देश्य **सीमन स्टेशन**ों और **कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क** में सुधार करना है।
 - ➔ **सैक्स सार्टेंड सीमन** का उपयोग करके **बुल प्रोडक्शन और नस्ल सुधार।**
 - ◊ कौशल विकास और किसान जागरूकता कार्यक्रम।

3.15. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

3.15.1. लोक लेखा समिति ने GST फ्रेमवर्क की समीक्षा की मांग की {PAC CALLS FOR REVIEW OF GST}

संसदीय लोक लेखा समिति ने GST फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा की मांग की।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- जुलाई 2017 में शुरू किया गया (101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016)
- व्यापक गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर
 - ➔ आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है।
 - ➔ कैस्केडिंग कर प्रभाव (कर पर कर) को समाप्त करता है।

GST में सम्मिलित केंद्रीय कर

- सेवा कर
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के सामान)
- औषधीय और शौचालय तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1995 के तहत उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD)
- विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (SAD)
- अधिभार और उपकर

GST में सम्मिलित राज्य कर

- केंद्रीय बिक्री कर
- क्रय कर
- मनोरंजन और मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों को छोड़कर)
- विलासिता कर
- चुंगी और प्रवेश कर (सभी प्रकार)
- लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर
- विज्ञापनों पर कर
- राज्य उपकर और अधिभार

GST फ्रेमवर्क को रेखांकित करने वाले मुद्दे

- **MSMEs की समस्याएं:** इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर की जटिलता और प्रशासनिक बोझ के कारण मौजूदा प्रावधानों का पालन करने में कठिनाई।
- **निर्यातकों की समस्याएं:** इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड में देरी, नकदी प्रवाह की समस्या का सामना करना।
- **स्टील रोलिंग मिलों की समस्याएं:** स्कैप डीलरों द्वारा GST का भुगतान न करने के कारण दोहरा कर, ITC के क्लेम में बाधा।
- **ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रक द्वारा कर चोरी:** अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स के कारण कर चोरी निरंतर जारी है।
 - ➔ 1 अक्टूबर, 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग पर **28% GST** लगाया जा रहा है।
 - ➔ IGST अधिनियम के तहत **सरलीकृत पंजीकरण योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य** किया गया है।
 - ➔ **GST असूचना महानिदेशालय (DGGI)** को अधिकार दिया गया है कि वह मध्यवर्तियों को IGST अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है।

आगे की राह

- MSMEs के लिए डिजाइन किया गया **सरलीकृत GST अनुपालन फ्रेमवर्क**।
- ITC दावों का शीघ्र निपटारा करने में निर्यातकों के लिए **समर्पित फास्ट-ट्रैक रिफंड प्रोसेसिंग सिस्टम** बनाया जाना चाहिए।

- अलग-अलग **गेमिंग प्लेटफॉर्म** द्वारा अपनाए गए **रेवेन्यू स्ट्रीमिंग मॉडल्स को समझने के लिए व्यापक** दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए।

3.15.2. सीएसआर, आईबीसी और ईएसजी को प्रभावी बनाना (MAKING CSR, IBC & ESG EFFECTIVE)

केंद्रीय कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की 'अनुदान मांगों (2025-26)' पर 10वीं रिपोर्ट में विविध मुद्दों जैसे **कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)**, **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)** तथा **पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ESG) विनियमों को प्रभावी बनाना पर प्रकाश डाला गया है और कई सिफारिशों की गई हैं:-**

क्षेत्र	समस्याएं	सिफारिशें
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)	➤ CSR फ्रेमवर्क को लागू करने और निगरानी में खामियां मौजूद हैं। ➤ CSR के तहत व्यय की प्रभावशीलता पर विस्तृत विश्लेषण का अभाव है। ➤ बिना खर्च हुई CSR राशि का लेखा-जोखा अभी भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है।	➤ अधिक व्यापक रिपोर्टिंग और निगरानी फ्रेमवर्क स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, CSR संबंधी परियोजनाओं के प्रभाव की नियमित रिपोर्ट प्रकाशित करना। ➤ अनुपालन न करने की स्थिति में समय पर दंड आरोपित किए जाने चाहिए।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)	➤ हितों का टकराव और प्रावधानों की असमान व्याख्या के कारण समाधान प्रक्रिया में देरी होती है। ➤ IBC के तहत समाधान पेशेवरों (RPs) के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए कोई मजबूत फ्रेमवर्क नहीं है।	➤ समाधान संबंधी योजनाओं को केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लागू करने हेतु प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। ➤ RPs के लिए कठोर प्रमाणन मानक और प्रदर्शन के मामले में स्वतंत्र समीक्षा लागू की जानी चाहिए। ➤ परिचालनरत लेनदारों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए कर्जदाताओं की समिति (CoC) की संरचना की समीक्षा करनी चाहिए।

पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ESG)	- ग्रीनवॉशिंग का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। - लघु व्यवसायों को ESG प्रणाली को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	- अनुपालन सुनिश्चित करने और ग्रीनवॉशिंग के लिए दंड आरोपित करने हेतु मंत्रालय के तहत एक समर्पित ESG पर्यवेक्षण निकाय गठित करना चाहिए। - निदेशकों के लिए प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में ESG उद्देश्यों को शामिल करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन किया जाना चाहिए। - लेखापरीक्षा समितियों के समान स्वतंत्र ESG समितियां गठित की जानी चाहिए।
---	---	---

3.15.3. कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने मात्स्यिकी क्षेत्रक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE SUBMITS REPORT ON FISHERIES SECTOR)

इस रिपोर्ट में मात्स्यिकी क्षेत्रक में सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राजस्व सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में की गई सिफारिशों पर सरकार की कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया गया है।

- भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है (वैश्विक उत्पादन का 8%), जिसकी कृषि GVA में हिस्सेदारी लगभग 6.72% है।

प्रमुख विशेषताएं

उजागर किए गए मुद्दे	सिफारिशें
समर्पित अनुसंधान निकाय का अभाव: उदाहरण के लिए, क्षेत्र-विशिष्ट फोकस का अभाव।	भारतीय मत्स्य एवं जलीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICFAR) की स्थापना करना।
छोटी मछलियों के दोहन पर नियंत्रण की कमी: बल ट्रोल्सिंग जैसी हानिकारक गतिविधियां मछली भंडार को समाप्त कर देती हैं।	न्यूनतम कानूनी जाल आकार (MLS) विनियमों को समान रूप से लागू करना और विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीकों पर प्रतिबंध लगाना।
मछुआरों के लिए ब्याज मुक्त ऋण का अभाव: केवल कुछ राज्य ही अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान करते हैं।	देश भर में ब्याज मुक्त KCC ऋण का विस्तार करना।
कटाई के बाद नुकसान और बुनियादी ढांचा: खराब भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण 20-25% तक नुकसान होता है।	PMMSY के अंतर्गत शीत भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन को मजबूत करना।
झींगा बूडस्टॉक में आत्मनिर्भरता का अभाव: आयातित एल. वन्नामेई झींगा बूडस्टॉक पर भारी निर्भरता।	ICAR के माध्यम से घरेलू बूडस्टॉक विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाना।
बांध के गेट खुलने और भारी वर्षा के कारण मछलियां बह गईं।	PMFBY की तरह बांध मछुआरों के लिए बीमा लागू करना।

सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी (SPS) बाधाएं तथा उचित प्रमाणीकरण एवं पता लगाने की क्षमता का अभाव नियति में बाधा डालता है।	नियति प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि: SPS अनुपालन, प्रमाणन आदि में सुधार।
--	---

3.15.4. सहकारी चीनी मिलों के लिए योजना (SCHEME FOR COOPERATIVE SUGAR MILLS)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने संशोधित 'इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना' के तहत सहकारी चीनी मिलों के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है।

योजना के बारे में

- कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- उद्देश्य:** मक्का और खाद्य के लिए अनुपयोगी हो चुके खाद्यान्न (DFG) का उपयोग करके गन्ना-आधारित मौजूदा इथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में बदलना।
- सरकार 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज छूट देगी या बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा तय ब्याज दर का 50% वहन करेगी (जो भी कम हो)।

3.15.5. तंबाकू (TOBACCO)

पिछले चार वर्षों में भारत का तंबाकू निर्यात दोगुना हो गया।

तंबाकू

- भारत की स्थिति:** दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (चीन के बाद) तथा निर्यातक (ब्राजील के बाद) देश है।
- प्रमुख उत्पादक राज्य:** गुजरात (कुल खेती योग्य क्षेत्र का 45% और उत्पादन 30%), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार।
- अनुकूल परिस्थितियां:**
 - तापमान (20° से 27°C के बीच); वर्षा (कम-से-कम 500 मिलीमीटर); मृदा (रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी) सबसे उपयुक्त होती है।
 - आंध्र प्रदेश, जहां गहरी काली मृदा में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है।

3.15.6. विश्व बैंक ने 'एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की {'BECOMING A HIGH-INCOME ECONOMY IN A GENERATION' REPORT RELEASED BY WORLD BANK}

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश (HIC) बनने के लिए अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8% की दर से विकास करना होगा। भारत 2007-08 में निम्न-मध्यम आय वाला देश (LMIC) बन गया था। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में 2032 तक उच्च-मध्यम आय वाला देश (UMIC) बनने की राह पर है।

2047 तक HIC समूह में शामिल होने में प्रमुख चुनौतियां

- मंद संरचनात्मक परिवर्तन:** भारत में कार्यबल का 45% हिस्सा (2023-24) कृषि क्षेत्रक में नियोजित है। इसके अलावा, निर्माण क्षेत्र में 30%, विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं में केवल 11% और 7% हिस्सेदारी है।
- निजी निवेश में गिरावट:** 2008 से निजी निवेश की GDP गिरावट देखी गई।

- ➔ **जनसांख्यिकीय लाभांश का कम उपयोग:** कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में 37.4% की वृद्धि (2000-19) हुई थी, लेकिन रोजगार में केवल 15.7%, श्रम बल भागीदारी दर 58% से घटकर 49% हो गई।

पिछले दो दशकों में भारत की आर्थिक संवृद्धि

अर्थव्यवस्था के आकार में 4 गुना वृद्धि	प्रति व्यक्ति GDP में 3 गुना वृद्धि	वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी में 2 गुना वृद्धि
नॉमिनल आधार पर विश्व की 5 ^{वीं} सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था	चरम निर्धनता में उल्लेखनीय कमी और अवसंरचना में सुधार	GDP में 6.7% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (कोविड महामारी से पहले)

वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी: 1.6% (2000) → 3.4% (2023)

2047 तक उच्च आय वाले देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) को वर्तमान स्तर से 8 गुना बढ़ाना होगा।

संवृद्धि हेतु मुख्य रणनीतियां

- ➔ **निवेश को बढ़ावा देना:** बेहतर वित्तीय विनियमों द्वारा, MSME क्षेत्र को ऋण उपलब्ध और सरलीकृत FDI नीतियों के माध्यम से 2035 तक निवेश को GDP के 33.5% से बढ़ाकर 40% करना।
- ➔ **रोजगार उत्पन्न करना:** एगो-प्रोसेसिंग, विनिर्माण, परिवहन और केयर इकॉनमी में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- ➔ **क्षेत्रीय संतुलन:** कम विकसित राज्य मूलभूत आवश्यकताओं (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अवसंरचनाओं के विकास) पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

3.15.7. UNCTAD ने 'ए वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2024' जारी की (UNCTAD RELEASED 'A WORLD OF DEBT REPORT 2024')

सार्वजनिक ऋण महत्वपूर्ण व्ययों को वित्त-पोषित करके विकास को गति दे सकता है, लेकिन अत्यधिक ऋण वृद्धि विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए चुनौतियां पैदा करता है।

- ➔ **व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) की 2024 की रिपोर्ट** में बढ़ते ऋण जोखिमों की चेतावनी दी गई है तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई का आग्रह किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- ➔ **वैश्विक ऋण वृद्धि:** 2023 में सार्वजनिक ऋण 97 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। (भारत में लगभग \$2.9 ट्रिलियन)
- ➔ **ऋण भुगतान पर अधिक व्यय:** 54 विकासशील देश अपने सामाजिक क्षेत्रों की तुलना में ब्याज भुगतान पर अधिक धन व्यय करते हैं।
- ➔ **असमान वित्तीय प्रणाली:** विकासशील देश 2 से 12 गुना अधिक दर पर ब्याज का भुगतान करते हैं।

बढ़ते वैश्विक सार्वजनिक ऋण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां

- ➔ **ऋण का बोझ:** निवेश व उपभोग की क्षमता को कम करके आर्थिक संवृद्धि को बाधित करता है।

- ➔ **तरलता संबंधी चुनौती:** विकासशील देशों से निजी ऋणदाताओं द्वारा लगभग 50 बिलियन डॉलर की निकासी ने तरलता की कमी को और बढ़ा दिया है।
- ➔ **पश्चिमी प्रभुत्व वाले ऋणदाता संस्थान** (निजी, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणदाता) ऋण की पुनर्संरचना को मंहंगा बनाते हैं।

सिफारिशें

- ➔ बेहतर ऋण पुनर्गठन तंत्र, आकस्मिक वित्तपोषण में वृद्धि (ऋण संकट को टालने के लिए) और वैश्विक वित्तीय गवर्नेंस में विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

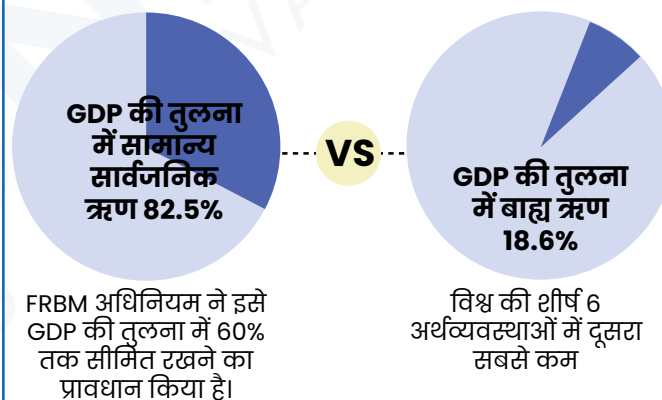
सार्वजनिक ऋण



सार्वजनिक ऋण क्या है?

सार्वजनिक ऋण (यानी संप्रभु ऋण) किसी सरकार द्वारा कुल वित्तीय देनदारियां होती है। इसे घरेलू या बाह्य स्रोतों से लिया जाता है। ऐसे ऋण सरकार अपने उन व्ययों को पूरा करने के लिए लेती है, जो सरकार के राजस्व से अधिक हो जाते हैं।

भारत के सार्वजनिक ऋण का अवलोकन



3.15.8. द्विपक्षीय स्वैप एग्रीमेंट {BILATERAL SWAP AGREEMENT (BSA)}

भारत और जापान ने 75 अरब डॉलर के द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौते को नवीनीकृत किया है।

द्विपक्षीय स्वैप एग्रीमेंट (BSA) के बारे में:

- ➔ यह दो केंद्रीय बैंकों के बीच एक समझौता है। इसके तहत विभिन्न मुद्राओं में नकदी प्रवाह से पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार विनिमय किया जाता है।
- ➔ **भारत-जापान BSA का उद्देश्य:** यह दोनों देशों को जरूरत पड़ने पर अपनी स्थानीय मुद्रा के बदले अमेरिकी डॉलर में बदलने में सक्षम बनाता है।
- ➔ **महत्व:** विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने में सहायता और वित्तीय संकटों के दौरान तरलता सुनिश्चित करता है।

3.15.9. सड़क क्षेत्रक में सबसे बड़ा InvIT मुद्रिकरण (LARGEST INVIT MONETIZATION IN ROADS SECTOR)

नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट (NHIT) ने सड़क क्षेत्र में InvITs के माध्यम से सबसे बड़ी धनराशि जुटाई है।

- ➔ NHIT राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 2020 में स्थापित InvIT है। इसका उद्देश्य भारत के परिसंपत्ति मुद्रिकरण कार्यक्रम में योगदान देना है।

अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvITs) के बारे में

- ➔ परिभाषा: निवेश जुटाने का एक साधन है, जो वास्तव में म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) की तरह कार्य करते हैं।
- ➔ InvITs किसी व्यक्ति/संस्थागत निवेशकों को सीधे या किसी स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)/ होल्डिंग कंपनी के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देते हैं।
- ➔ आय: InvITs टोल, रेंट, निवेश पर ब्याज या लाभांश के माध्यम से उत्पन्न; यूनिट होल्डर्स के लिए कर योग्य।
- ➔ विनियमन: सेबी (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 के तहत प्रशासित।
 - सेबी निवेशकों को 90% आय वितरण अनिवार्य करता है।
 - वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी/ SARFAESI), 2002 के तहत "उधार लेने वाले" के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- ➔ प्रकार: सार्वजनिक क्षेत्र के InvITs; निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध InvITs; तथा निजी क्षेत्र के गैर-सूचीबद्ध InvITs.
- ➔ लाभ: रिटेल यानी व्यक्तिगत निवेशक द्वारा बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश, कम प्रवेश लागत और स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के माध्यम से तरलता को सक्षम बनाता है।

InvIT का संरचनात्मक अवलोकन	
प्रायोजक	इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या प्राइवेट इक्विटी फर्म मुख्य कार्य: InvIT की स्थापना; इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों को InvIT ट्रस्ट में स्थानांतरित करना।
InvIT	बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है। प्राथमिक कार्य: बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों का रखरखाव; निवेश इकाइयां जारी करना।
निवेशक	InvIT में स्वामित्व हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयां प्राप्त करना।

परिसंपत्ति मुद्रिकरण (Asset Monetization) के बारे में

- ➔ परिभाषा: अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करके नए राजस्व अर्जित करने की प्रक्रिया है।
- ➔ भारत का मुद्रिकरण कार्यक्रम
 - राष्ट्रीय मुद्रिकरण पाइपलाइन (NMP): यह नीति आयोग द्वारा विकसित है, 2022-2025 तक 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।
 - दूसरी परिसंपत्ति मुद्रिकरण योजना (2025-2030): केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी, जिसमें मुद्रिकरण से 10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
 - अन्य योजनाएं: इसमें राष्ट्रीय भूमि मुद्रिकरण निगम शामिल है।

3.15.10. MSMEs के लिए नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (DIGITAL FOOTPRINT-BASED LENDING FOR MSMEs)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऋण मूल्यांकन और संवितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए MSMEs का डिजिटल फुटप्रिंट-आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लॉन्च किया।

नए ऋण मूल्यांकन मॉडल के बारे में

- ➔ यह MSMEs के ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम डेटा का उपयोग करेगा।
- ➔ इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, पारंपरिक क्रेडिट स्कोर पर निर्भरता को कम करना और एमएसएमई को बैंकिंग संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना आसान बनाना है।
- ➔ सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक MSMEs को ऋण देने से पहले उनके ऋण भुगतान की क्षमता का आकलन करेंगे, ताकि उन्हें किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर ना रहना पड़े।

3.15.11. वेंचर कैपिटल (VENTURE CAPITAL)

भारत की वेंचर कैपिटल (VC) फंडिंग 2024 में 43% बढ़कर 13.7 बिलियन डॉलर हो गई।

वेंचर कैपिटल के बारे में

- ➔ यह निजी इक्विटी का एक रूप है, जो दीर्घकालिक विकास क्षमता वाले स्टार्ट-अप तथा लघु व्यवसायों के लिए वित्त-पोषण का एक प्रकार है।
- ➔ इसमें इक्विटी शेयर या परिवर्तनीय ऋण शामिल है, जो फर्म को स्वामित्व प्रदान करता है।
- ➔ वित्त-पोषण, तकनीकी विशेषज्ञता या प्रबंधकीय सहायता प्रदान करता है।

3.15.12. पुनर्बीमा (REINSURANCE)

वैल्यूएटिक्स री (Valueattics Re) भारत में पुनर्बीमा कारोबार शुरू करने के लिए IRDAI से मंजूरी पाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है।

- ➔ वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्रक की जनरल इंड्योरेंस कॉरपोरेशन (GIC Re) भारत में कार्यरत एकमात्र पुनर्बीमा कंपनी है।

पुनर्बीमा के बारे में

- ➔ पुनर्बीमा जोखिम प्रबंधन पद्धति है। इसमें बीमा कंपनियां अपने जोखिम का एक हिस्सा किसी अन्य बीमा कंपनी (रीइंशोरर/पुनर्बीमाकर्ता) को हस्तांतरित करती है।
- ➔ विनियामक: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)।
- ➔ कानून: बीमा अधिनियम, 1938 और IRDAI (पुनर्बीमा) विनियम, 2018

3.15.13. समर्थ (SAMARTH)

टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने दूरसंचार और IT क्षेत्रकों के लिए अत्याधुनिक इनक्यूबेशन कार्यक्रम 'समर्थ' का शुभारंभ किया।

समर्थ के बारे में

- ➔ कानून: बीमा अधिनियम, 1938 और IRDAI (पुनर्बीमा) विनियम, उद्देश्य: सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, आदि।

- **कानून: बीमा अधिनियम, 1938 और IRDAI (पुनर्बीमा) विनियम, कार्यान्वयन साझेदार:** सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन।

3.15.14. अपलिंग इनिशिएटिव (UPLINK INITIATIVE)

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के तहत अपलिक इनिशिएटिव से 2023-2024 के दौरान कार्बन उत्सर्जन में 142,400 टन की कटौती हुई।

अपलिंक इनिशिएटिव के बारे में

- ➔ यह **प्रभावशाली प्रारंभिक चरण के इनोवेशन** पर केंद्रित है।
- ➔ इसे **डेलॉइट और मैल्सफोर्स** के सहयोग से **WEF द्वारा 2020** में लॉन्च किया गया था।
- ➔ यह ऐसे **इकोसिस्टम्स** का निर्माण करता है, जो उद्देश्य युक्त, शुरूआती चरण के उद्यमियों को नेट जीरो उत्सर्जन, प्रकृति-अनुकूल और न्यायसंगत भविष्य के लिए अपने व्यवसायों को बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
- ➔ **उद्देश्य:** प्रारंभिक चरण के इनोवेटर्स को सहायता देना, इनोवेशन आधारित इकोसिस्टम को सक्षम बनाना और धारणा को प्रभावित करना।

GS मेन्स एडवांस कोर्स 2025



 लाइव/ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

यह कार्य मूलभूत अवधारणाओं की समझ रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके तहत अभ्यर्थियों को जटिल टॉपिक्स तथा उन्हें आपस में जोड़ कर पढ़ने और समझ विकसित करने में उनकी मदद की जाएगी। साथ ही, मुख्य परीक्षा में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए उनकी विशेषतात्मक समता में सुधार किया जाएगा।



अवधारणात्मक रूप से कठिन टॉपिक्स
को कवर किया जाएगा



मेन्स 2025 हेतु आवश्यक
विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर
बल दिया जाएगा



कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा (सॉफ्ट कॉपी)



सेक्शनल मिनी टेस्ट का आयोजन
किया जाएगा



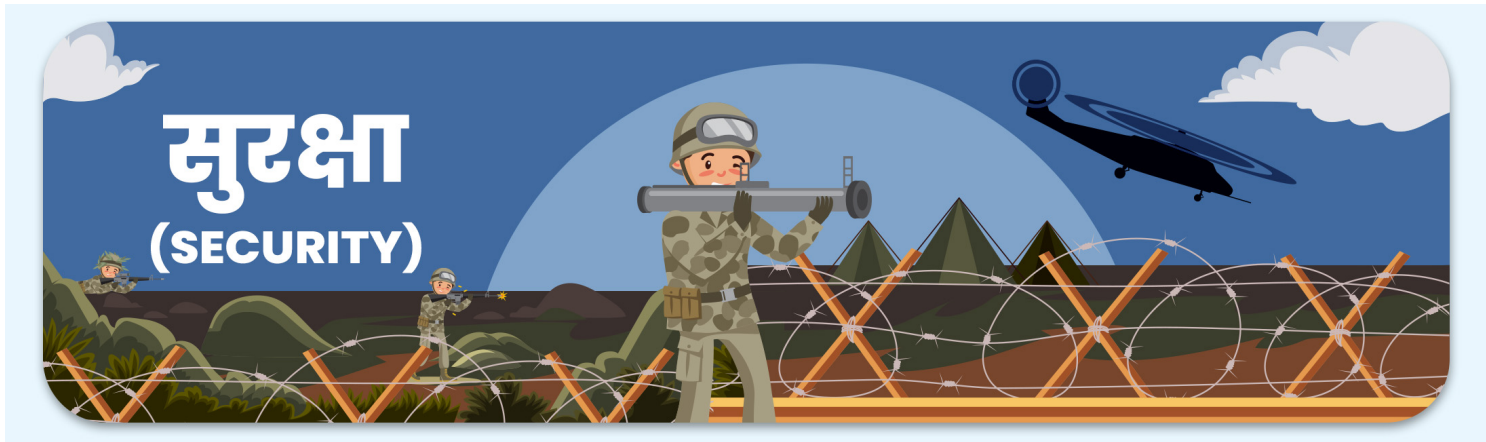
कोर्स की अवधि: 7 सप्ताह, प्रति सप्ताह 6-7 कक्षाएं (जरूरत पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

Scan the QR CODE to
download VISION IAS app



ENGLISH MEDIUM
हिन्दी माध्यम

5 JUNE



4.1. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका (ROLE OF QUANTUM COMPUTING IN NATIONAL SECURITY)

मुख्तियारों में क्यों?

नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) ने “क्वांटम कंप्यूटिंग: राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ और रणनीतिक तैयारी” पर एक रणनीतिक-पत्र जारी किया।

नोट: क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया जून, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 8.1 देखें।

क्वांटम कंप्यूटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा को कैसे बदल रही है

- **क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा:** क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं, जिससे डेटा की सुरक्षा के लिए पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) को अपनाया जा सकता है।
 - ➔ **उदाहरण के लिए-** संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट 2018 साइबर खतरों से निपटने हेतु PQC के उपयोग पर जोर देता है।
- **इंटेलिजेंस द्वारा जुटाई गई जानकारी का बेहतर उपयोग:** क्वांटम कंप्यूटिंग बेहतर खुफिया विश्लेषण के लिए जटिल डेटासेट को काफी बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकती है और संचार को बाधित कर सकती है।
 - ➔ **उदाहरण के लिए-** नाटो की 2024 की रणनीति क्वांटम-रेडी डिफेंस एप्लीकेशंस को बढ़ावा देती है।
- **सुरक्षित संचार: क्वांटम-की-डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) के तहत** एन्क्रिप्शन कीज को साझा करके संचार को प्रमाणित रूप से सुरक्षित बनाया जाता है।
 - ➔ **उदाहरण के लिए-** चीन ने बीजिंग और शंघाई के बीच दुनिया का सबसे लंबा (2,000 कि.मी.) स्थलीय QKD नेटवर्क बनाया है।
- **सैन्य हार्डवेयर:** क्वांटम प्रौद्योगिकियां मटेरियल्स साइंस में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। इससे अगली पीढ़ी का सैन्य हार्डवेयर विकसित हो सकेंगे।
 - ➔ **उदाहरण के लिए-** क्वांटम-आधारित AI स्वचालित सैन्य ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम्स के संचालन को बेहतर बना सकते हैं।
- **इकोनॉमिक वारफेयर:** एन्क्रिप्शन को तोड़ने की क्षमता वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर सकती है।
 - ➔ **उदाहरण के लिए-** संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट जैसी पहल आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा दोनों के लिए क्वांटम संबंधी नवाचार की आवश्यकता को उजागर करता है।
- **भू-राजनीतिक शक्ति:** क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जल्दी सफलता प्राप्त करने वाले देश इस क्षेत्र से संबंधित तकनीकी और ज्ञान का आधार स्थापित करने में अग्रणी रहेंगे।
 - ➔ **उदाहरण के लिए-** चीन के मिसाइल उपग्रह (2016) ने क्वांटम आधारित सुरक्षित लंबी दूरी के संचार को संभव किया है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत द्वारा उठाए गए कदम



राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
क्वांटम अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है



QuesT कार्यक्रम
क्वांटम प्रयोगशालाओं और आवश्यक अवसंरचना विकसित करने का समर्थन करता है



अकादमिक अनुसंधान और नवाचार केंद्र
संस्थानों में क्वांटम अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना



निजी क्षेत्र का योगदान
क्वांटम सुरक्षित नेटवर्क विकसित करता है



अन्य पहल
इसमें क्वांटम संचार प्रयोगशाला और QKD सोल्यूशंस शामिल हैं

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का लाभ उठाने के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां

- **कार्यबल की कमी:** मैकिन्से (2022) के अनुसार, क्वांटम कंप्यूटिंग संबंधी हर तीन नौकरियों के लिए केवल एक योग्य उम्मीदवार उपलब्ध है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** क्वांटम अनुसंधान एवं विकास (R&D) में असमान निवेश रणनीतिक अंतर पैदा कर रहा है: चीन (\$15 बिलियन), अमेरिका (\$5.8 बिलियन), भारत (\$0.758 बिलियन)।
- **संसाधनों में असमानता:** कम निवेश वाले देशों के लिए सुरक्षित क्वांटम संचार का अभाव।

- **तकनीक में परिपक्वता की कमी:** प्रारंभिक चरण के क्वांटम कंप्यूटरों में स्थिरता और स्केलेबिलिटी का अभाव है। उदाहरण के लिए, IBM का 433-क्यूबिट ऑस्त्रो प्रोसेसर अभी भी त्रुटि दरों की समस्या का सामना कर रहा है।
- **डेटा संबंधी जोखिम:** भविष्य में हैकर्स द्वारा डेटा डिक्रिप्शन का खतरा।

प्रमुख सिफारिशें

- **निरंतर निगरानी:** वैश्विक स्तर पर क्वांटम के क्षेत्र में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक **क्वांटम टास्क फोर्स** की स्थापना करनी चाहिए।
- **क्रिप्टोग्राफिक इंटेलिजेंस:** क्वांटम से संबंधित सुभेद्यताओं की पहचान करने के लिए नियमित ऑडिट किया जाना चाहिए।
- **PQC ट्रांजिशन प्लान:** PQC को अपनाने के लिए एक रोडमैप विकसित करना और क्रॉस-सेक्टर सहयोग सुनिश्चित करें।
 - ➔ **उदाहरण के लिए,** Google Chrome का Kyber जैसे PQC एल्गोरिदम का परीक्षण।
- **क्वांटम कार्यबल को सशक्त बनाना:** उच्चतर शिक्षा स्तर पर क्वांटम सूचना विज्ञान (QIS) संबंधी शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए; तथा वैश्विक प्रतिभा के लिए इमिग्रेशन नीति में सुधार करना चाहिए।
- **क्वांटम इकोसिस्टम का निर्माण:** यूएस क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम (QED-C) जैसे संघों के माध्यम से एक जीवंत क्वांटम उद्योग बनाएँ।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** QIS प्रौद्योगिकी विकास में समन्वय हेतु सहयोग करने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ क्वांटम पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना चाहिए।
 - ➔ उदाहरण के लिए- भारत और यूरोपीय आयोग ने 2022 में **"HPC, वेदर एक्सट्रीम्स एंड क्लाउडमेट मॉडलिंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीस पर सहयोग हेतु इंटेक्ट ऑफ को-ऑपरेशन"** पर हस्ताक्षर किए थे।
- **अन्य:** संभावित नवाचारों के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली, एन्क्रिप्शन संबंधी बदलावों को तेजी से अपनाने में मदद करने हेतु क्रिप्टो एजिलिटी फ्रेमवर्क अनुसंधान एवं विकास (R&D) फंडिंग में लचीलापन।

निष्कर्ष:

क्वांटम कंप्यूटिंग भारत की रणनीतिक व सामरिक लचीलापन तथा विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होगी।

4.2. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

4.2.1. अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण के रुझान, 2024 (TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2024)

SIPRI ने वैश्विक हथियार हस्तांतरण में महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाने वाले नए आंकड़े जारी किए।

मुख्य आंकड़ों पर एक नज़र

- **भारत:** भारत अब यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है; घरेलू उत्पादन के कारण हथियारों के आयात में 9.3% की गिरावट आई है। रुस अभी भी भारत के लिए एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। यद्यपि भारत फ्रांस, इजरायल और अमेरिका से हथियार खरीद कर हथियार के आयात में विविधता बनाए हुए है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका** की वैश्विक स्तर पर हथियार निर्यात में हिस्सेदारी बढ़कर 43% हो गई है।
- **रुस द्वारा हथियार निर्यात में 64% की गिरावट** आई है।

4.2.2. भारत में सोने की तस्करी (SMUGGLING OF GOLD IN INDIA)

हाल ही में, एक अभिनेत्री को **सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार** किया गया।

- सोने की तस्करी से विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है और संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है।
- अवैध सोने का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों से भारत में आता है।
- **कानून:** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और भारतीय न्याय संहिता, 2023; आर्थिक दंड लगाया जाता है, और UAPA तस्करी को "आतंकवादी कृत्य" मानता है यदि यह भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है।

4.2.3. C-DOT का त्रिनेत्र (C-Dot Trinetra)

केरल ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए **केरल पुलिस** हेतु **'एडवांस्ड साइबर सिम्योरीटी ऑपरेशंस सेंटर' (SOC)** लॉन्च किया है।

- यह **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) के 'त्रिनेत्र' (TRINETRA) प्लेटफॉर्म** पर आधारित है।

के त्रिनेत्र के बारे में

- **C-DOT:** यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। यह एंडपॉइंट्स, नेटवर्क ट्रैफिक और यूजर बिहेवियर की निगरानी करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह सुभेद्यताओं की पहचान करने, विसंगतियों का पता लगाने और साइबर खतरों को कम करने में भी सहायक है।

4.2.4. गांधीव मिसाइल (MISSILE 'GANDIVA')

DRDO ने अपनी हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक को आधिकारिक तौर पर **"गांधीव"** (अस्त्र MK-3) नाम दिया।

विशेषताएं: 'सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रणोदन प्रणाली' का उपयोग किया गया है। यह 300-350 किलोमीटर की विस्तारित रेंज में मैक 4.5 तक की सुपरसोनिक गति पर रहते हुए यात्रा कर सकती है।

4.2.5. अश्विनी (ASHWINI)

रक्षा मंत्रालय ने **भारतीय वायु सेना के लिए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार (LLTR) 'अश्विनी'** की खरीद अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य विशेषताएं:

- यह तेज गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स जैसे हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है।
- यह रडार 200 कि.मी. तक के क्षेत्र में लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है।

4.2.6. सोनिक वेपन (SONIC WEAPON)

सर्बिया ने बेलग्रेड में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए प्रतिबंधित 'सोनिक वेपन' के इस्तेमाल से इनकार किया।

- सोनिक वेपन के बारे में: ये उपकरण लंबी दूरी तक बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिससे टिनिटस और सुनने की क्षमता में कमी जैसे प्रभाव होते हैं।

4.2.7. गोल्डन डोम (GOLDEN DOME)

संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

- गोल्डन डोम के बारे में: एक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों तथा अन्य उन्नत हवाई हमलों के खतरों से अमेरिका की रक्षा करना है। यह इंटरायल की आयर्न डोम प्रणाली से प्रेरित है।

4.2.8. क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CONVENTION ON CLUSTER MUNITIONS)

लिथुआनिया ने रूस से सुरक्षा चिंताओं के कारण क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CCM) से हटने की घोषणा की।

क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CCM) के बारे में

- यह संधि क्लस्टर म्यूनिशंस/हथियारों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। 2010 से प्रभावी है। भारत, रूस, चीन और अमेरिका इस पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।

4.2.9. सुर्खियों में रहे युद्ध अभ्यास (Exercises in News)

युद्ध अभ्यास इंद्र 2025	➤ इसका 14वां संस्करण 28 मार्च, 2025 से 02 अप्रैल, 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया गया। ➤ यह भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, जो 2003 से शुरू हुआ था।
प्रचंड प्रहार अभ्यास	➤ भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) ने अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं के एकीकृत बहु-क्षेत्रीय अभ्यास, प्रचंड प्रहार का आयोजन किया।
वरुण सैन्य अभ्यास 2025	➤ हाल ही अरब सागर में वरुण सैन्य अभ्यास 2025 संपन्न हुआ। यह भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
बोंगो सागर 2025	➤ यह भारत-बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ➤ अन्य द्विपक्षीय अभ्यास: अभ्यास सम्प्रीति- वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसमें आतंकवाद-रोधी अभियान और आपदा प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
युद्ध अभ्यास खंजर	➤ यह भारत-किर्गिजस्तान संयुक्त विशेष बलों का युद्ध अभ्यास है, इसे वार्षिक रूप से दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। ➤ उद्देश्य: आतंकवाद-रोधी और विशेष बल अभियानों में सहयोग करना।
ट्रोपेक्स/ TROPEX - 2025	➤ यह भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्ध अभ्यास है। ➤ उद्देश्य: भारतीय थल सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल के समन्वय में परिचालन तैयारियों का आकलन करना।
युद्ध अभ्यास डेजर्ट हंट 2025	➤ यह तीनों सेनाओं के विशेष बल का युद्ध अभ्यास है। इसमें पैरा (विशेष बल), मरीन कमांडो (MARCOS), और गरुड़ स्पेशल फोर्स शामिल होते हैं। ➤ उद्देश्य: आपसी सहयोग, समन्वय और तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमताओं को परखना।
INIOCHOS-25	➤ यह ग्रीस की हेलनिक एयर फोर्स द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ➤ भारतीय वायु सेना ने सामरिक ज्ञान और सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए इसमें भाग लिया।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

► प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 27 मई, 11 AM

JAIPUR: 12 मई

JODHPUR: 15 मई

प्रवेश प्रारम्भ

BHOPAL | LUCKNOW

पर्यावरण (ENVIRONMENT)



5.1. जैव ईंधन (BIOFUELS)

सुखियों में क्यों?

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बन गया है।

जैव ईंधन के बारे में

- नवीकरणीय संसाधनों से उत्पादित ईंधन को जैव ईंधन कहा जाता है। इसका उपयोग जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर या उनके साथ मिश्रित कर किया जाता है।
- प्रकार: इन्हें चार पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है।
- प्रमुख उत्पादक देश: यूएसए जैव ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद ब्राजील का स्थान है।
- इसमें एथेनॉल और बायोडीजल, संपीड़ित बायोगैस (CBG), सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) आदि शामिल हैं।

जैव ईंधन का महत्त्व

- पर्यावरणीय लाभ: जीवाश्म ईंधन की तुलना में उत्सर्जन को 80% तक कम कर सकते हैं और पराली जलाने की समस्या को हल कर सकते हैं।
- ऊर्जा सुरक्षा: इथेनॉल मिश्रण की वजह से 1,13,007 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसने तेल क्षेत्र की अस्थिरता को कम करने में मदद की है।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था: यह अपशिष्ट से धन सृजन करके व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करता है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: यह किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है।
- डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग: औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ नवीकरणीय मेथनॉल और उपोत्पादों का उत्पादन करता है।

जैव ईंधन का विकास

- पहली पीढ़ी: खाद्य फसलों से प्राप्त ईंधन।
- दूसरी पीढ़ी: जैविक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन।
- तीसरी पीढ़ी: शैवाल आधारित ईंधन।
- चौथी पीढ़ी: आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीवों से तैयार ईंधन।

जैव ईंधन के साथ चुनौतियां

- फीडस्टॉक चुनौतियां: फीडस्टॉक को अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। कृषि अपशिष्ट की मौसमी उपलब्धता और विघटन से जुड़ी बाधाएं।
- अवसंरचना संबंधी बाधाएं: विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाओं का अभाव है।
- खाद्य सुरक्षा बनाम ईंधन दुविधा: खाद्य फसलों की जगह इनकी खेती, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है।
- वित्त-पोषण की आवश्यकता: लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक 100-270 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।
- पारंपरिक ईंधन से प्रतिस्पर्धा: SAF पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में 2-10 गुना अधिक महंगा है।
- कम ऊर्जा दक्षता: जैव ईंधन में जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है।

जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली/वाले प्रमुख पहलें/कदम

नीतिगत और रोडमैप संबंधी पहलें:

- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018, 2022 में संशोधित): फीडस्टॉक आधार का विस्तार किया गया है और वित्तीय प्रोत्साहन की शुरुआत की गई है।
- एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम: जनवरी 2025 तक पेट्रोल में 19.6% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

अवसंरचना और उत्पादन सहायता:

- **प्रधानमंत्री जी-वन योजना (2019):** 2G एथेनॉल क्षमता में प्रगति को बढ़ावा देना।
- **गोबर-धन योजना:** कृषि अपशिष्ट और पशुओं के गोबर से बायोगैस को बढ़ावा देना।
- **सतत/ SATAT पहल (2018):** बायोमास अपशिष्ट से आर्थिक मूल्य प्राप्त करना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- **ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (2023):** जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाली पहल।
 - ➔ **द्विपक्षीय तंत्र:** इंडिया-ब्राजील सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल।
- **अन्य:** जैव डीजल की खरीद पर GST दर को 12% से घटाकर 5% किया गया है। E20 ईंधन, एथेनॉल 100 आदि को लॉन्च किया गया है।

5.2. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NATIONAL BOARD FOR WILDLIFE: NBWL)**मुख्तियों में क्यो?**

भारत के प्रधान मंत्री ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की।

अन्य संबंधित तथ्य

- NBWL की हाल ही में हुई बैठक 10 वर्षों के बाद हुई (पिछली पूर्ण बैठक 2012 में हुई थी)।
- 2025 में शेरों की संख्या का आकलन करने के 16वें चक्र की शुरुआत की घोषणा की।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में

- यह एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन के बाद 2003 में किया गया था।
- **उत्पत्ति:** 1952 में गठित भारतीय वन्यजीव बोर्ड (IBW) से विकसित।
- **सदस्य:**
 - ➔ **अध्यक्ष:** प्रधान मंत्री।
 - ➔ **उपाध्यक्ष:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री।
 - ➔ NGO प्रतिनिधि और प्रख्यात संरक्षणवादी।
- **स्थायी समिति** की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है।
- इसके कार्यों में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना, नीतियां बनाना, संरक्षित क्षेत्रों पर सिफारिशें करना और वन्यजीवों पर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना शामिल है।

NBWL से जुड़ी चिंताएं

- पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बावजूद संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- स्वीकृत परियोजनाओं से लुप्तप्राय प्रजातियों को खतरा है।
- निर्णय लेने में स्वतंत्र सदस्यों की सीमित भूमिका।
- परियोजना मंजूरी में स्थानीय समुदायों की राय की उपेक्षा की जाती है।
- परियोजना मंजूरी के बाद अनुपालन की अपर्याप्त निगरानी की जाती है।

आगे की राह

- योग्य वन्यजीव वैज्ञानिकों एवं संरक्षण के क्षेत्र में संलग्न NGOs की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- वार्षिक प्रमाण-पत्रों के माध्यम से अनुपालन की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- वन-आश्रित समुदायों से स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के माध्यम से स्थानीय समुदाय की भागीदारी को संस्थागत बनाया जाना चाहिए।
- पारिस्थितिकी के प्रति अनुकूल विकल्पों को प्रोत्साहित करके विकास और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना चाहिए।
- बेहतर प्रभाव आकलन के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

5.3. प्रोजेक्ट लायन और IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ़ स्पीशीज (PROJECT LION AND IUCN GREEN STATUS OF SPECIES)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्र ने शेरों के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 'प्रोजेक्ट लायन' के लिए वित्त-पोषण को मंजूरी दी।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार ने वन्यजीवों में बीमारियों की निगरानी के लिए गुजरात के जूनागढ़ जिले में नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ (NRC-W) की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
- IUCN ने शेरों के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट भी जारी किया है। इसमें शेरों को "बहुत अधिक गिरावट" श्रेणी में रखा है।
- आकलन से यह भी पता चला कि मानवीय गतिविधियों का प्रभाव शेरों को उनके संपूर्ण प्राकृतिक पर्यावास में पारिस्थितिक रूप से पूरी भूमिका निभाने में बाधा डालता है।

IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ़ स्पीशीज

- यह प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति को मापने और संरक्षण प्रभाव का आकलन करने के लिए एक वैश्विक मानक प्रदान करता है।
- सूक्ष्मजीवों को छोड़कर सभी प्रजातियों का कवरेज, आठ ग्रीन स्टेटस श्रेणियां और रेड लिस्ट को पूरक बनाना इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल है।
- कोई प्रजाति पूर्णतः पुनर्प्राप्त हो जाती है, यदि वह अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है। वह अपने पूरे पर्यावास में व्यवहार्य आबादी में मौजूद है। वह अपने पर्यावास के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती है।

प्रोजेक्ट लायन (2020) के बारे में

- उद्देश्य: व्यापक संरक्षण संबंधी प्रयासों के माध्यम से एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना।
- मुख्य फोकस क्षेत्र: परिदृश्य पारिस्थितिकी-आधारित संरक्षण, शेरों के पर्यावास का पुनरुद्धार, सामुदायिक भागीदारी और रोग प्रबंधन।
- समय अवधि: 10 वर्ष।
- कार्यान्वयन: गुजरात सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा।

एशियाई शेर (भारतीय शेर) के बारे में

- पर्यावास: घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियां और खुले वन।
- वितरण: वर्तमान में केवल गुजरात के गिर भू-परिदृश्य में पाए जाते हैं।
- मुख्य विशेषताएं: वयस्क नर शेर मादाओं की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इनका जीवनकाल लगभग 16-18 वर्ष का होता है। शेर बड़े झुंडों में रहते हैं। शेर रात में ही शिकार करते हैं। मादाओं की गर्भधारण अवधि लगभग 100 से 119 दिनों तक रहती है। नर शेर नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं।
- पारिस्थितिक भूमिका: शेर शीर्ष शिकारी होते हैं। वे शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और बीमारी के प्रसार पर रोक लगाते हैं।
- आबादी: 2020 में 674 (2015 में 523) थी।
- संरक्षण स्थिति: वल्नरेबल (IUCN); वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची-I में सूचीबद्ध; तथा CITES: परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध।
- उप-प्रजातियां: नॉर्डन लायन (पेंथरा लियो लियो): उत्तर, मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। इसमें एशियाई शेर शामिल हैं। सदरन लायन: पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी शेर।

कई अन्य पहलों ने एशियाई शेरों के संरक्षण को और मजबूत किया है

- इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस (2023)।
- एशियाई शेर संरक्षण परियोजना।
- अतिरिक्त उपयुक्त पर्यावास विकसित करने के लिए ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट।
- वन्यजीव अपराध प्रकोष्ठ सहित मजबूत सुरक्षा तंत्र।
- अन्य पहलों में CSS-DWH समर्थन, पर्यावास सुधार उपाय और विश्व शेर दिवस मनाना शामिल हैं।

गिर भू-क्षेत्र

- गिर वन भारत के अर्ध-शुष्क पश्चिमी भाग में शुष्क पर्णपाती वनों का सबसे बड़ा सघन क्षेत्र है।
- इसमें ऊबड़-खाबड़ भूमि, पहाड़ियां, पठार और घाटियां हैं।
- विभिन्न नदियों, वनस्पतियों, जीवों और मालधारी जनजातीय समुदाय का घर है।

5.4. नदी डॉल्फिन (RIVER DOLPHINS)

मुख्तियों में क्यों?

नदी डॉल्फिन के पहले व्यापक सर्वेक्षण से पता चला है कि मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटियों में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या 6,327 है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 'प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020' के तहत किया।
- इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष "भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024" शीर्षक वाली रिपोर्ट में प्रकाशित हुए हैं।

"भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024" रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- 20वीं सदी के अंत तक गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या 4,000-5,000 थी, लेकिन यह घटकर लगभग 1,800 रह गई है।
- भारत में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या 6,327 है, जिसमें गंगा नदी की डॉल्फिन (6324) और सिंधु नदी की डॉल्फिन (केवल 3) हैं।
- उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की सबसे ज्यादा आबादी है। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, असम झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है।
- सिंधु नदी डॉल्फिन की संख्या चिंताजनक रूप से कम है। इसके संरक्षण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- डॉल्फिन पर्यावास और जैव विविधता संरक्षण के लिए अंबेला प्रजाति के रूप में कार्य करती हैं।

भारतीय वन्यजीव संस्थान

- उत्पत्ति: 1982, WII को अप्रैल 1986 में स्वायत्तता प्रदान की गई थी।
- मुख्यालय: देहरादून
- मंत्रालय: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- गवर्नेस: भारतीय वन्यजीव संस्थान का शासन केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता वाली सोसायटी के अधीन चलता है।
- मिशन: वन्यजीव विज्ञान के विकास को बढ़ावा देना और हमारे सांस्कृतिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अनुरूप संरक्षण में इसके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- कार्य: वन्यजीव और जैव विविधता अनुसंधान एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम व सलाह।
- महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ: पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस, पर्यावरण सूचना प्रणाली केंद्र (ENVIS) आदि।

गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में तथ्य

- मुख्य रूप से गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगु नदी प्रणालियों में पाई जाती है।
- भारत में दुनिया की 90% गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं।
- यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। स्थानीय रूप से इसे 'सूंसा' कहा जाता है।
- यह शीर्ष शिकारी व संकेतक प्रजाति है, जिस कारण से इसे "टाइगर ऑफ गंगा" कहा जाता है।
- CITES: परिशिष्ट-I; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: अनुसूची-I; IUCN स्थिति: एंडेंजर्ड।
- आमतौर पर एकांतवासी एवं दृष्टिहीन जीव। इकोलोकेशन के जरिए नदी के जल में अपना मार्ग और शिकार खोजती है।

सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में मुख्य तथ्य

- इसे 2019 में पंजाब ने राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया था।
- रंग भूरा या धूसर (ग्रे) होता है, दृष्टिहीन होती है तथा दिशा और शिकार के लिए इकोलोकेशन तकनीक का उपयोग करती हैं।
- पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रणाली और पंजाब में ब्यास नदी में पाई जाती है।
- इनका स्थानीय नाम "भूलन" है।
- वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 में गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन को दो अलग-अलग प्रजातियों के रूप में शामिल किया गया है।

गंगा नदी की डॉल्फिन के समक्ष खतरा

- मछली पकड़ने के दौरान गलती से मृत्यु, बायकेच और जानबूझकर हत्या की जाती है।
- मानव निर्मित जलीय अवसंरचना पर्यावास संपर्क को बाधित कर रही है।
- खनन, कृषि और औद्योगिक गतिविधियां जल की गुणवत्ता को खराब कर रही हैं।
- नावों की आवाजाही में वृद्धि और मानवीय गतिविधियों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों में खारा पानी भी प्रवेश कर रहा है।

नदी डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए भारत की पहलें

- संरक्षण और पर्यावास सुधार के लिए व्यापक कार्य योजना (2022-2047)।
- वन्यजीव पर्यावास विकास योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता
- विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना।
- चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र को नामित किया गया।

- जागरूकता के लिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है।
- पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना।
- 2024 में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली सैटेलाइट-टैगिंग।

5.5. जंपिंग स्पाइडर्स (JUMPING SPIDERS)

सुर्खियों में क्यों?

एक सहयोगात्मक शोध में पश्चिमी घाट के शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य (केरल) से जंपिंग स्पाइडर्स की दो नई प्रजातियों की खोज की गई।

नई प्रजातियों के बारे में

- दोनों नई प्रजातियां एपिडेलेक्सिया कुल से संबंधित हैं।
- इस जीनस को भारत में पहली बार दर्ज किया गया है। पहले इसे श्रीलंका की स्थानिक प्रजाति माना जाता था।

जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में:

- **कुल:** यह मकड़ियों (स्पाइडर्स) के सबसे बड़े कुल से संबंधित हैं।
- **पर्यावास:** उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य।
- **विशेषताएं:**
 - ➔ अपने शरीर की लंबाई से 30 गुना अधिक दूरी तक छलांग लगा सकती हैं।
 - ➔ इनके सामने के बड़े पैर इन्हें शिकार को पकड़ने और पकड़े रहने में मदद करते हैं। ये अपने पिछले पैरों का उपयोग छलांग लगाने के लिए करती हैं।
- अधिकांश मकड़ियों की आठ या छः आंखें होती हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कमजोर होती है।
 - ➔ जंपिंग स्पाइडर्स की 8 आंखें होती हैं, जो युग्मों में व्यवस्थित होती हैं। साथ ही, मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा रंग देख सकती हैं।
 - ➔ दिन में शिकार करते समय जंपिंग स्पाइडर्स लाल स्पेक्ट्रम, हरा स्पेक्ट्रम और पराबैंगनी प्रकाश में देख सकती हैं।
- **व्यवहार:**
 - ➔ जंपिंग स्पाइडर्स सक्रिय शिकारी होती हैं और कीड़ों तथा अन्य मकड़ियों का शिकार करती हैं।
 - ➔ जंपिंग स्पाइडर्स अपने रेशम से "प्लूप टेंट" नामक आश्रय बनाती हैं।

मकड़ियों बनाम कीट

- **वर्गीकरण:**
 - ➔ **मकड़ियां:** वर्ग अरचिन्डा
 - ➔ **कीट:** वर्ग इन्सेक्टा
- **शरीर की संरचना:**
 - ➔ **मकड़ियां:** 2 खंड (सेफालोथोरैक्स और वक्ष), 8 पैर
 - ➔ **कीट:** 3 खंड (सिर, वक्ष व पेट), 6 पैर
- **मुख्य विशेषताएं:**
 - ➔ **मकड़ियां:** एंटीना नहीं होते, कोई पंख नहीं, कोई कार्यांतरण नहीं।
 - ➔ **कीट:** एंटीना होते हैं, अक्सर पंख होते हैं, कार्यांतरण से गुजरते हैं।
- **समानताएं:**
 - ➔ दोनों ही फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित हैं।
 - ➔ दोनों में एक्सोस्केलेटन और जोड़दार पैर होते हैं।

शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **नाम:** यहां की एक स्थानिक वृक्ष प्रजाति "चेंकुरिंजी" पर रखा गया गया है।
- **अवस्थिति:** यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। यह आगस्थमाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है।
- **वनस्पति:** उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्द्ध-सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन।
- **प्राणी:** हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर (इंडियन बाइसन), सांभर हिरण, आदि।
- **विशेष पारिस्थितिकी-तंत्र:** यहां मायारिस्टिका दलदल पाए जाते हैं। मायारिस्टिका दलदल ताजे जल के विशिष्ट पारिस्थितिकी-तंत्र हैं। इसमें मिरिस्टिका प्रजाति के वृक्षों का प्रभुत्व है (एक आदिम और सदाबहार वृक्ष प्रजाति), जो दक्षिणी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:** बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता।

5.6. मरीन हीटवेव्स (MARINE HEATWAVES)

मुख्तियों में क्यों?

नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 2023-24 की गर्मियों में मरीन हीटवेव्स (MHWs) के दिनों की औसत संख्या में **240 प्रतिशत** की वृद्धि हुई।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- पिछले दो वर्ष (2023-2024) **स्थल और महासागर** दोनों पर अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं।
- पूरे विश्व में मरीन हीटवेव्स की घटनाएं देखी गई हैं। **महासागरों के 8.8% भाग में** अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे अधिक **समुद्री सतही तापमान** दर्ज किया गया है।
- प्रचंड घटनाएं विशेष रूप से **उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण-पश्चिम प्रशांत, पूर्वी प्रशांत और पश्चिमी हिंद महासागर** में स्पष्ट रूप में देखी गईं।

मरीन हीटवेव (MHWs) क्या होती है?

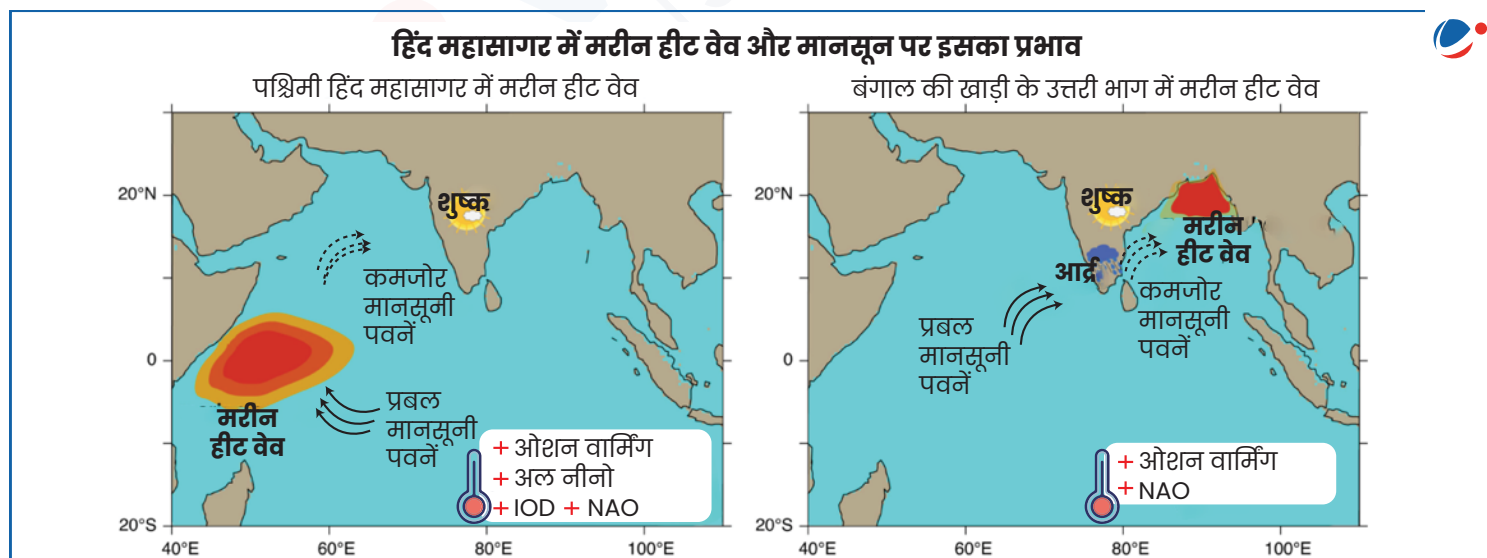
- यह तब घटित होती है, जब समुद्र के किसी क्षेत्र विशेष का सतही तापमान कम-से-कम **पांच दिनों तक औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक** बना रहता है।
- कोई **निश्चित तापमान** मरीन हीटवेव्स को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि महासागर का तापमान स्थान और समय के हिसाब से बदलता रहता है। इनका आमतौर पर तब पता चलता है जब समुद्री जल का तापमान पिछले माप की तुलना में अधिक गर्म होता है।
- MHWs की स्थिति **कई दिनों, हफ्तों, महीनों या यहां तक कि वर्षों तक** बनी रह सकती है।
- 1982** के बाद से समुद्री **MHWs की घटनाओं की संख्या** दोगुनी हो गई है।

समुद्री हीटवेव के कारक

- उच्च दाब प्रणालियों सहित **वायुमंडलीय और महासागरीय प्रक्रियाओं का संयोजन** मरीन हीटवेव्स का कारण बन सकते हैं।
- जब वायुमंडलीय उच्च दबाव प्रणालियां अधिक समय तक जल क्षेत्रों पर बनी रहती हैं, तो वे **सतही ऊष्मा प्रवाह** बढ़ाती हैं।
- अभिवहन:** समुद्री धाराओं द्वारा किसी क्षेत्र में गर्म समुद्री जल पहुंचाना।
- मानव-प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग:** महासागर ग्रीनहाउस गैसों से उत्सर्जित 90% अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित करते हैं।

समुद्री हीटवेव के प्रभाव

- जैविक प्रभाव:** प्रवाल विरंजन, केल्व फॉरेस्ट्स घास और प्रवाल भित्तियों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी-तंत्रों की क्षति।
- प्रभावित मौसम पैटर्न** की वजह से रिकॉर्ड तूफान और वर्षा।
- मरीन हीटवेव के कारण विशेष रूप से **उथले जल क्षेत्र के समुद्री जल में ऑक्सीजन की कमी**।
- भारत जैसे क्षेत्रों में **मानसूनी वर्षा के पैटर्न पर प्रभाव**।
- समुद्र के अम्लीकरण** में वृद्धि।
- जलीय कृषि, पर्यटन और मछली पकड़ने पर प्रभाव डालकर **आजीविका को नुकसान**।
- जल के तापीय विस्तार** के जरिए समुद्र के जलस्तर में वृद्धि।



मरीन हीटवेव से निपटने की रणनीतियां

- इसमें **कोरल्स को गहरे और ठंडे पानी में स्थानांतरित** करने जैसे पूर्व सक्रिय हस्तक्षेप।
- माल्पिकी को बंद करना और मछली पकड़ने की प्रथाओं को बदलने** सहित प्रतिक्रियात्मक हस्तक्षेप।

- लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए बाह्य-स्थाने संरक्षण विधियां।
- समुद्री बादल की चमक बढ़ाने जैसे जियो-इंजीनियरिंग हस्तक्षेप।
- पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन।
- तैयारी और प्रतिक्रिया योजना को सक्षम करने के लिए मरीन हीटवेव पूर्वानुमान विधि।

5.7. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA: GSI)

मुख्तियों में क्यों?

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की स्थापना के 175 वर्ष पूरे हुए।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के बारे में

- इसकी परिकल्पना जॉन मैक्लेडलैंड ने की थी। डेविड हीरॉ विलियम्स को 1846 में पहला भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था।
- 1851 में नए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक थॉमस ओल्डहम की नियुक्ति के बाद GSI द्वारा कार्यों की शुरुआत हुई थी।
- यह सर्वे ऑफ इंडिया (1767) के बाद भारत का दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण संगठन है।
- GSI को शुरू में रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया था। अब यह ख्याति प्राप्त भूविज्ञान संस्थान है।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- खान मंत्रालय से संबद्ध।

GSI के कार्य

- इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी जुटाना, उसे अपडेट करना और खनिज संसाधन का आकलन करना है।
- यह सर्वेक्षण, संसाधन मूल्यांकन, सूचना प्रसार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण को कवर करने वाले पांच मिशनों के तहत काम करता है।

GSI की उपलब्धियां

- 1877 में भारत का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र प्रकाशित किया और राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी की शुरुआत की।
- वर्तमान में 448 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें दुर्लभ भू-तत्व, लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी शामिल हैं।
- यह GNSS आधारित स्टेशनों का संचालन करता है और इसने भूकोष नामक भू-स्थानिक पोर्टल विकसित किया है।
- रिचर्ड डिकसन ओल्डम के अध्ययन की मदद से भूकंप के बारे में बेहतर समझ विकसित की और भूकंपीय तरंगों के तीन अलग-अलग प्रकारों की पहचान की।
- यह भूस्खलन के कारणों की जांच करने के संबंध में नोडल एजेंसी है। प्रोटोटाइप के रूप में अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित की है।
- यह अंटार्कटिका का अध्ययन करता है तथा भू-विरासत स्थलों और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है।
 - ➔ हाल ही में, GSI ने फ्यूचर मिनरल फोरम 2024 (सऊदी अरब) और 37वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस (साऊथ कोरिया) में भाग लिया है।

5.8. संक्षिप्त मुख्तियां (News in Shorts)

5.8.1. IUCN ग्रीन लिस्ट (IUCN GREEN LIST)

IUCN ग्रीन लिस्ट में चार नए स्थल जोड़े गए।

IUCN ग्रीन लिस्ट के बारे में

- इसमें सऊदी अरब का शरान नेचर रिजर्व और किंग अब्दुलअजीज रॉयल नेचर रिजर्व, जॉर्डन का अकाबा मरीन रिजर्व, और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का सिर बु नेर संरक्षित क्षेत्र शामिल है।
- यह प्रभावी, न्यायसंगत और सफल संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रमाणन से संबंधित वैश्विक कार्यक्रम है।
- संरक्षण संबंधी प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों को उजागर करना तथा प्रगति के लिए मानक निर्धारित करना।
- उद्देश्य: बेहतर तरीके से संरक्षित एवं प्रबंधित क्षेत्रों में वृद्धि करना और ऐसे संरक्षण संबंधी परिणाम पैदा करना जो SDG-15 तथा CBD आईसी लक्ष्य 11 को प्राप्त करने में मदद करते हैं।

5.8.2. 58वां टाइगर रिजर्व {58TH TIGER RESERVE (TR)}

मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।

- यह मध्य प्रदेश का नौवां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में रातापानी, वीरांगना दुर्गावती, संजय धुबरी, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच आदि शामिल हैं।

माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- अवस्थिति: यह चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले में भारत की मध्य उच्चभूमि के उत्तरी छोर पर स्थित है। मध्य उच्चभूमि ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का भाग है।
 - ➔ इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- झीलें: इसके दक्षिणी भाग में साख्य सागर और माधव सागर हैं।
- जीव-जंतु: नीलगाय, चिंकारा, मार्श क्रोकोडाइल, तेंदुआ, आदि।
- वनस्पति: उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन जिसमें करई वृक्ष अधिक पाए जाते हैं।

भारत में टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के अनुसार टाइगर रिजर्व अधिसूचित करती हैं।
- अधिसूचना में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:
 - राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होना;
 - NTCA विस्तृत विवरणों की मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देता है;
 - NTCA समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है;
 - राज्य सरकार संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करती है।

बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस)

- पर्यावास: उष्णकटिबंधीय वन, मैंग्रोव दलदल, घास के मैदान आदि।
- विशेषताएं: सभी एशियाई विडाल वंशियों में सबसे बड़ा। यह देखने की क्षमता और शिकार की हलचल एवं आवाज के जरिए शिकार करता है। यह प्रायः एकांतवासी जीव है। यह रात्रिचर प्राणी है और घात लगाकर शिकार करता है। यह अच्छा तैराक होता है।
- संरक्षण स्थिति: एंजेंड (IUCN); परिशिष्ट-I (CITES); अनुसूची-I {वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972}।

बाघों के संरक्षण के लिए भारत और वैश्विक प्रयास

- प्रोजेक्ट टाइगर: MoEFCC की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके तहत बाघों वाले राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
- कंज़र्वेशन असोसिएट टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA/TS): यह टाइगर रिजर्व के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। भारत के 23 टाइगर रिजर्व को यह मान्यता मिल चुकी है।
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस: इसे बिग कैट्स और उनके परिदृश्यों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत ने शुरू किया है।
- ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम: इसे विश्व बैंक ने बाघों के पर्यावासों को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। इसकी शुरुआत 2010 में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तत्वावधान में की गई थी।
- टाइगर अलाइव इनिशिएटिव: यह WWF का वन्य बाघों की संख्या को दोगुना करने का प्रयास है।

5.8.3. जैव विविधता विरासत स्थल {BIODIVERSITY HERITAGE SITES (BHS)}

कसमपट्टी सेक्रेड ग्रीव को तमिलनाडु का दूसरा BHS घोषित किया गया है। यह डिंडीगुल जिले में अलगमल्लै रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थित है।

जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) के बारे में

- BHS विशिष्ट पारिस्थितिकी-तंत्र है। यह अपने कुछ महत्वपूर्ण घटकों के साथ जैव-विविधता के मामले में समृद्ध होता है। यहां प्रजातियों की उच्च समृद्धता; उच्च स्थानिकता; दुर्लभ, स्थानिक और संकटग्रस्त प्रजातियां; कीस्टोन प्रजातियां आदि पाई जाती हैं।
- इन स्थलों को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37(1) के तहत अधिसूचित किया जाता है।
- राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव-विविधता महत्त्व वाले क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में BHS के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

5.8.4. संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट (UNITED NATIONS WORLD WATER DEVELOPMENT REPORT)

यूनेस्को द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में पारिस्थितिकी-तंत्र, पहाड़ों एवं अल्पाइन ग्लेशियर्स (वाटर टावर्स) की भूमिका का उल्लेख किया गया है।

पर्वतीय पारिस्थितिकी-तंत्र

- पारिस्थितिकी-तंत्र: वैश्विक पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर वन हैं तथा अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान और अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति है।
- जल विनियमन: दुनिया की दो-तिहाई सिंचित कृषि पहाड़ों से बहकर आने वाले जल पर निर्भर करती है।
- कार्बन भंडारण: पहाड़ी पर्माफ्रॉस्ट मिट्टी में लगभग 66 पेटाग्राम (Pg) जैविक कार्बन जमा होता है, जो वैश्विक मृदा जैविक कार्बन का 4.5% है।
- जैव विविधता: दुनिया के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से 25 पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें उच्च स्थानिक जैव विविधता पाई जाती है।

पर्वतीय पारिस्थितिकी-तंत्र की सुभेद्यताएं:

- ग्लेशियर्स की हानि: एंडीज (1980 के दशक से 30-50%) और हिंदू कुश हिमालय (2100 तक 50% अनुमानित) में तेजी से बर्फ पिघलना जल सुरक्षा के लिए खतरा है।
- वाटरमेलन स्नो इफेक्ट: ग्लेशियर्स की सतह पर होने वाला लाल शैवाल प्रस्फुटन इनके एल्विडो को कम करता है, जिसके कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है।
- शहरीकरण: यह जल विज्ञान चक्र को गंभीर रूप से बदलता है, जो संसाधनों के अत्यधिक दोहन का कारण बनता है और आपदाओं को बढ़ाता है।
- वायुमंडलीय प्रदूषण: लंबी दूरी तक पहुंचने वाले प्रदूषण के कारण बर्फ के कोर और झील की तलछट में ब्लैक कार्बन की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है।

हिंदू कुश हिमालय (HKH)

- यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा अल्पाइन पारिस्थितिकी-तंत्र है। इसकी औसत ऊंचाई 4,000 मीटर है और यह लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
- इसमें 1,00,000 वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा बर्फ भंडार है। ये 12,000+ झीलें और 10+ प्रमुख नदियों को जल प्रदान करते हैं।
- HKH, तिब्बती पठार, पामीर, हेंगडुआन, तिबेन शान और चिलियन पर्वत मिलकर "तीसरा ध्रुव" या "एशिया का जल स्तंभ" कहलाते हैं।

5.8.5. ग्लोबल एनर्जी रिव्यू (GLOBAL ENERGY REVIEW)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी 'ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, 2025' रिपोर्ट प्रकाशित की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- 2024 में वैश्विक ऊर्जा की मांग में 2.2% की बढ़ोतरी हुई। इसमें 80% से अधिक योगदान उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का रहा।
- 2024 में वैश्विक विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि में 80% नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का योगदान रहा। ऐसा पहली बार है जब कुल विद्युत उत्पादन में इनका योगदान 40% से अधिक रहा।

- 2019 से सोलर पी.वी. पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रिक कार और हीट पम्पस का उपयोग करने से **हर साल 2.6 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम** हुआ है, जो वैश्विक उत्सर्जन का **7%** है।

5.8.6. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 (WORLD AIR QUALITY REPORT, 2024)

IQAir ने **7वीं** वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 जारी की। यह रिपोर्ट **2024 में विश्व में वायु गुणवत्ता की स्थिति** का मूल्यांकन करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- केवल 7 देशों ने WHO की वार्षिक औसत PM2.5 गाइडलाइन को पूरा किया है। ये देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड।
- 2024 के 5 सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं: चाड > बांग्लादेश > पाकिस्तान > कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य > भारत।
 - दिल्ली अब भी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है।
- भारत का बर्नीहाट (असम) 2024 में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र रहा है।
- ओशिनिया विश्व का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है।

5.8.7. जलवायु कार्रवाई के लिए बजट (BUDGET FOR CLIMATE ACTION)

अहमदाबाद नगर निगम (AMC) अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना।

- AMC ने 2025-26 के बजट का एक-तिहाई हिस्सा जलवायु कार्रवाई के लिए निर्धारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा 2070 तक नेट-जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान को लागू करना है।
- इससे पहले, बृहन्मंबई नगर निगम (BMC) ने भी 33% पूंजीगत व्यय जलवायु-संबंधी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया था।

जलवायु बजटिंग के बारे में

- इसके तहत जलवायु प्रतिबद्धताओं को नीतियों, कार्यवाहियों और बजटीय आवंटन में प्रमुखता से शामिल किया जाता है।
- इसके तहत, शहरों की जलवायु कार्य योजना से जुड़े लक्ष्यों को बजट प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाता है।
- शहरों के लिए जलवायु बजट का महत्व:
 - यह जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हुए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विकास को बढ़ावा देता है।
 - इससे जलवायु वित्त की कमी की पहचान होती है तथा नवोन्मेषी जलवायु वित्त मॉडल्स को बढ़ावा मिलता है।

स्थानीय सरकार जलवायु वित्त के लिए तंत्र

- ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े बॉन्ड (जैसे, वडोदरा ग्रीन मुनि बॉन्ड)।
- स्थानीय सरकारों को प्रदर्शन-आधारित राजकोषीय हस्तांतरण (जैसे, UNCDF और LOCAL)।
- प्रदूषण और भीड़भाड़ शुल्क (जैसे, लंदन कंजेशन चार्ज और लो-एमिशन ज़ोन्स)।

5.8.8. 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विज़न (2030 GLOBAL FOREST VISION)

फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट ने '2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विज़न (GFV): प्रायोरीटी एक्शंस फॉर गवर्नमेंट्स इन 2025' रिपोर्ट जारी की।

- फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट (FDA) को 2015 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स (NYDF) प्रोग्रेस असेसमेंट के रूप में स्थापित किया गया था। NYDF लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करने के लिए नागरिक समाज के नेतृत्व में किया गया प्रयास है।
- NYDF को 2014 में सरकारों, कंपनियों, देशज लोगों और गैर-सरकारी संगठनों के गठबंधन द्वारा अपनाया गया था। साथ ही, 2014 के जलवायु शिखर सम्मेलन में इसका समर्थन किया गया था।
- NYDF स्वेच्छिक प्रकृति का है। इसके तहत 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत द्वारा अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया है।

2030 GFV के अंतर्गत आठ प्राथमिकता वाली कार्रवाइयां

- महत्वाकांक्षा: जलवायु एवं जैव विविधता योजनाओं और COP-30 परिणामों में वन लक्ष्यों को एकीकृत करना।
- व्यापार: कानूनी, निर्वनीकरण, और क्षरण-मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना।
- वित्त: परिणाम-आधारित भुगतान और कार्बन क्रेडिट के माध्यम से वनों के संरक्षण के लिए वित्त-पोषण को बढ़ाना।
- अधिकार: देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना।
- पर्यवेक्षण: वित्तीय संस्थानों द्वारा वन-संबंधी जोखिमों का आकलन व प्रबंधन करना।
- सब्सिडी: संधारणीय भूमि उपयोग का समर्थन करने के लिए हानिकारक सब्सिडी को स्थानांतरित करना।
- गवर्नेंस: भूमि-उपयोग क्षेत्र में गवर्नेंस को मजबूत करना तथा उसे वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ एकीकृत करना।
- ऋण: राष्ट्रीय ऋण रणनीतियों में वनों की प्राकृतिक पूंजी को शामिल करना।

5.8.9. अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट {ANTARCTIC CIRCUMPOLAR CURRENT (ACC)}

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2050 तक ACC में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आ सकती है।

ACC क्या है?

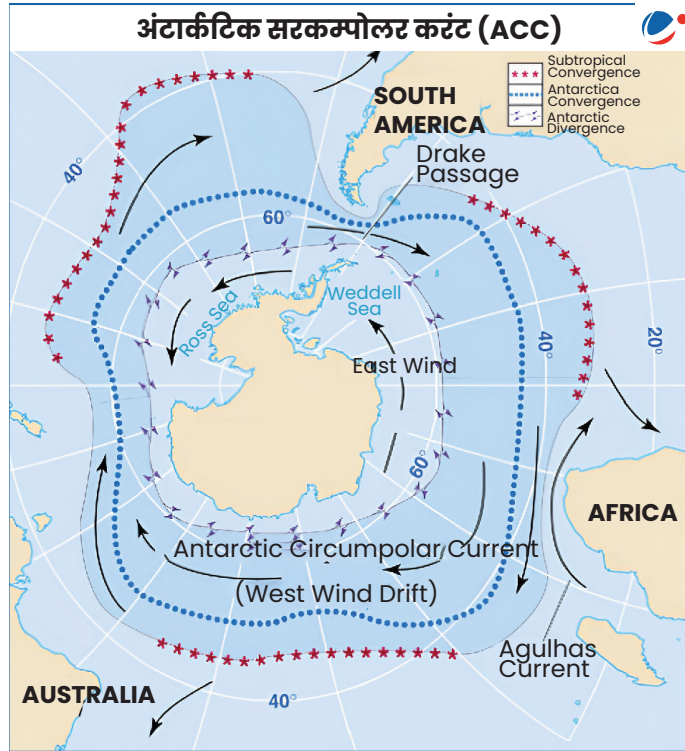
- यह पृथ्वी पर सबसे मजबूत पवन-चालित महासागरीय धारा है। यह अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमती है।
- यह एकमात्र महासागरीय धारा है, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों के जलों को जोड़ती है।
- यह गर्म जल को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकती है। यह ऊष्मा और CO2 के अवशोषण में बड़ी भूमिका निभाती है।

ACC के कमजोर होने के कारण

- महासागरीय लवणता में परिवर्तन: हिमखंड के तेजी से पिघलने की वजह से अंटार्कटिक बॉटम वॉटर (AABW) कमजोर हो जाता है।
- पवन के पैटर्न में परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा व वेग को बदल देता है।
- पॉजिटिव फीडबैक लूप: समुद्री बर्फ में कमी से वार्मिंग चक्र बनता है, जो ACC को और कमजोर करता है।

संभावित प्रभाव

- कुछ क्षेत्रों में अधिक चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तनशीलता में वृद्धि।
- महासागर की कार्बन अवशोषण क्षमता घटने से ग्लोबल वार्मिंग में तेजी।
- अंटार्कटिका तक पहुंचने वाली आक्रामक प्रजातियों से खाद्य जाल में व्यवधान।
- AABW के कमजोर होने से विश्व की महासागरीय धाराओं की परिसंचरण प्रणाली पर प्रभाव।



5.8.10. अंटार्कटिका में गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी-तंत्र की खोज की गई (DEEP-SEA ECOSYSTEMS DISCOVERED IN ANTARCTICA)

जॉर्ज VI आइस शेल्फ से हिमखंड के अलग होने के बाद अंटार्कटिका में समृद्ध गहरे समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र की खोज हुई।

- यह खोज चैलेंजर 150 पहल के तहत की गई है। इस पहल को महासागर दशक कार्रवाई (2021-2030) के हिस्से के रूप में यूनेस्को/ अंतर-सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग (IOC) से समर्थन प्राप्त है।

इस खोज के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- समृद्ध पारिस्थितिकी-तंत्र: 1,300 मीटर (मेसोपेलैजिक जोन) की गहराई पर बड़े कोरल और स्पंज वाले पारिस्थितिकी-तंत्र मौजूद हैं। ये आइसफिश और जायंट सी स्पाइडर्स जैसे विविध जीवों का समर्थन करते हैं।
 - ये पारिस्थितिकी-तंत्र सदियों से 150 मीटर मोटी बर्फ के नीचे अलग-थलग अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये सतही पोषक तत्वों से पूरी तरह कटे हुए थे।
- खोजी गई नई प्रजातियाँ: जायंट सी स्पाइडर्स, ऑक्टोपस, जायंट फैंटम जेलीफिश (1 मीटर तक के आकार वाली), फूलदान के आकार का स्पंज (संभवतः सैकड़ों वर्ष पुराना) आदि।

गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी-तंत्र के बारे में

- परिभाषा:** ये समुद्र में 200 मीटर से अधिक गहरे क्षेत्र या समुद्र नितल होते हैं। इसे अप्रकाशी/ एफोटिक जोन कहा जाता है। ये कुल समुद्री क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा हैं। ये पृथ्वी के सबसे बड़े बायोम भी हैं।
- गहरे समुद्री पर्यावास और जैव विविधता संबंधी अनूठी विशेषताएं:**
 - विशाल सागर नितल मैदान:** ये प्रकाश रहित क्षेत्र हैं। यहां मौजूद प्रजातियां जीवित रहने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण के लिए- समुद्री खीरा।
 - हाइड्रोथर्मल वेंट्स:** ये खनिज युक्त टावर हैं। यहां पाई जाने वाली प्रजातियां जीवित रहने के लिए रसायन-संश्लेषक बैक्टीरिया पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण के लिए- ब्लूबर्म और येति क्रेब्स।
 - ढेल फॉल्स:** जब ढेल का मृत शरीर समुद्र की गहराई में डूबता है, तो यह अस्थायी पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए: हैगफिश।

गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी-तंत्र का अवलोकन

जैव विविधता का अनुकूलन

- बायोल्यूमिनेसेंस:** कुछ प्रजातियाँ शिकार, साथी को आकर्षित करने या शिकारियों को भ्रमित करने के लिए प्रकाश उत्पन्न करती हैं।
- ऊर्ध्वधर प्रवास:** जूप्लैक्टन और मछलियां प्रतिदिन ऊपर-नीचे जाती हैं। रात में सतह पर भोजन करती हैं और दिन में गहरे समुद्र में वापस लौट जाती हैं।
- धीमा चयापचय:** भोजन की कमी वाले क्षेत्रों में जीव बहुत कम ऊर्जा में जीवित रहते हैं।

महत्त्व

- जलवायु विनियमन:** गर्म और ठंडे समुद्री जल के मिश्रण (थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन) के माध्यम से पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करता है, जिससे वैश्विक जलवायु पर असर पड़ता है।
- कार्बन भंडारण:** विशाल सागर नितल मैदान में 5 किमी मोटी कार्बन युक्त परतें होती हैं, जो कार्बन को पृथ्वी में लंबे समय तक संचित करने में मदद करती हैं।

5.8.11. ओकजोकुल/ ओह-युकुल ग्लेशियर (OKJÖKULL GLACIER)

यह पहला ग्लेशियर है, जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक रूप से पूर्णतया विलुप्त घोषित किया गया है।

- 2014 में आइसलैंड के ओह-युकुल ग्लेशियर को डेड (मृत) घोषित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना कम हो गया था कि इसकी आगे की और बढ़ने की गति रुक गई थी।
- अन्य ग्लेशियर जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है: एंडरसन ग्लेशियर, क्लार्क ग्लेशियर और ग्लिसन ग्लेशियर (संयुक्त राज्य अमेरिका); बाउमन ग्लेशियर (न्यूजीलैंड); काल्डेरोन ग्लेशियर (इटली) आदि।

ग्लेशियर के बारे में

- ग्लेशियर बर्फ और हिम का एक विशाल व बारहमासी संचय होता है। यह अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढलान की दिशा में आगे बढ़ता रहता है।
- ग्लेशियर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु के करीब होता है और शीत ऋतु में वर्षण से अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है।

ग्लेशियरों का महत्त्व:

- **जल भंडार:** ग्लेशियरों में पृथ्वी के लगभग **तीन-चौथाई ताजे जल** का भंडारण मौजूद है।
- **खाद्य प्रणालियाँ:** कृषि भूमि के लिए **सिंचाई और उर्वरता** का स्रोत है।
- **जैव विविधता:** जलीय पारिस्थितिकी-तंत्रों को पोषक तत्व पहुँचाते हैं, तथा पादपल्लवकों और खाद्य श्रृंखलाओं का समर्थन करते हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने के प्रभाव

- **जल चक्र में व्यवधान:** ताजे जल की उपलब्धता और पारिस्थितिकी-तंत्र व कृषि के समक्ष खतरा।
- **प्राकृतिक आपदाएँ:** हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से आने वाली बाढ़ और हिमस्खलन का खतरा।
- **समुद्री जल स्तर में वृद्धि:** तटीय कटाव, पर्यावास की क्षति, जैव विविधता हानि आदि।
- **क्लाइमेट फीडबैक लूप:** पृथ्वी की सतह के एल्बिडो में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि।

ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें

- **वैश्विक:** संयुक्त राष्ट्र ने **2025 को 'ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष'** घोषित किया तथा यूनेस्को अंतर-सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम आदि।
- **भारत:** नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र, हिमांश (HIMANSH) अनुसंधान केंद्र आदि।

5.8.12. नरव्हेल (NARWHAL)

हाल ही में **नरव्हेल** का पहली बार उनके '**टस्किंग बिहेवियर**' के लिए अध्ययन किया गया।

नरव्हेल के बारे में

- **नरव्हेल** का एक लंबा टस्क होता है, जो वास्तव में दांत है।
- नर के टस्क होता है, जबकि आमतौर पर मादा के पास टस्क नहीं होता है। हालांकि, यह आम लक्षण नहीं है। कुछ मादाओं में छोटा टस्क देखा गया है, वहीं कुछ नर में टस्क होता ही नहीं है। **कुछ नरव्हेल में दो-दो टस्क** रिकॉर्ड किए गए हैं।
- **टस्क के उपयोग:** जल में लवणता और तापमान का पता लगाने में सहायक होता है, शिकार करने और पर्यावरण में बदलाव के अनुसार ढलने में मदद करता है आदि।
- **वैज्ञानिक नाम:** **मोनोडोन मोनोसेरोस**। इसका अर्थ है: **एक टस्क और एक सींग वाली व्हेल**।
- **पर्यावास क्षेत्र:** कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस में फैला आर्कटिक जल।
- **IUCN रेड लिस्ट स्थिति:** लीस्ट कंसर्न।
- **जीवनकाल:** मादा लगभग **100 वर्ष**, जबकि नर लगभग **84 वर्ष**।
- **प्रजनन:** गर्भकाल (**लगभग 13 से 16 महीने**)।

5.8.13. ब्लू फ्लैग (BLUE FLAG)

रुशिकोंडा बीच ने फिर से ब्लू फ्लैग टैग हासिल किया। ज्ञातव्य है कि **खराब रखरखाव के कारण रुशिकोंडा से यह टैग वापस ले लिया** गया था।

- यह **आंध्र प्रदेश** का एकमात्र **ब्लू फ्लैग बीच** है। यह **भारत के 13 ब्लू फ्लैग बीचों** में शामिल है।

ब्लू फ्लैग टैग के बारे में

- **कैसे दिया जाता है:** इसे समुद्र तटों, मरीनों और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक **श्रेणी के लिए अलग-अलग मानक** होते हैं।
- **प्रदाता:** डेनमार्क स्थित **फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE)** द्वारा।
- **मानदंड:** कठोर **पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और अभिगम्यता मानदंडों** की एक श्रृंखला को पूर्ण करना तथा बनाए रखना आवश्यक है।

"You are as strong as your Foundation"

FOUNDATION COURSE

GENERAL STUDIES

PRELIMS CUM MAINS

2026, 2027 & 2028

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam

- Includes Pre Foundation Classes
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2026, 2027 & 2028

**DELHI: 7 MAY, 8 AM | 8 MAY, 11 AM | 16 MAY, 5 PM
20 MAY, 11 AM | 21 MAY, 2 PM | 29 MAY, 8 AM**

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 20 MAY, 11 AM | 27 MAY, 6 PM

हिन्दी माध्यम DELHI: 27 मई, 11 AM

AHMEDABAD: 7 JUNE BENGALURU: 28 MAY BHOPAL: 26 MAY CHANDIARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 11 JUNE JAIPUR: 10 MAY, 18 MAY JODHPUR: 15 MAY LUCKNOW: 19 MAY PUNE: 8 MAY

Live - online / Offline Classes

Scan the QR CODE to download VISION IAS app



ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव
असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र



2025	ENGLISH MEDIUM 23 MARCH	हिन्दी माध्यम 23 मार्च
2026	ENGLISH MEDIUM 11 MAY	हिन्दी माध्यम 11 मई

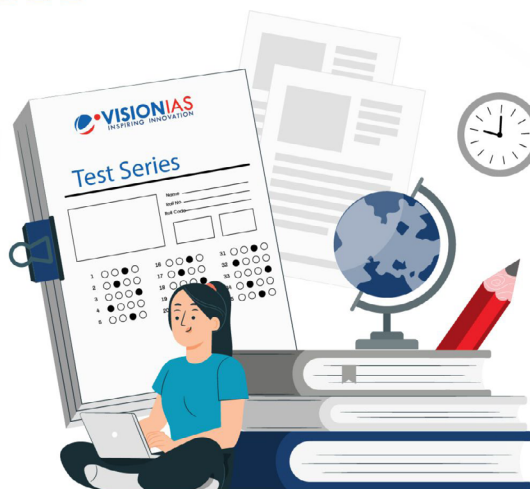


ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर
प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट
15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

2026	ENGLISH MEDIUM 11 MAY	हिन्दी माध्यम 11 मई
-------------	--	--------------------------------------



सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)



6.1. सिनेमा और समाज (Cinema and Society)

मुख्तियों में क्यों?

हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मीडिया में वायलेंट कंटेंट (हिंसा फैलाने वाले कंटेंट) का समाज पर प्रभाव गहरा हो सकता है, परंतु इससे निपटने के लिए उठाए गए किसी भी कदम को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

सिनेमा के बारे में

- सिनेमा **जन-संचार का एक लोकप्रिय माध्यम** है, जिसे **"सातवीं कला (सेवंथ आर्ट)"** के रूप में भी जाना जाता है।
 - ➔ कला के अन्य 6 रूप हैं- चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्यकला, साहित्य, रंगमंच और संगीत।
- **विविध कलात्मक और सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से**, भारतीय सिनेमा व्यक्तिगत और सामाजिक, दोनों तरह की धारणाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करती है।

भारतीय सिनेमा का विकास (1950 के दशक से 2025 तक)

- **1950-60 का दशक:** सामाजिक यथार्थवाद और राष्ट्रवाद
- **1970 का दशक:** सामाजिक अन्याय, समानांतर सिनेमा और सामाजिक व्यंग्य
- **1990 का दशक:** वैश्वीकरण, भौतिकवाद और पहचान, पितृसत्ता और सुधार, रिश्ते और व्यक्तित्व
- **2000 के दशक की शुरुआत:** यथार्थवाद, वैश्वीकरण और पहचान, सामाजिक मुद्दे
- **2020 के बाद:** OTT सिनेमा और क्षेत्रीय सिनेमा

फिल्में समाज को किस प्रकार दिशा दिखाती हैं?

भारतीय समाज पर सिनेमा का सकारात्मक प्रभाव

- भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने में
- सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब: **डेढ़ इश्किया** जैसी फिल्मों लखनऊ की नवाबी संस्कृति को दर्शाती हैं।
- विकसित होते पारिवारिक मूल्यों का प्रतिबिंब
- महिला सशक्तिकरण: **दुर्गा सहाय** जैसी फिल्मों
- शिक्षा के प्रति जागरूकता
- सामाजिक परिवर्तन के लिए सशक्त साधन: जागरूकता बढ़ाना, सामाजिक सोच को बदलना, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को आकार देना

भारतीय समाज पर सिनेमा का नकारात्मक प्रभाव

- लिंग रुढ़िवादिता और प्रभुत्व वाली पुरुषवादी सोच
- अवास्तविक शारीरिक मानकों को बढ़ावा देना: यह **बॉडी शेमिंग** को भी बढ़ावा देता है
- परिवार की संस्था पर सवाल उठाना: सिनेमा में अक्सर प्रेम विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है।
- सांस्कृतिक प्राथमिकताओं में बदलाव: सिनेमा का शास्त्रीय नृत्य शैलियों के स्थान पर पश्चिमी नृत्य शैलियों पर बढ़ता फोकस।
- कमजोर समुदायों की संवेदनहीन प्रस्तुति:
- नशे के सेवन का महिमामंडन
- समाज में विभाजन को बढ़ावा देना: दुष्प्रचार वाली फिल्मों तेजी से किसी खास राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दे रही हैं।

सिनेमा में कंटेंट की निगरानी पर नियम और कानून

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** अश्लील कृत्यों को अपराध घोषित करती है, और इसके लिए जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

- ➔ **स्त्री अश्लिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986:** यह कानून प्रकाशनों, विज्ञापनों और मीडिया में महिलाओं के अभद्र रूप से चित्रण करने पर रोक लगाता है।
- ➔ **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995:** यह सुनिश्चित करता है कि प्रसारित कार्यक्रम सामाजिक मर्यादा के मानकों के अनुरूप हों, तथा इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है।
- ➔ **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952:** यह फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित करना अनिवार्य करता है।
- ➔ **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI):** यह एक स्व-विनियामक संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि विज्ञापन सार्वजनिक मर्यादा के मानकों का पालन करें।

6.2. सोशल मीडिया और किशोर (Social Media and Adolescents)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज **“एडोलेसेंस (Adolescence)”** ने वैश्विक स्तर पर **ऑनलाइन कट्टरपंथवाद और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किशोरों की सुरक्षा** को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी गई है। यह उन ज्वलंत मुद्दों को उजागर करती है, जिनका सामना बच्चे इंटरनेट के अनियंत्रित प्रभाव और उससे उत्पन्न सामाजिक परिणामों के चलते कर रहे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ➔ यूनाइटेड किंगडम अपने स्कूलों में इस वेब सीरीज को दिखाने की योजना बना रहा है, जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए डिस्कशन गाइड्स भी शामिल होंगे।
- ➔ 2024 में, **ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध** लगा दिया है।

ऑनलाइन स्पेस/ सोशल मीडिया का किशोरों पर हानिकारक प्रभाव

- ➔ **नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग:** उदाहरण के लिए, **अश्लील कंटेंट व महिलाओं के प्रति नफरत फैलाने वाले कंटेंट गुस्सा और नफरत** को बढ़ावा देते हैं; **‘अच्छे दिखने के स्टैंडर्ड’ वाले कंटेंट से किशोरों में खुद को छोटा समझने का भाव उत्पन्न हो सकता है;** आदि।
- ➔ **ऑनलाइन कट्टरपंथवाद:** उदाहरण के लिए, **“मैनोस्फीयर” से जुड़े चैट फोरम, जो नारीवादी विचारधारा के जवाब में महिलाओं के प्रति नफरत और प्रभुत्व वाली पुरुषवादी सोच को उचित ठहराते हैं।**
- ➔ **सोशल मीडिया की लत और अलगाव:** ऑनलाइन स्पेस का लंबे समय तक इस्तेमाल बच्चों को **वास्तविक दुनिया से अलग कर देता है।**
- ➔ **मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का जन्म:** चिंता, अवसाद और बॉडी इमेज को लेकर चिंता।
- ➔ **सहानुभूति की कमी और साइबर-बुलिंग:** उदाहरण के लिए, **दिल्ली में “बॉयज़ लॉकर रूम” की घटना (2020)** जिसमें स्कूली लड़कों के एक ग्रुप में आपत्तिजनक इमेजेज साझा किए गए थे।

अलग-अलग हितधारक किशोर-किशोरियों के व्यक्तित्व निर्माण में कैसे भूमिका निभाते हैं?

- ➔ **सहकर्मी:** मूल्य, व्यवहार
- ➔ **सामाजिक:** परिवार, समाज
- ➔ **संस्थागत:** इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्कूल, सरकारें

किशोरों पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को रोकने में चुनौतियां?

- ➔ **अप्रासंगिक हो गई नीतियां:** डिजिटल क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव नीतियों में सुधारों की गति से कहीं आगे निकल गए हैं।
- ➔ **डिजिटल साक्षरता का अभाव**
- ➔ **कंटेंट मॉडरेशन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नियम-कानून के दायरे में लाना **विवादास्पद** बना हुआ है, मुख्य रूप से इस तर्क के कारण कि इस तरह का रेगुलेशन **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर** करता है।
- ➔ **कंटेंट मॉडरेशन में खामियां:** किसी कंटेंट को बच्चों के लिए प्रतिबंधित करने से भी कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चे डार्क वेब, पाइरेसी आदि के जरिए इस कंटेंट तक पहुंच सकते हैं।
- ➔ **अलग-अलग पीढ़ियों के बीच डिजिटल डिवाइड:** किशोर नई तकनीकों को जल्दी अपना लेते हैं, जबकि बड़े लोग विरोध कर सकते हैं या गलत समझ सकते हैं।
- ➔ **जागरूकता की कमी**

आगे की राह

- ➔ **किशोरों के बीच डिजिटल सिटीजनशिप को बढ़ावा देना:** जब आप इंटरनेट का उपयोग **कानूनी, सुरक्षित, सम्मानजनक तरीके** से करते हैं।
- ➔ **डिजिटल एथिक्स ऑफ़ केयर:** डिजिटल रिस्पॉसिबिलिटी, डिजिटल एम्पथी, डिजिटल केयर एंड काइंडनेस, डिजिटल रेस्पेक्ट।
- ➔ **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना**
- ➔ **माता-पिता की निगरानी**
- ➔ **स्कूल प्रणाली में सुधार:** उदाहरण के लिए, **यू.के. की तरह संबंधों, सेक्स और स्वास्थ्य शिक्षा (RSHE)** को पाठ्यक्रम में शामिल करना।
- ➔ **नीतिगत सुधार:** बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना, शिक्षा नीतियां, किशोर न्याय कानून।
- ➔ **टेक कंपनियों के लिए जवाबदेही तय करना।**

6.3. पारिवारिक संस्था में बदलाव (Changing Institution of Family)

मुख्तियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि **पारिवारिक मूल्य क्षीण हो रहे हैं**, क्योंकि **माता-पिता और बच्चे** संपत्ति और भरण-पोषण के मामलों को लेकर **एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाज़ी कर रहे हैं**। इससे देश **“एक व्यक्ति, एक परिवार”** मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जो कि **“वसुधैव कुटुंबकम्”** की भावना के विपरीत है।

भारत में बदलती परिवार संस्था

पहलू	पारंपरिक परिवार	नवीन प्रवृत्तियां
संरचना	संयुक्त परिवार प्रणाली जिसमें दादा-दादी, चाचा-चाची, भतीजे-भतीजियां सहित कई पीढ़ियां एक ही घर में एक साथ रहती हैं।	मुख्यतः एकल परिवार , जिसमें केवल माता-पिता और गैर-वयस्क बच्चे ही शामिल होते हैं।
निर्णय लेना	पितृसत्तात्मक पदानुक्रम , जिसमें निर्णय सामूहिक रूप से बुजुर्गों द्वारा लिए जाते हैं।	अब अधिक समतामूलक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जहां पुरुष और महिलाएं मिलकर निर्णय लेती हैं।
विवाह प्रथाएं	बुजुर्गों द्वारा तय की जाने वाली पारंपरिक विवाह प्रणाली; वंश और पारिवारिक एकता पर बल ।	प्रेम विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और समलैंगिक संबंधों जैसे गैर-पारंपरिक संबंधों की स्वीकार्यता बढ़ी है।
जीवन मूल्य	सामूहिकता पर बल : परिवार की वफादारी, एकता, परस्पर निर्भरता ।	गोपनीयता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर ध्यान ; व्यक्तिवादिता में वृद्धि ।

भारतीय परिवार संस्था में बदलाव के कारक

- ➔ **आर्थिक कारक**: शहरीकरण, श्रम बाजार की बढ़ती मांग आदि।
- ➔ **लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन**: महिलाओं की शिक्षा और औपचारिक रोजगार के अवसरों तक पहुंच में सुधार।
- ➔ **पाश्चात्य प्रभाव**: अब लोग **छोटे और निजता-प्रधान परिवारों को अधिक महत्त्व** देने लगे हैं।
- ➔ **वैश्वीकरण**: उदाहरण के तौर पर, **बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) की कार्य संस्कृति** छोटे और लचीले पारिवारिक ढांचे को बढ़ावा देती है।
- ➔ **तकनीक की भूमिका**: Skype, WhatsApp जैसे आधुनिक संचार माध्यमों ने दूर रहते हुए भी संपर्क बनाए रखने में मदद की है, लेकिन ये पारिवारिक संबंधों की गहरी और भावनात्मक निकटता को प्रभावित किया है।

पारिवारिक संस्था में बदलाव के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- ➔ **सक्रिय पालन-पोषण**: पिता अब बच्चों के पालन-पोषण में पहले से कहीं अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
- ➔ **माता-पिता और बच्चों के बीच मजबूत संबंध**
- ➔ **पारिवारिक संघर्ष में कमी**
- ➔ **अधिक स्वायत्तता**: व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं को स्वतंत्र तरीके से जीवन व्यतीत करने का अवसर।

नकारात्मक प्रभाव

- ➔ **अंतर-पीढ़ीगत संघर्ष**
- ➔ **पारंपरिक मूल्यों की हानि**
- ➔ **अकेलापन**: बच्चों में, माता-पिता में
- ➔ **सामाजिक अवसरचना पर दबाव**: संस्थागत तरीके से बुजुर्ग देखभाल, बाल देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहायता की अधिक मांग।

आगे की राह

- ➔ **समुदाय-आधारित समर्थन प्रणालियों को मजबूत करना**: पड़ोस-आधारित बेहतर बुजुर्ग देखभाल सेवाएं, बाल देखभाल केंद्र (क्रेच) और मानसिक कल्याण केंद्र स्थापित करना। **उदाहरण: केरल का कुदुम्बश्री नेटवर्क** समुदाय और देखभाल अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है।
- ➔ **शिक्षा और सामाजिक जागरूकता**
- ➔ **शहरी नियोजन के माध्यम से अंतर-पीढ़ीगत जीवन को बढ़ावा देना**
- ➔ **परिवार की अवधारणा को पुनः परिभाषित करना**: राज्यों की नीतियों और शासन संरचनाओं को पारंपरिक परिभाषा से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
- ➔ **नीतिगत दृष्टिकोण**: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के **भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007** का प्रभावी कार्यान्वयन। साथ ही, **बुजुर्गों के लिए / निःशुल्क कानूनी सहायता**।

6.4. महिलाओं के नेतृत्व में विकास (WOMEN-LED DEVELOPMENT)

मुख्तियों में क्यों?

हाल ही में, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 30वीं वर्षगांठ पर, विश्व भर की सरकारों ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण पर एक घोषणा-पत्र अपनाया। यह घोषणा-पत्र महिलाओं के नेतृत्व में विकास के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BPfA) के बारे में

- इसे मूल रूप से 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। इसमें बिना किसी अपवाद के हर महिला और लड़की के लिए सभी प्रकार के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बनाए रखने पर जोर दिया गया था।
- इसकी 30वीं वर्षगांठ पर, बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित 6 प्रमुख प्राथमिकताएं शामिल थीं:
 - ➔ डिजिटल क्रांति: नए कौशल की प्राप्ति, डिजिटल डिवाइड को दूर करना, आदि।
 - ➔ गरीबी से मुक्ति: सामाजिक सुरक्षा तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा और केयर) प्रदान करना।
 - ➔ हिंसा की समाप्ति: समुदाय-आधारित संगठनों को शामिल करते हुए व्यापक राष्ट्रीय कार्ययोजनाएं अपनाना।
 - ➔ निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण और समान शक्ति: निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में।
 - ➔ शांति और सुरक्षा: लिंग-संवेदनशील मानवीय कार्य।
 - ➔ क्लाइमेट जस्टिस: आदिवासी समुदायों की महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देना, ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देना, आदि।

महिलाओं का विकास बनाम महिलाओं के नेतृत्व में विकास

महिलाओं का विकास	महिलाओं के नेतृत्व में विकास
➤ इसमें महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है, हालांकि इन योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है। ➤ इसके तहत महिलाओं को विकास कार्यक्रमों के केवल लाभार्थी के रूप में देखा जाता है। ➤ टॉप-डाउन अप्रोच।	➤ इसमें महिलाओं को न केवल लाभार्थी के रूप में देखा जाता है, बल्कि विकास-प्रक्रिया के लीडर, नीति-निर्माता और इनोवेटर के रूप में भी देखा जाता है। ➤ यह माना जाता है कि महिलाओं के पास विशिष्ट अंतर्दृष्टि होती है। ➤ बॉटम-अप अप्रोच।

‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास’ समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- सशक्तीकरण की प्रतिनिधि के रूप में महिलाएं।
- लैंगिक समानता: ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024: भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर है।
- आर्थिक सशक्तीकरण: रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से देश की GDP में 30% तक की वृद्धि की जा सकती है।
- ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन: दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने से उनकी घरेलू आय में 22% की वृद्धि हुई।
- समावेशी विकास और स्थिरता: डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने लगभग 5,000 दलित और आदिवासी महिला लघु किसानों के साथ सहयोग किया।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की राह में मुख्य चुनौतियां

- पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड: NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, केवल 3% महिलाएं ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं।
- शिक्षा: वैश्विक स्तर पर महिलाओं की औसत साक्षरता दर 79.9% है, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे (62.3%) है।
- कार्यस्थल पर भेदभाव: विश्व आर्थिक मंच (WEF) की जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 के अनुसार समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 20% कम वेतन प्राप्त होता है।
- लैंगिक डिजिटल डिवाइड: भारत में केवल 15% महिलाओं की ही इंटरनेट तक पहुंच है (मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021)।
- बाल विवाह और मातृत्व की जिम्मेदारी: NFHS-5 के अनुसार, 20-24 वर्ष के आयु वर्ग की 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गई थी।
- महिलाओं की सुरक्षा: NCRB की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए।

सरकार की पहल: महिला सशक्तीकरण से महिला-नेतृत्व वाले विकास तक

- जेंडर बजटिंग: कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट हेतु आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 में 8.86% तक बढ़ गया है, जो 2024-25 में 6.8% था।
- संपत्ति का स्वामित्व: पी.एम. आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 72% घरों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।
- राजनीतिक सशक्तीकरण: नारी शक्ति अधिनियम के तहत लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण का प्रावधान।
- शिक्षा और STEM का प्रचार: भारत में 43% STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) स्नातक महिलाएं हैं।
- उद्यमिता और कौशल विकास: स्टार्ट-अप और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं; महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और महिला प्रौद्योगिकी पार्कों (WIPs) की स्थापना।
- आर्थिक सशक्तीकरण: मुद्रा योजना, लखपति दीदी, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी योजनाएं।

6.5. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

6.5.1. संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने न्यूनतम आहार विविधता (MDD) के लिए नया SDG संकेतक अपनाया {NEW SDG INDICATOR ON MINIMUM DIETARY DIVERSITY (MDD) ADOPTED BY UN STATISTICAL COMMISSION}

FAO और यूनिसेफ (UNICEF) संयुक्त रूप से इस नए संकेतक का प्रबंधन करते हैं। यह संकेतक स्वस्थ आहार के मामले में SDG की प्रगति को ट्रैक करने में आ रही कमी को दूर करेगा।

- ➔ यह संकेतक उन पहलुओं पर ध्यान देगा, जो कुपोषण को समाप्त करने और SDG-2 को हासिल करने तथा व्यापक एजेंडा 2030 की प्रगति को ट्रैक करने हेतु उपलब्ध नहीं थे।
- ➔ SDG-2: भुखमरी को समाप्त करना।

न्यूनतम आहार विविधता (MDD) के बारे में

- ➔ WHO के अनुसार, न्यूनतम आहार विविधता को तब हासिल किया जा सकता है जब आहार में निम्नलिखित 8 खाद्य समूहों में से 5 या उससे अधिक शामिल हों:
 - ➔ माता का दूध; अनाज; फलियां; डेयरी उत्पाद; मांस खाद्य पदार्थ; अंडे; फल और सब्जियां तथा विटामिन A से भरपूर फल और सब्जियां। 5 से कम खाद्य समूहों से आहार का सेवन न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF) माना जाता है।

न्यूनतम आहार विविधता (MDD) संकेतक का महत्व

- ➔ पोषण का बेहतर आकलन: यह विशेष रूप से महिलाओं (MDD-W) और बच्चों (MDD-C) की पोषण संबंधी जरूरतों को ट्रैक करती है।
- ➔ वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को ट्रैक करना: यह SDG-2 का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य भुखमरी को समाप्त करना और पोषण में सुधार करना है।
- ➔ नीति संबंधी साधन: नीति निर्माताओं को कुपोषण से निपटने के लिए रणनीतियां विकसित करने में मदद करती है।
- ➔ पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन: यह पोषण संबंधी पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करती है।

भारत में न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF) की स्थिति (वर्ष 2019-21):

- ➔ क्षेत्रीय असमानताएं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 80% से अधिक बच्चे MDDF से पीड़ित हैं।
- ➔ MDDF पर आयु का प्रभाव: 6-23 महीने आयु वर्ग के 77% बच्चों में उच्च आयु समूहों की तुलना में MDDF की व्यापकता सबसे अधिक है।
- ➔ कमजोर वर्ग: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बच्चों में सबसे ज्यादा MDDF (79%) है। उसके बाद अनुसूचित जाति (77.2%) और अनुसूचित जनजाति (76%) का स्थान है।

6.5.2. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WORLD HAPPINESS REPORT)

यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल्बीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UN-SDSN) और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ मिलकर प्रकाशित की है।

रिपोर्ट के बारे में

- ➔ यह रिपोर्ट केंद्रिल सेल्फ-एंकरिंग स्ट्राइविंग स्केल (केंद्रिल लैडर) से प्राप्त एक प्रश्न पर आधारित है।
 - ➔ स्केल का सबसे ऊपरी हिस्सा 'बहुत खुशहाल जीवन' को दर्शाता है, जबकि स्केल का सबसे नीचे वाला हिस्सा 'बिल्कुल भी खुशहाल नहीं' जीवन को दर्शाता है।
- ➔ रैंकिंग के लिए अपनाए गए मापदण्ड: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, आदि।
- ➔ सबसे खुशहाल देश: फिनलैंड (पहला स्थान), इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान है।
- ➔ भारत का स्थान: 147 देशों में से 118वां स्थान।

6.5.3. स्वावलंबिनी (SWAVALAMBINI)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी - महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है।

स्वावलंबिनी-महिला उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में

- ➔ यह लैंगिक रूप से समावेशी उद्यमिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- ➔ उद्देश्य: इस कार्यक्रम का लक्ष्य उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल, संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उन्हें सक्षम बनाना है।
- ➔ संरचना: इसमें उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, मार्गदर्शन और फैकल्टी ट्रेनिंग भी शामिल हैं।
- ➔ कार्यान्वयन निकाय: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान।
- ➔ प्रभाव: इसका लक्ष्य प्रशिक्षित प्रतिभागियों में से 10% को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे भारत में महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

6.5.4. पीएम-युवा 3.0 (PM-YUVA 3.0)

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम-युवा 3.0 (यंग, अपकमिंग और वर्सटाइल ऑथर्स) लॉन्च किया।

पीएम-युवा 3.0 के बारे में

- ➔ उद्देश्य: 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और नवोदित लेखकों को पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित करना।
- ➔ चयन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया: अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 50 लेखकों का चयन किया जाएगा।
- ➔ कार्यान्वयन एजेंसी: नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी है जो व्यवस्थित मार्गदर्शन सुनिश्चित करती है।
- ➔ महत्व: सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करता है।

6.5.5. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE: IOC)

जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक **क्लिस्टी कोवेंद्री** IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।

→ IOC एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र निकाय है, जो ओलंपिक गतिविधियों का प्रबंधन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के बारे में

→ मुख्यालय: लॉज़ेन (ओलंपिक राजधानी), स्विट्जरलैंड।

→ उत्पत्ति: पेरिस में आयोजित प्रथम ओलंपिक कांग्रेस में स्थापित (1894)।

→ विज़न: खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना।

→ वित्त-पोषण: पूर्णतः निजी तौर पर वित्त-पोषित तथा अपने राजस्व का 90% सभी स्तरों पर खेलों एवं एथलीटों के विकास के लिए वितरित करता है।

→ कार्य:

→ ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने वाले खेलों और मेजबान शहर के चयन का निर्णय लेना।

→ एथलीटों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (NOCs) और खेल महासंघों सहित ओलंपिक हितधारकों के बीच सहयोग को सुगम बनाना।

♦ भारतीय ओलंपिक संघ (IOC) भारत के NOC के रूप में कार्य करता है।



लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2026

प्रारंभ: 19 मई

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 16 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 25,000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए
रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु
15.5 माह का कार्यक्रम)



- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय-वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN



/VISION_IAS



WWW.VISIONIAS.IN



/C/VISIONIASDELHI



VISION_IAS



/VISIONIAS_UPSC

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)



7.1. मानव संवर्धन (Human Enhancement)

सुखियों में क्यों?

IMARC की एक रिपोर्ट के अनुसार, मानव संवर्धन उद्योग का आकार 2024 में 125 बिलियन डॉलर था और इसके 2033 तक बढ़कर 348.5 बिलियन डॉलर तक होने की संभावना है।

मानव संवर्धन क्या होता है?

- व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक, कृत्रिम तथा तकनीकी माध्यमों से ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं, जो उसकी संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि करते हैं।
- यह कार्य दवाइयों, हार्मोन, इम्प्लांट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आहार सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे तरीकों से पूरा किया जाता है।
 - पारंपरिक चिकित्सा में बीमारी का इलाज किया जाता है, जबकि मानव संवर्धन का उद्देश्य मानव की सामान्य क्षमता के दायरे को बढ़ाना है।
 - उदाहरण के लिए, मानव संवर्धन प्रौद्योगिकियां मलेरिया, टी.बी. और लाइम जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता या उनके प्रति प्रतिरोध प्रदान करती हैं।
- मुख्य विचार:
 - ट्रांसह्यूमैनिस्ट: मानव क्षमताओं में अत्यधिक वृद्धि करने और जीवनकाल को बढ़ाने वाली उन्नत प्रौद्योगिकियों का समर्थन करती है।
 - बायोकंजरवेटिव: मानव की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने का समर्थन करती है।

मानव संवर्धन के प्रकार

फेनोटाइपिक (गैर-वंशानुगत)	फेनोटाइपिक (गैर-वंशानुगत)	जर्मलाइन (वंशानुगत)
जीन में बदलाव किए बिना शरीर को बेहतर बनाया जाता है। उदाहरण: - बायोनिक अंग - विशेष ग्लासेज - एक्सोस्केलेटन यह सामान्य रूप से स्वीकार्य है।	इसमें शरीर के कोशिकाओं में बदलाव किया जाता है, लेकिन यह अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचता है। उदाहरण: - रोगों के लिए जीन थेरेपी - सोमैटिक सेल मॉडिफिकेशन - टांगेंट सेल ट्रीटमेंट इसे ज्यादातर स्वीकार किया जाता है।	इसमें भ्रूण के जीन में बदलाव किया जाता है, जिससे यह बदलाव आने वाली पीढ़ियों में भी दिखता है। उदाहरण: - भ्रूण जीन एडिटिंग - वंशानुगत संशोधन - डिजाइनर बेबी इसको लेकर नैतिक सवाल उठाए जाते हैं।

मानव संवर्धन से जुड़ी चिंताएं

- समानता: सभी की पहुंच समान नहीं हो सकती है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ सकती है।
- पहचान: मूल गुणों में बदलाव से मानव की प्राकृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है।
- सहमति: बिना सहमति के मानव संवर्धन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है।
- सामाजिक दबाव: बिना संवर्धन वाले लोगों के खिलाफ भेदभाव हो सकता है।
- स्वास्थ्य संबंधी जोखिम: इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी नहीं है।
- पर्यावरण: लंबे जीवनकाल से संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है।
- आनुवंशिक विविधता: आनुवंशिक इंजीनियरिंग से विविधता में कमी आ सकती है, जिससे बीमारियों के प्रति सुभेद्यता बढ़ सकती है।
- विनियमन: इन प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, न्यायपूर्ण और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

मानव संवर्धन मानव के जीवनकाल को लंबा कर सकता है तथा क्षमताओं को बढ़ा सकता है। इसे मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए नैतिक विनियमन, समानता और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जागरूकता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

7.2. रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (Strategic Crypto Reserve: SCR)

सुर्खियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक **रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व** और एक **यू.एस. डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल** की स्थापना की गई है, ताकि एक **रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR)** तैयार किया जा सके।

अन्य संबंधित तथ्य

➔ इसका उद्देश्य क्रिप्टो प्रबंधन में मौजूद कमियों को दूर करना और यू.एस. को डिजिटल एसेट रणनीति में एक अग्रणी लीडर बनाना है।

क्रिप्टोकॉरेसी क्या है?

- ➔ यह एक **डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा** है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है और विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है।
- ➔ पारंपरिक फिएट मुद्राओं के विपरीत, इसे कोई **सरकार या केंद्रीय बैंक नियंत्रित नहीं** करता है।
- ➔ **उदाहरण:** बिटकॉइन (BTC), एथेरियम (ETH), रिपल (XRP), टीथर (USDT)
- ➔ **क्रिप्टोकॉरेसी की मुख्य विशेषताएं:**
 - ➔ **विकेंद्रीकरण:** यह एक **डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर** का उपयोग करती है, जिससे **बिचौलियों पर निर्भरता कम** हो जाती है।
 - ➔ **सीमित आपूर्ति:** बिटकॉइन (अधिकतम 21 मिलियन) की तरह कई की आपूर्ति निश्चित होती है।
 - ➔ **पारदर्शिता:** ब्लॉकचेन लेनदेन को **खुला और सत्यापन योग्य** बनाता है।
 - ➔ **सुरक्षा:** **क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन** धोखाधड़ी और जालसाजी से बचाता है।
 - ➔ **सीमा-रहित लेनदेन:** यह सीमा-रहित तेज़, कम लागत वाले वैश्विक ट्रांसफर की अनुमति देता है।

रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR) के बारे में

- ➔ **परिभाषा:** SCR एक **सरकारी क्रिप्टो भंडार** है। इसे आर्थिक लचीलापन, वित्तीय संप्रभुता और अनिश्चितता के खिलाफ बचाव को बढ़ावा देने के लिए **राष्ट्रीय भंडार में शामिल** किया गया है।
- ➔ यह पारंपरिक करेंसी रिजर्व जैसे विदेशी **मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार के बजाय** एक डिजिटल मुद्रा भंडार के रूप में कार्य करता है।
- ➔ SCR के **संचालन की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से तय नहीं** की गई है।
 - ➔ इसे **रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व** की अवधारणा के समान समझा जा सकता है, जिसका उपयोग बाहरी व्यवधानों के खिलाफ सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।

क्या भारत को भी रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व स्थापित करना चाहिए?

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
➔ विविधीकरण: स्वर्ण, बॉण्ड और शेयर से ज्यादा संबंधित नहीं होती है, जिससे पोर्टफोलियो संबंधी जोखिम कम हो जाता है। ➔ आर्थिक झटकों से बचाव: यह USD के उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों (जैसे कि आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार युद्ध, आदि) के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। ➔ लागत प्रभावी विप्रेषण: क्रिप्टो लेन-देन विप्रेषण शुल्क को 6.4% से घटाकर 1% कर सकते हैं, जिससे अरबों रुपये की बचत होगी। ➔ तकनीकी रूप से अग्रणी: भारत की ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi) नवाचार क्षमता का लाभ उठाता है। ➔ उच्च रिटर्न की क्षमता: क्रिप्टो बे बेहतर रिटर्न दिया है। उदाहरण: बिटकॉइन ने 200 गुना, NVIDIA और Apple जैसे बड़े स्टॉक्स ने 50 गुना और 10 गुना की वृद्धि की। ➔ वित्तीय संप्रभुता: यह SWIFT जैसी बाहरी प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है।	➔ अस्थिरता: उच्च मूल्य उतार-चढ़ाव (जैसे, 2022 में बिटकॉइन की 80% गिरावट) रिजर्व स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करते हैं। ➔ RBI का रुख: RBI बार-बार वित्तीय अस्थिरता की चेतावनी देता है; विकेंद्रीकृत क्रिप्टो की तुलना में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को प्राथमिकता देता है। ➔ विनियामक मुद्दे: इसमें मौजूदा वित्तीय कानूनों से टकराव और भविष्य में संभावित विनियमों के संबंध में अनिश्चितता शामिल है। ➔ सुरक्षा खतरे: क्रिप्टो वॉलेट्स पर साइबर हमले हो सकते हैं। ➔ पर्यावरण संबंधी चिंताएं: क्रिप्टोकॉरेसी माइनिंग प्रक्रिया (जैसे: बिटकॉइन) में बिजली की खपत अधिक होती है। ➔ स्वीकृति संबंधी बाधाएं: इसमें क्रिप्टो के प्रति आम लोगों में संदेह और रिजर्व संपत्ति के रूप में इसकी सीमित संस्थागत विश्वसनीयता, आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- ➔ **लघु स्तर पर शुरुआत:** ट्रायल के तौर पर विदेशी मुद्रा भंडार का 1-2% (लगभग 6-12 बिलियन डॉलर) हिस्सा क्रिप्टोकॉरेसी के लिए निर्धारित कर सकता है।
- ➔ **विनियामक फ्रेमवर्क:** भारत सिंगापुर और जापान के संतुलित मॉडल से सीख ले सकता है।
- ➔ **तकनीकी विशेषज्ञता:** सुरक्षित अभिरक्षा और ब्लॉकचेन अवसंरचना के निर्माण के लिए भारत की प्रतिभा का उपयोग किया जा सकता है।
- ➔ **उपयोगिता पर ध्यान देना:** विप्रेषण और DeFi में क्रिप्टो के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- ➔ **वैश्विक प्रवृत्तियों पर नजर रखना:** भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों (जैसे: अमेरिकी बिटकॉइन ETF, EU के MiCA रेगुलेशन) के अनुरूप नियम बना सकता है।

7.3. लाइट सुपरसॉलिड (LIGHT SUPERSOLID)

सुर्खियों में क्यों?

इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने पहली बार **प्रकाश से सुपरसॉलिड का निर्माण** किया है।

सुपरसॉलिड के बारे में

- **परिभाषा:** यह पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है, जो ठोस जैसी संरचना और घर्षण रहित प्रवाह दोनों का प्रदर्शन करती है।
- **प्रारंभिक शोध:** 1960 के दशक में इसकी भविष्यवाणी की गई; 2017 में **अल्ट्राकोल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेन्सेट्स (BECs)** का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया।
 - ➔ **अत्यधिक निम्न तापमान (0 केल्विन या -273.15°C) अनिवार्य होता था**, जिस पर क्वांटम प्रभाव दिखाई देते हैं।
 - ➔ इस तापमान पर **परमाणुओं में न्यूनतम ऊर्जा** होती है जिसे **पदार्थ की पाँचवीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेन्सेट्स (BECs)** के रूप में जाना जाता है।
- **वर्तमान शोध:** नए शोध में **“पोलारिटॉन” सिस्टम** की विशेषताओं पर आधारित एक **नई तकनीक** का उपयोग किया गया है।
 - ➔ **पोलारिटॉन** वस्तुतः प्रबल विद्युत-चुम्बकीय इंटरएक्शन के तहत प्रकाश और क्वासि-पार्टिकल्स जैसे एक्साइटोन के आपस में जुड़ने से बनते हैं।
 - ➔ क्वासि पार्टिकल्स गणितीय सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जिसके तहत पदार्थों में होने वाले मूलभूत बदलावों (जैसे- स्पिन वेक्स) को कणों या पार्टिकल्स के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

प्रकाश को सुपरसॉलिड में बदलने का क्या महत्व है?

- **क्वांटम कंप्यूटिंग:** यह **क्वांटम कंप्यूटिंग** में अधिक स्थिर क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स) बनाने में मदद कर सकता है।
- **ऑप्टिकल और फोटोनिक डिवाइस:** ऑप्टिकल उपकरणों, फोटोनिक सर्किट्स, और यहां तक कि बुनियादी क्वांटम यांत्रिकी संबंधी शोध में क्रांति ला सकती है।
- **मैटेरियल साइंस और एनर्जी:** शोधकर्ताओं को मैटेरियल साइंस के नए क्षेत्रों का अन्वेषण करने में सक्षम बनाती है तथा ऊर्जा के तथा समझ के हमारे तरीके में भी नए मार्ग खोल सकती है।

प्रकाश के बारे में

- ब्रह्मांड में **प्रकाश की गति सबसे अधिक** है। **प्रकाश की गति 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड** है।
- प्रकाश वेव-पार्टिकल **ड्युअलिटी** प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश **कभी-कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी-कभी कण की तरह**।
- **क्वांटम यांत्रिकी** हमें बताती है कि प्रकाश एक साथ **कण और तरंग, दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है**।

7.4. एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी दवाइयां {ANTI-RETROVIRAL THERAPY (ART) DRUGS}

सुर्खियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को HIV/AIDS (PLHIV) से पीड़ित रोगियों के लिए एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) दवाओं की आपूर्ति और खरीद में आ रही समस्याओं पर जवाब देने का निर्देश दिया है।

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) दवाइयां क्या होती हैं?

- HIV से संक्रमित रोगी का इलाज **ART** से किया जाता है, जिसमें रोगी को **एंटी-HIV दवाइयां** दी जाती हैं। ART का मुख्य उद्देश्य **शरीर में वायरस की मात्रा या प्रभाव को बहुत कम स्तर (अनडिटेक्टेबल) तक लाना** है। इसे **“अनडिटेक्टेबल=अनट्रांसमिटेबल” (U=U)** कहा जाता है।
- ART में **2 से 4 दवाइयों का संयोजन** शामिल है। इसे **हाइली एक्टिव एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (HAART)** भी कहा जाता है।
- ART **HIV का इलाज नहीं** है, लेकिन यह HIV से संक्रमित लोगों को लंबे और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है।
- भारत में ART दवाओं का प्रबंधन **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)** द्वारा किया जाता है।

HIV/AIDS के बारे में

- **HIV (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस):** यह एक वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और खासतौर पर **CD4 कोशिकाओं** (T कोशिकाओं) को नष्ट करता है। ये कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं।
- **AIDS (एक्वायर्ड इम्यून डेफिशियेंसी सिंड्रोम):** यह HIV संक्रमण का अंतिम चरण है। इसमें इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि वह जीवन-धातक संक्रमणों से नहीं लड़ पाता है।
 - ➔ हर HIV संक्रमित व्यक्ति को AIDS हो जाए, यह जरूरी नहीं है, खासकर जब समय पर सही इलाज और देखभाल मिल रही हो।
- **संक्रमण:** असुरक्षित यौन संपर्क, ब्लड-टू-ब्लड संपर्क, संक्रमित माँ से बच्चे में संक्रमण फैलना, आदि।
- **भारत में स्थिति:** **इंडिया HIV अनुमान 2023** रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **2.5 मिलियन** से अधिक लोग HIV से पीड़ित हैं।

उठाए गए उपाय

वैश्विक प्रयास:

➤ वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास:

- ➔ **UNAIDS 95-95-95 लक्ष्य (2030 तक):** HIV से संक्रमित 95% लोगों को उनकी बीमारी की स्थिति के बारे में बताना, निदान किए गए 95% लोगों को ART उपलब्ध कराना, ART प्राप्त कर रहे 95% लोगों में वायरस के स्तर को कम-से-कम करना।
- ➔ **एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष।**

➤ भारत में किए गए प्रयास:

- ➔ **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP):** इसे 1992 में शुरू किया गया था। अब इसका-V चल रहा है, जिसकी अवधि 2021-2026 तक है।
- ➔ **निःशुल्क ART उपचार और देखभाल:** भारत में 700+ ART केंद्रों पर उपलब्ध है।
- ➔ **कानूनी संरक्षण: HIV/ AIDS अधिनियम, 2017** HIV से संक्रमित सभी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क ART की व्यवस्था करना अनिवार्य करता है।

7.5. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

7.5.1. मोटापा (OBESITY)

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक स्तर पर हर आठ में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है और 5 से 19 वर्ष के बच्चों व किशोरों में इसके मामले चार गुना बढ़ गए हैं। प्रधान मंत्री ने मोटापा कम करने के लिए खाद्य तेल की खपत में लोगों से 10% की कटौती करने का आह्वान किया है।

मोटापा के बारे में

- WHO के अनुसार, मोटापा शरीर में असामान्य या अत्यधिक वसा का संचय है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है।
 - ➔ **BMI मोटापे का माप है।**
 - ♦ 25 या इससे अधिक BMI वाले व्यक्ति को अधिक वजन वाला माना जाता है।
 - ♦ 30 या इससे अधिक BMI वाले व्यक्ति को मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है।
- **स्वास्थ्य जोखिम:** हृदय रोग में वृद्धि, मधुमेह, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां, आदि।

मोटापे की समस्या की रोकथाम के लिए भारत में कुछ रणनीतिक उपाय



पोषण अभियान

बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना



फिट इंडिया मूवमेंट

सक्रिय जीवन-शैली को बढ़ावा और दिनचर्या में फिटनेस के लिए प्रोत्साहन



गैर-संचारी रोगों (NCDs) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

समुदाय के सदस्यों, नागरिक समाज और मीडिया को शामिल करके व्यवहार परिवर्तन के जरिए बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा



ईट राइट इंडिया

सभी के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और संधारणीय भोजन सुनिश्चित करना



RUCO (रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल) पहल

एक बार उपयोग हो चुके खाना पकाने के तेल का सुरक्षित रूप से पुनः उपयोग

NFHS-5 (2019-2021) के अनुसार, भारत में मोटापे की स्थिति

- 24% महिलाएं और 23% पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं।
- 2015-16 से 2019-21 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वजन की दर 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गई।

भारत में मोटापे को बढ़ावा देने वाले कारक

- **उच्च-कैलोरी एवं कम-पोषक तत्व वाले आहार:** रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एवं सैचुरेटेड फैट्स यानी संतृप्त वसा का बढ़ता सेवन।
- **भाग-दौड़ वाली जीवन-शैली:** लंबे समय तक बैठे रहना, स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय बिताना, शारीरिक गतिविधियों पर बहुत कम ध्यान देना, आदि।
- **आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग:** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें मानव शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती हैं और वजन में अवांछित वृद्धि का कारण बन सकती हैं।

7.5.2. राष्ट्रीय जीन बैंक (NATIONAL GENE BANK)

केंद्र सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक (NGB) की स्थापना की घोषणा की। इसका उद्देश्य भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख क्राप (फसल) जर्मप्लाज्म का संरक्षण करना है।

जीन बैंक के बारे में

- जीन बैंक ऐसे जैव-भंडार होते हैं, जहां जैव विविधता को संरक्षित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पादपों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित किया जाता है।
- **जीन बैंक के प्रकार**
 - ➔ **सीड बैंक (बीज बैंक)**-जैसे स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे।
 - ➔ **फील्ड जीन बैंक**- प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित पादपों का संरक्षण।
 - ➔ **क्रायो-प्रीजर्वेशन बैंक**- ऊतक, भ्रूण और कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए।
 - ➔ **पोलन (पराग) और DNA बैंक।**
- भारत में अन्य जीन बैंक
 - ➔ **पशु जीन बैंक:** ICAR-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR), हरियाणा।
 - ➔ **माइक्रोबियल जीन बैंक:** ICAR-राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो (NBAIM), उत्तर प्रदेश।

7.5.3. ट्रांसजेनिक जीव (TRANSGENIC ORGANISM)

‘ट्रांसजेनिक चूहों’ के लिए फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति के गलत बयान के बाद ट्रांसजेनिक चूहे सुर्खियों में आए।

ट्रांसजेनिक जीवों के बारे में

- ➔ **अवधारणा:** ऐसे जीव जो अपनी प्रजाति के प्राकृतिक गुणों की बजाय नए गुण या प्रोटीन निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। ‘ट्रांस’ का अर्थ है ‘एक से दूसरे तक’ और ‘जेनेटिक’ का अर्थ है ‘जीन’।
- ➔ **ट्रांसजेनिक चूहा:** मनुष्यों के साथ फिजियोलॉजिकल तथा जीनोमिक समानता के कारण जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
- ➔ **उद्देश्य एवं उपयोग**
 - ➔ **सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं (फिजियोलॉजिकल) को समझना:** उदाहरण के लिए- चयापचय और रक्त कोशिका का अध्ययन करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग।
 - ➔ **मानव रोगों का मॉडल बनाना:** उदाहरण के लिए- अल्जाइमर जैसे रोगों के अध्ययन हेतु ट्रांसजेनिक सूअरों का उपयोग।
 - ➔ **नये उपचारों का विकास करना:** उदाहरण के लिए- दवा के परीक्षण हेतु ट्रांसजेनिक जेब्राफिश का उपयोग।
 - ➔ **चिकित्सीय प्रोटीन का उत्पादन:** ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन का उत्पादन करने के लिए ट्रांसजेनिक बकैरियों का विकास किया गया है।
 - ➔ **रोग प्रतिरोधी फसलें:** उदाहरण के लिए- **Bt कॉटन** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है, जो **बॉलवर्म के खिलाफ प्रतिरोधी** है।
- ➔ **चुनौतियां**
 - ➔ **नैतिक चिंताएं:** इसमें पशु कल्याण और अनपेक्षित परिणाम आना शामिल है।
 - ➔ **पर्यावरणीय जोखिम:** पारिस्थितिकी-तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।
- ➔ **भारत में विनियमन:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ‘नियम, 1989’; जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) आदि द्वारा विनियमित।

7.5.4. MeitY ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की (MEITY LAUNCHED MULTIPLE INITIATIVES TO BOOST THE AI ECOSYSTEM)

इंडिया AI मिशन का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कई पहलें शुरू की गईं।

लॉन्च की गई प्रमुख पहलें

- ➔ **AI कोष:** यह डेटासेट, AI मॉडल और AI सैंडबॉक्स के लिए एक सुरक्षित रिपोजिटरी है।
- ➔ **इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल:** 10,000+ GPU एक्सेस के साथ सब्सिडी वाले कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क सेवाएं प्रदान करता है।
- ➔ **AI कंपीटेंसी फ्रेमवर्क:** यह सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को AI संबंधी कौशल और क्षमता से लैस करता है।
- ➔ **iGOT-AI:** यह iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर AI-संचालित व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करता है।

अन्य पहलें:

- ➔ इंडिया AI स्टार्ट-अप ग्लोबल एक्सेलरेशन प्रोग्राम,
- ➔ इंडिया AI इनोवेशन चैलेंज
- ➔ इंडिया AI फ्यूचरस्किल्स फेलोशिप।

इंडिया AI मिशन (2024) के बारे में

- ➔ **उद्देश्य:** PPP मॉडल और एडवांस्ड AI अवसंरचना के माध्यम से AI नवाचार को बढ़ावा देना।
- ➔ **फोकस:** लोकतांत्रिक कंप्यूट, स्टार्टअप कैपिटल, एथिकल और प्रभावी AI,
- ➔ **मंत्रालय:** यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का अम्बेला प्रोग्राम है।
- ➔ **कार्यान्वयन एजेंसी:** डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग “इंडिया AI”।

भारत के प्रमुख AI मॉडल्स और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी



भारतजेन: यह सरकार द्वारा वित्त-पोषित पहला मल्टी-मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) है।



डिजिटल इंडिया भाषिणी: यह AI-संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है।



सर्वम-1 AI मॉडल: इसे भाषा अनुवाद, टेक्स्ट संक्षेपण और कंटेंट जनरेशन जैसे उपयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।



चित्रलेखा: यह उपयोगकर्ताओं को विविध भारतीय भाषाओं में ऑडियो ट्रांस्क्रिप्ट बनाने और एडिट करने की सुविधा देता है।



हनुमान एवरेस्ट 1.0: यह बहुभाषी AI प्रणाली है, जो 35 भारतीय भाषाओं में काम कर सकती है।

7.5.5. AI वॉशिंग (AI WASHING)

कई वेंचर कैपिटलिस्ट, स्टार्ट-अप्स द्वारा फंड प्राप्त करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले **AI-वॉशिंग** तरीके से चिंतित हैं।

AI-वॉशिंग के बारे में

- ➔ AI वॉशिंग वह प्रक्रिया है, जिसमें कंपनियां अपने उत्पादों, सेवाओं या व्यापार रणनीतियों में **AI** के उपयोग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं या गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं।
- ➔ **यह शब्द “ग्रीनवॉशिंग” से प्रेरित है** जिसका मतलब है पर्यावरण से जुड़े झूठे दावे करना।
- ➔ **AI-वॉशिंग के उदाहरण:**
 - ➔ ऑटोमेशन को AI बताकर गलत तरीके पेश करना;

7.5.6. नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च {NATIONAL INNOVATION CHALLENGE FOR DRONE APPLICATION AND RESEARCH (NIDAR)}

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI)** के सहयोग से **स्वयान/ SwaYaan पहल** के तहत **NIDAR** का शुभारंभ किया।

- ➔ NIDAR का उद्देश्य **आपदा प्रबंधन और परिशुद्ध कृषि** के लिए **सहयोगात्मक स्वायत्त ड्रोन विकसित करने में** छात्रों और शोधकर्ताओं को शामिल करना है।

स्वयान के बारे में

- ➔ इसे **2022 में MeitY ने मंजूरी प्रदान** की थी।
- ➔ यह ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकियों सहित मानव रहित विमान प्रणालियों (UAS) में **क्षमता निर्माण पर ध्यान** देता है।

7.5.7. उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना (NORTH INDIA'S FIRST NUCLEAR POWER PROJECT)

उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी।

- गोरखपुर परियोजना में **दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर वाली दो जुड़ा इकाइयाँ** शामिल हैं जिनकी **कुल क्षमता 2800 MW** होगी।

PHWR के बारे में

- **शीतलक और मंदक** दोनों के लिए **भारी जल (D_2O)** तथा ईंधन के रूप में **प्राकृतिक यूरेनियम** का उपयोग किया जाता है।
 - भारी जल में **ड्यूटेरियम होता है जो न्यूट्रॉन को प्रभावी ढंग से धीमा कर देता है। इसमें न्यूट्रॉन के अवशोषण की संभावना भी कम होती है।**
- **भारत के PHWR संयंत्र का विकास**
 - 1960 के दशक में **भारत-कनाडा परमाणु सहयोग** के माध्यम से शुरू हुई थी।
 - **राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (RAPS-1)** में पहला **220 MW का रिएक्टर** बनाया गया था।
 - **पोखरण-1 (1974)** के बाद, कनाडा ने भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग देना बंद कर दिया था। इसके बाद **भारत ने 220 MW के PHWR डिजाइन को स्वदेशी रूप से विकसित किया था।**

भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास

- **परमाणु ऊर्जा मिशन** का लक्ष्य **2047 तक 100 गीगावाट (GW) क्षमता हासिल करना** है। वर्तमान क्षमता **8.1 GW** है।
- **झारखंड की जादुगुड़ा माइंस** में नए यूरेनियम भंडार की खोज की गई है।
- **गुजरात के काकरापार में 700 MWe के PHWR की पहली दो इकाइयाँ (KAPS- 3 और 4)** ने वित्त वर्ष 2023-24 में **वाणिज्यिक परिचालन शुरू** कर दिया है।
- **देश के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR 500 मेगावाट)** ने 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं।
- **NPCIL और NTPC ने अश्विनी (ASHVINI) का गठन किया है। 4x700 मेगावाट PHWR माही-बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना इसी के अंतर्गत शुरू की जा रही है।**

7.5.8. नासा के अंतरिक्ष यात्री 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे (NASA'S ASTRONAUTS RETURN TO EARTH AFTER BEING STUCK IN SPACE FOR 286 DAYS)

नासा के अंतरिक्ष यात्री **सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर पर अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा की।**

लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मिलने वाले अवसर:

- **चिकित्सा अनुसंधान:** यह मानव शरीर पर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के प्रभावों का अध्ययन करने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी परीक्षण:** इस तरह का मिशन स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रणालियों का आकलन करने में मदद करता है।
- **डीप स्पेस मिशन की तैयारी:** यह भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर मिशन भेजने की योजना बनाने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करता है।

अंतरिक्ष में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ:

- **अंतरिक्ष विकिरण:** कैंसर एवं अन्य विकिरण जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
- **माइक्रोग्रैविटी:** इससे मांसपेशियों के अट्रॉफी और हड्डी के घनत्व में कमी आ सकती है। साथ ही, पृथ्वी पर आने के बाद शारीरिक संतुलन एवं तालमेल प्रभावित हो सकता है।
 - माइक्रोग्रैविटी से **प्रति माह 1% से 1.5% तक** का नुकसान हो सकता है।
- **अकेलापन और मानसिक दबाव:** यह **मानसिक स्वास्थ्य और टीम के तालमेल को प्रभावित** कर सकता है।

अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)



यह एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है, जो **निम्न भू-कक्षा (370-460 कि.मी. की ऊंचाई पर)** में स्थित है।



प्रमुख साझेदार: यूरोपीय देश (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रतिनिधित्व), संयुक्त राज्य अमेरिका {नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA)}, जापान (जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी), कनाडा (कनाडाई स्पेस एजेंसी) और रूस (रोस्कोस्मोस)।



उद्देश्य: वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी परीक्षण, गहन अंतरिक्ष में अन्वेषण की तैयारी करना, आदि।

7.5.9. स्टारलिंग सैटेलाइट इंटरनेट (STARLINK SATELLITE INTERNET)

'ट्रांसजेनिक चूहों' के लिए फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति के गलत बयान के बाद ट्रांसजेनिक चूहे सुर्खियों में आए।

ट्रांसजेनिक जीवों के बारे में

- **अवधारणा:** ऐसे जीव जो अपनी प्रजाति के प्राकृतिक गुणों की बजाय नए गुण या प्रोटीन निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। 'ट्रांस' का अर्थ है 'एक से दूसरे तक' और 'जेनेटिक' का अर्थ है 'जीन'।
- **ट्रांसजेनिक चूहा:** मनुष्यों के साथ फिजियोलॉजिकल तथा जीनोमिक समानता के कारण जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
- **उद्देश्य एवं उपयोग**
 - **सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं (फिजियोलॉजिकल) को समझना:** उदाहरण के लिए- **चयापचय और रक्त कोशिका का अध्ययन** करने के लिए **ट्रांसजेनिक चूहों** का उपयोग।
 - **मानव रोगों का मॉडल बनाना:** उदाहरण के लिए- **अल्जाइमर जैसे रोगों के अध्ययन हेतु ट्रांसजेनिक मूअरों** का उपयोग।
 - **नये उपचारों का विकास करना:** उदाहरण के लिए- **दवा के परीक्षण हेतु ट्रांसजेनिक जेन्नाफिश** का उपयोग।
 - **चिकित्सीय प्रोटीन का उत्पादन:** **ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन** का उत्पादन करने के लिए **ट्रांसजेनिक बकरियों** का विकास किया गया है।
 - **रोग प्रतिरोधी फसलें:** उदाहरण के लिए- **Bt काटोन** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है, जो **बॉलवर्म के खिलाफ प्रतिरोधी** है।
- **चुनौतियाँ**
 - **नैतिक चिंताएं:** इसमें पशु कल्याण और अनपेक्षित परिणाम आना शामिल है।
 - **पर्यावरणीय जोखिम:** पारिस्थितिकी-तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।
- **भारत में विनियमन:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'नियम, 1989'; जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) आदि द्वारा विनियमित।

7.5.10. उल्काभ (METEORITE)

वैज्ञानिकों ने बीड (महाराष्ट्र) के एक गांव में उल्का पिंड गिरने की पुष्टि की।

- जब कोई उल्काभ वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर पृथ्वी के धरातल से टकराती है, तो उसे उल्कापिंड कहते हैं।

उल्काभ, उल्का और उल्कापिंड के बीच अंतर

अंतरिक्ष में	वायुमंडल में प्रवेश के दौरान	धरातल से टकराने पर
		
उल्काभ (Meteoroid)	उल्का (Meteor)	उल्कापिंड (Meteorite)
- ये आम तौर पर बड़े खगोलीय पिंडों से टूटकर अलग हुए अंतरिक्ष में मौजूद छोटे-छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। जैसे ग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु आदि। - ये चट्टानी और/या धातुमय दोनों रूप में हो सकते हैं।	- ये तब बनते हैं, जब उल्कापिंड पृथ्वी या किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। - इन्हें 'शूटिंग स्टार' कहा जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में तेज गति से प्रवेश करते हुए घर्षण के दबाव के कारण जल जाते हैं।	- जब कोई उल्काभ वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर धरातल से टकराती है, तो उसे उल्कापिंड कहते हैं। - यह धरातल से टकराकर 'क्रेटर' बना सकता है। उदाहरण के लिए लोनार झील (महाराष्ट्र)।

उल्कापिंडों के अध्ययन का महत्व

- सौर प्रणालियों को समझने में सहायक: इनमें सौर मंडल के इतिहास के प्रमाण मिल सकते हैं।
- भूवैज्ञानिक संरचना: ये ग्रहों एवं सौर मंडल के भू-रसायन विज्ञान और खनिज संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- ये ग्रहों के उद्भव और जीवन की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में मदद कर सकते हैं।

7.5.11. ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स {GLOBAL ASTROMETRIC INTERFEROMETER FOR ASTROPHYSICS (GAIA)}

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन, GAIA को बंद कर दिया।

GAIA के बारे में

- यह हमारी आकाशगंगा, **मिल्की वे का त्रि-आयामी मानचित्र बनाने** का एक मिशन था।
- GAIA को **लैंग्रेज पॉइंट-2 (L-2)** में स्थापित किया गया है। यदि सूर्य से अवलोकन किया जाए तो, **L-2 पृथ्वी के पीछे** है। GAIA पृथ्वी से लगभग **1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी** पर है।
- **लैंग्रेज पॉइंट्स** वे स्थान हैं जहाँ **गुरुत्वाकर्षण बल और कक्षीय गति संतुलित** होती है।
- **उद्देश्य:** इसे तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की अवस्थिति एवं गति की सटीक माप के माध्यम से एस्ट्रोमेट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था।

7.5.12. एबेल पुरस्कार (ABEL PRIZE)

जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा (78) को 2025 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को अक्सर **"गणित का नोबेल"** कहा जाता है। यह पुरस्कार उन्हें **बीजगणितीय विश्लेषण, रिप्रजेंटेशन थ्योरी, डी-मॉड्यूलस और क्रिस्टल बेसिस** में उनके कार्यों के लिए दिया गया है।

एबेल पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कार **हर साल गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान** के लिए दिया जाता है। इसका नाम **नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल (1802-1829)** के नाम पर रखा गया है।
- एबेल ने **सामान्य पंचम समीकरण को मूलों की मदद से हल करने की असंभवता को सिद्ध** किया था। वे **दीर्घवृत्तीय फलनों (एबेलियन फलनों)** के क्षेत्र में भी अग्रणी थे।
- यह पुरस्कार **नॉर्वे सरकार द्वारा 2002 में स्थापित** किया गया था। इसे **नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स** द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

नोट: अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने **यूनेस्को के सहयोग से वर्ष 2000 को विश्व गणितीय वर्ष** घोषित किया था।

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.inFoundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028DELHI : 7 MAY, 8 AM | 8 MAY, 11 AM | 16 MAY, 5 PM
20 MAY, 11 AM | 21 MAY, 2 PM | 29 MAY, 8 AMGTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
20 MAY, 11 AM | 27 MAY, 6 PMAHMEDABAD: 7 JUNE | BENGALURU: 28 MAY | BHOPAL: 26 MAY | CHANDIGARH: 18 JUNE
HYDERABAD: 11 JUNE | JAIPUR: 10 MAY, 18 MAY | JODHPUR: 15 MAY | LUCKNOW: 19 MAY | PUNE: 8 MAY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

→ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 27 मई, 11 AM | JAIPUR : 12 मई | JODHPUR : 30 अप्रैल | प्रवेश प्रारम्भ | BHOPAL | LUCKNOW



Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

f/visionias.upsc | t/visioniasdelhi
t/visioniasdelhi | l/visionias_upscDELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110006 | CONTACT: 8468022022, 9019066066
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI



8.1. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO WORLD HERITAGE SITES)

मुख्तियों में क्यों?

यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने 2025 में भारत के लिए संभावित सूची में छह स्थलों/स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- संभावित सूची उन स्थलों/स्मारकों की एक "सूची" है, जिनके बारे में किसी देश का मानना है कि वे विश्व धरोहर स्थल बनने के योग्य हैं।
- प्रक्रिया:** सूची में शामिल होने के बाद, नामांकन दस्तावेज़ तैयार किया जाता है जिसे भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग (INCCU) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मिलकर यूनेस्को को प्रस्तुत करते हैं।
- भारत के 62 स्थल/स्मारक यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं।
- नवीनतम शामिल 6 स्थल/स्मारक हैं- मुदुमल मेन्डिर (तेलंगाना); कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़); विविध राज्यों में स्थित अशोक के अभिलेख; मध्य प्रदेश और ओडिशा का चौसठ योगिनी मंदिर; उत्तर भारत में गुप्तकालीन मंदिर; तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलों के महल-किले।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल/स्मारक (WHS) क्या है?

- विश्व धरोहर स्थल/स्मारक वे स्थल/स्मारक होते हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके "विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य" के लिए मान्यता दी जाती है।
- श्रेणियाँ: सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा मिश्रित धरोहर।

चयन के लिए मानदंड

- किसी स्थल/स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से कम-से-कम एक मानदंड को पूरा करना चाहिए: मानव की रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण हो; सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व का प्रदर्शन करता हो, स्थापत्य कला, पारिस्थितिकी या भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, या असाधारण प्राकृतिक सौंदर्यता और जैव विविधता का प्रदर्शन करता हो।
- अन्य कारक: संरक्षण, प्रबंधन, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा।
- विश्व धरोहर अभिसमय (यूनेस्को की महासभा द्वारा 1972 में अपनाया)
 - यह 1975 से प्रभावी है। यह विश्व धरोहर सूची में अभिलेख के लिए मानदंड परिभाषित करता है।
 - विश्व धरोहर समिति (WHC), 'वर्ल्ड हेरिटेज इन डेनजर' सूची और 'वर्ल्ड हेरिटेज फंड' की स्थापना की गई थी।
 - भारत ने इस अभिसमय की अभिपुष्टि 1977 में की थी।

विश्व धरोहर अभिसमय के अंतर्गत प्रमुख विकास

- विश्व धरोहर पर बुडापेस्ट घोषणा-पत्र (2002): रणनीतिक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया- "4Cs" अर्थात् विश्वसनीयता (Credibility), संरक्षण (Conservation), क्षमता निर्माण (Capacity-building) और संचार (Communication)।
 - 4Cs को रणनीतिक उद्देश्यों के लिए 'समुदाय (Community)' शब्द जोड़कर "5Cs" के रूप में संशोधित किया गया है।
- सांस्कृतिक विरासत की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण पर वारसा अनुशांसा (2018): सशस्त्र संघर्षों, आपदाओं एवं प्राकृतिक खतरों के बाद WHS की पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण हेतु सार्वभौमिक दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- विश्व धरोहर साझेदार पहल (PACT) (1992): सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करना और WHSs के संरक्षण में विविध संस्थाओं एवं व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना।

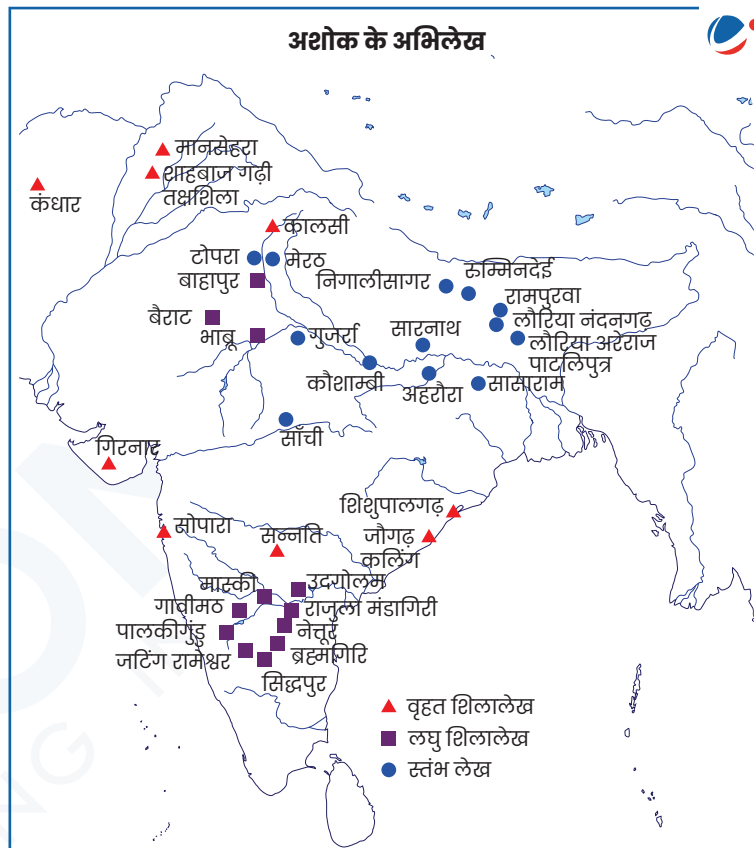
यूनेस्को विश्व धरोहर समिति (असाधारण सार्वभौमिक मूल्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर-सरकारी समिति)

- संरचना: यह समिति भारत सहित 196 सदस्य देशों में से 6 वर्षों (स्वेच्छा से 4 वर्षों तक) तक चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती है।
- कार्य: इसकी वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक होती है, जिसमें WHS की सूची में नए स्थलों/स्मारकों को शामिल करने, पुराने स्थलों/स्मारकों को हटाने या संशोधित करने पर विचार-विमर्श किया जाता है।

- भारत ने **जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ASI द्वारा आयोजित 46वीं बैठक की मेजबानी की**, जहां 'मोईदम्स' (अहोम राजवंश की दफन प्रणाली) भारत के 43वें WHS बन गए।
- 1977 में स्थापित **विश्व धरोहर फंड**, सदस्य देशों के योगदान और स्वैच्छिक दान के माध्यम से संरक्षण का समर्थन करता है।

8.1.1. अशोक के अभिलेख स्थल (ASHOKAN EDICT SITES)

- **अवधि:** मौर्य सम्राट अशोक (268 ई.पू. - 232 ई.पू.) ने अपने शासनकाल के दौरान **प्रस्तर, स्तंभों, शिलाओं और गुफा की भित्तियों** पर 30 से अधिक अभिलेख उत्कीर्ण कराए थे।
 - ये अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद **भारत में पहले लिखित अभिलेख** हैं, जिनमें **14 वृहद शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख और कुछ लघु शिलालेख** उत्कीर्ण करवाए थे।
- **उद्देश्य:** अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य के **शाही आदेश** थे। अधिकतर अभिलेखों पर अशोक द्वारा दिए गए आदेशों को उत्कीर्ण करवाया गया है। ये आदेश **सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों** से संबंधित हैं। इनके माध्यम से अशोक ने **कुलीनों, अधिकारियों तथा आम जनता को संबोधित** किया था।
- **भाषा:** मुख्यतः **प्राकृत**, लेकिन **उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र** में कुछ की **अरामाईक और ग्रीक**।
- **लिपि:** **ब्राह्मी** (मुख्य लिपि), **खरोष्ठी** (गांधार क्षेत्र में प्रयुक्त), **ग्रीक** और **अरामाईक**।
- **निर्माण सामग्री:** अशोक के स्तंभ अभिलेखों का निर्माण **चुनार से लाए गए बादामी रंग के कठोर बलुआ पत्थर और मथुरा से लाए गए धब्बेदार लाल एवं सफेद बलुआ पत्थर** से किया गया है।
- **अभिलेखों की अन्य विशेषताएं:**
 - अशोक ने अभिलेखों (धम्म लिपि) का उत्कीर्णन मुख्यतः अपनी धम्म नीति का प्रचार करने के लिए कराया था। हालांकि, इन अभिलेखों से अशोक के विशाल साम्राज्य की सीमाओं का भी पता चलता है।
 - चार स्थानों, यथा- **मास्की व ब्रह्मगिरी (कर्नाटक), गुज्जरा (मध्य प्रदेश), और नेट्टर (आंध्र प्रदेश)** से मिले अभिलेखों में **अशोक का नाम "देवामीपिय"** (देवताओं का प्रिय) मिलता है।
 - **कर्नाटक** में एक स्तूप पर उत्कीर्ण **कंगनहल्ली अभिलेख** में अशोक को **"रान्यो अशोक"** (राजा अशोक) कहा गया है।



वृहद शिलालेख	विवरण
I	पशु वध और उत्सवों में हत्याओं पर प्रतिबंध; अशोक ने शिकार करना बंद कर दिया।
II	सभी के लिए चिकित्सा देखभाल; चोल, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र और एण्टियोकस द्वितीय का उल्लेख है।
III	राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद; उदारता को बढ़ावा, अधिकारियों को धम्म के प्रचार का निर्देश।
IV	भेरीघोष (युद्ध) पर धम्मघोष (शांति) को प्राथमिकता; नैतिक शासन को बढ़ावा।
V	"प्रत्येक मनुष्य मेरा पुत्र है"; धम्म महामात्रों की नियुक्ति; दासता को संबोधित करता है।
VI	जनकल्याण और जनसंपर्क पर केंद्रित।
VII	धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देता है।
VIII	बोधगया की पहली "धम्म यात्रा" का उल्लेख।
IX	दिखावटी अनुष्ठानों का विरोध; सादगी को प्राथमिकता।
X	यश और प्रसिद्धि की आलोचना; धम्म को महत्व।
XI	धम्म को राज्य की नीति घोषित किया; नैतिकता और दासों के प्रति करुणा पर जोर दिया।
XII	धार्मिक समरसता को प्रोत्साहन; कंधार शिलालेख में यूनानी संपर्क का उल्लेख।
XIII	सबसे लंबा शिलालेख; कलिंग युद्ध पर पश्चाताप; यूनानी और दक्षिण भारतीय राजाओं से कूटनीतिक संबंध।
XIV	अभिलेखों के व्यापक प्रचार-प्रसार का उल्लेख।

8.1.2. गुप्तकालीन मंदिर (GUPTA TEMPLES)

- गुप्त काल (लगभग 320 ई. - 550 ई.) प्राचीन भारत का “स्वर्ण युग” माना जाता है। इसकी मुख्य वजह इस काल में मंदिर स्थापत्य कला में आया महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी बदलाव है।
- स्थापत्य शैली: नागर (उत्तर भारतीय) और द्रविड़ (दक्षिण भारतीय) दोनों शैलियों का मिश्रण। आरंभिक मंदिर साधारण व सपाट छत वाले थे। हालांकि, इस काल में बाद में इनमें विविध नई संरचनाएं {जैसे- गर्भगृह, मंडप (स्तंभों वाले सभाकक्ष), मुखमंडप और ऊंचे शिखर आदि} देखने को मिलती हैं।
- संरक्षण: चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे गुप्त शासकों के समय विष्णु, शिव एवं शक्ति को समर्पित मंदिरों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था।
- गुप्तकालीन मंदिरों की मुख्य विशेषताएं:
 - आरंभिक विकास चरण बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं से प्रभावित था।
 - संरचनात्मक स्थायित्व: नाशवान सामग्रियों की जगह पत्थर और ईंटों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा था।
 - गुप्त काल में पांच प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ: वर्गाकार सपाट छत वाले मंदिर, प्रदक्षिणा पथ वाले वर्गाकार मंदिर, अर्ध-बेलनाकार छत वाले आयताकार मंदिर, वक्राकार शिखर वाले वर्गाकार मंदिर और गोलाकार/ अष्टकोणीय मंदिर।
 - स्तंभ: स्तंभों में मौर्य काल के उल्टे कमल या घंटीनुमा शीर्ष की जगह नए प्रकार का शीर्ष भाग देखने को मिलता है, जिसे “कलश शीर्ष” या “पूर्णकलश” कहा जाता है।
 - अन्य विशेषताएं: सोपानिक चबूतरे, बारीक और सुंदर नक्काशी, धार्मिक प्रतीकों का अंकन आदि।
- सामाजिक-आर्थिक महत्त्व: मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि आर्थिक केंद्र भी बने - इन्हें भूमि दान (देवदान) के जरिए आय प्राप्त होती थी। मंदिर कृषि व्यवस्था को भी नियंत्रित करते थे। उत्तरापथ जैसे व्यापार मार्गों पर स्थित होने से शहरीकरण व श्रमिक संघों का विकास हुआ।

गुप्तकालीन मंदिर

- दशावतार मंदिर, देवगढ़ (उत्तर प्रदेश): यह मंदिर बेतवा नदी के तट पर छठी शताब्दी में बना था, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। इस मंदिर ने शिखर शैली की शुरुआत की थी। इसका शिखर ब्रह्मांडीय केंद्र के रूप में मेरु पर्वत का प्रतीक है। यह मंदिर ‘पंचायतन’ शैली में निर्मित है। मुख्य मंदिर के 4 कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर बनाए गए हैं।
- भितरगांव मंदिर, कानपुर (उत्तर प्रदेश): यह पूर्व दिशा की ओर मुख वाला तथा ईंटों से बना 5वीं सदी का मंदिर है। मंदिर योजना वर्गाकार है। मंदिर की अन्य संरचनाओं में अर्धमंडप, अंतराल और गर्भगृह शामिल हैं।
- नचना-कुठार मंदिर, पन्ना (मध्य प्रदेश): 5वीं-6वीं शताब्दी ई. में निर्मित, यह मंदिर भगवान शिव/ पार्वती को समर्पित है।
- महाबोधि मंदिर, बोधगया (बिहार): मूल मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ई.पू. में करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच का है। यह पूर्णतया ईंटों से निर्मित भारत के सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है।

गुप्तकालीन अन्य मंदिर

- मध्य प्रदेश: वामन मंदिर, देवरी; गुफा संख्या 1, उदयगिरि; मंदिर क्रमांक 17, साँची में गुप्त मंदिर; आदि।
- बिहार: सोपानबद्ध ईंटों से बना मंदिर, लौरिया- नंदनगढ़; नालंदा महाविहार में गुप्त मंदिर; मुंडेश्वरी मंदिर, रामगढ़ (अष्टकोणीय योजना) आदि।
- उत्तर प्रदेश: भीतरी मंदिर, आदि।
- राजस्थान: भीम की चौरी (दरी) आदि।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव
असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र



2025	ENGLISH MEDIUM 23 MARCH	हिन्दी माध्यम 23 मार्च
2026	ENGLISH MEDIUM 11 MAY	हिन्दी माध्यम 11 मई



8.1.3. तेलंगाना के मुदुमल मेन्हिर (MUDUMAL MENHIRS OF TELANGANA)

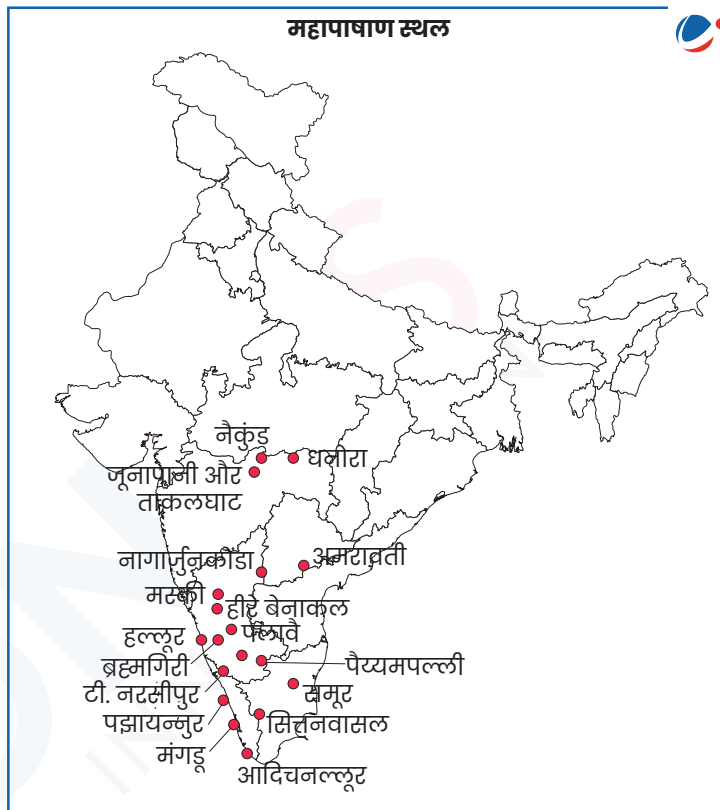
- भारत की सबसे विशाल और बेहतर तरीके से संरक्षित **महापाषाण (मेगालिथिक) खगोलीय वेधशालाओं** में से एक, लगभग 3500-4000 वर्ष प्राचीन, तेलंगाना में **कृष्णा नदी** के तट के निकट स्थित है।
- मुख्य विशेषताएं:**
 - सबसे बड़ा महापाषाण समाधि स्थल:** दक्षिण भारत में।
 - रात्रिकालीन आकाश का चित्रण:** यह **दक्षिण एशिया** का एकमात्र स्थल है, जहां रात्रि में आकाश के विविध नक्षत्रों जैसे- **सप्तऋषि (Ursa Major)**, **सिंह (Leo)** **तारामंडल** आदि को पत्थरों के माध्यम से भौतिक रूप से दर्शाया गया है।
 - प्राचीन वेधशाला:** यहां के मेन्हिर (सीधे खड़े पत्थर) खगोलीय घटनाओं जैसे **संक्रांति, विषुव** आदि के अनुरूप स्थापित हैं।
 - सांस्कृतिक महत्व:** मेन्हिर को स्थानीय लोग **पवित्र मानते थे**, और उन्हें **"निलुरल्ला तिमप्पा"** (खड़े पत्थरों के तिमप्पा) कहते थे। इन मेन्हिर में से एक को **देवी येल्लम्मा** के रूप में पूजा जाता था।

महापाषाण स्थल क्या हैं?

- बड़े पत्थर की संरचनाएं जिनका उपयोग **शवाधान स्थलों या स्मारक स्मारकों** (जैसे- मेन्हिर, डोलमेन) के रूप में किया जाता था। ये **नवपाषाण काल से लेकर लौह युग** तक की हैं।

भारत में महापाषाण संस्कृति (लगभग 1000 ईसा पूर्व से - पहली शताब्दी ईस्वी तक)

- दक्षिण भारत में **महापाषाण संस्कृति पूर्ण रूप से विकसित एक लौह युगीन संस्कृति थी।**
- महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से **समाधि स्थलों और काले व लाल (BRW) रंग के मृदभांड** से संबंधित थी।
- कर्नाटक के ब्रह्मगिरि क्षेत्र में स्थित पिकलीहल और हल्लूर** नामक स्थानों पर ऐसे सबसे पुराने महापाषाणिक शवाधान खोजे गए हैं।
- प्रकार:** बहु-पाषाणीय (डोलमेन, केयर्न, क्रोमलेख, सिस्ट, आदि) तथा **एकल-पाषाणीय** (मेन्हिर, आदि)।
- भौगोलिक वितरण:** महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में **1400 से अधिक स्थल** हैं। **1116 स्थल केवल प्रायद्वीपीय भारत** में हैं।
- जीवन निर्वाह:** प्रारंभिक लौह युग के समुदायों में कृषि, शिकार और मछली पकड़ने का संयुक्त प्रयोग होता था, जो गतिहीन जीवन जीने का संकेत देता है।
- मृदभांड के प्रकार:** इसमें **काले एवं लाल (BRW) तथा लाल एवं चमकदार काले मृदभांड** शामिल हैं।



8.1.4. मध्य प्रदेश और ओडिशा में चौसठ योगिनी मंदिर (CHAUSATH YOGINI TEMPLES IN MADHYA PRADESH AND ODISHA)

चौसठ योगिनी मंदिर में मंदिर की **परिधि** में स्थित कक्षों में **योगिनियों की 64 प्रतिमाएं** स्थापित हैं।

योगिनी योग का अभ्यास करने वाली महिला को संदर्भित करता है और **चौसठ** हिंदी में **संख्या 64** के लिए शब्द है।

- मंदिर के खुले केंद्रीय प्रांगण में भगवान शिव या शक्ति** को समर्पित एक **गर्भगृह** है, जो प्रत्येक कक्ष से दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि नर्तक/ नर्तकियां संभवतः इसी केंद्रीय प्रांगण में प्रदर्शन करते थे/ करती थीं।
- मुख्य विशेषताएं:**
 - ये मंदिर **आमतौर पर वृत्ताकार हैं, ऊँचे स्थान (या पीठ) पर बने होते हैं और आसमान की ओर खुले होते हैं।**
 - अधिकांश मंदिर **वृत्ताकार**, लेकिन **खजुराहो, बड़ोह और रिखिया में आयताकार।**
 - वृत्ताकार योजना **समय चक्र, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह** को दर्शाती है।
 - ये मंदिर **सरल पत्थर का भार वहन करने वाली संरचनाएं हैं।** इनमें मुख्य मंदिर संरचना पर **साधारण नक्काशी** होती है, जबकि **मूर्तियां बारीकी से उकेरी गई हैं।**
 - इन मंदिरों में **नारी शक्ति, कामुकता और प्रजनन क्षमता** का उत्सव मनाते हुए **तांत्रिक एवं योगिक अनुष्ठान** किए जाते थे।
- भारत में चौसठ योगिनी मंदिर**
 - मध्य प्रदेश:** खजुराहो, मितौली (मुरैना), दुधई (जबलपुर), बड़ोह, हिंगलाजगढ़, शहडोल और नारेसर



- उत्तर प्रदेश: लाखेरी व रिखियां
- तमिलनाडु: कांचीपुरम
- ओडिशा: हीरापुर व रानीपुर
- चौसठ योगिनी मंदिर, मुरैना (इकत्तरसो महादेव मंदिर): यह एक वृत्ताकार मंदिर है, जिसका निर्माण कच्छपघात वंश के महाराजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था।
- पुराने संसद भवन की संरचना इस मंदिर की वृत्ताकार आकृति वाली संरचना से प्रेरित है। इसका वृत्ताकार विन्यास श्री यंत्र का प्रतीक माना जाता है, जो ब्रह्मांड और दिव्य नारी शक्ति (शक्ति) का प्रतीक माना जाता है।
- चौसठ योगिनी मंदिर, खजुराहो (9वीं शताब्दी में चंदेल वंश के संरक्षण में निर्मित): भारत के सभी चौसठ योगिनी मंदिरों में से खजुराहो का मंदिर निर्माण में सबसे प्राचीन है। इसका आयताकार स्वरूप इसे विशिष्ट बनाता है। यह पूरी तरह से स्थानीय रूप से पाए जाने वाले बड़े दानों वाले ग्रेनाइट पत्थर से बना है, जबकि खजुराहो के अन्य मंदिर मुख्य रूप से बलुआ पत्थर (सैंडस्टोन) से निर्मित हैं।
- चौसठ योगिनी मंदिर, बड़ोह (गदरमल मंदिर): इसमें एक आयताकार गर्भगृह है, जिसके ऊपर एक विशाल शिखर बना हुआ है। इसके सामने एक छोटा सा द्वारमंडप है। इस मंदिर के ऊपर छत बाद में जोड़ी गई थी। मूल रूप से बड़ोह मंदिर अन्य योगिनी मंदिरों की तरह बिना छत (Hypaethral) वाला रहा होगा।

8.1.5. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल-किले (PALACE-FORTRESSES OF THE BUNDELAS IN MADHYA PRADESH AND UTTAR PRADESH)

बुंदेलों के महल-किलों में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित 6 प्रमुख संरचनाएं शामिल हैं-

- गढ़कुंडार किला: यह गढ़कुंडार में स्थित है, जो बुंदेल राजपूतों की प्रारंभिक राजधानी थी।
- राजा महल (ओरछा): यह महल बुंदेला शासक मधुकर शाह के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। 16वीं शताब्दी में राजधानी को ओरछा स्थानांतरित कर दिया गया था।
- जहांगीर महल (ओरछा): इसका निर्माण मधुकर शाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और इसका प्रमुख निर्माण बीर सिंह देव के शासनकाल में हुआ था।
- दतिया महल: 1620 ई. में निर्मित। पांच मंजिला भवन, जिसे बीर सिंह देव महल के नाम से भी जाना जाता है।
- झाँसी का किला: यह किला 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीर सिंह देव ने बनवाया था।
- धुबेला महल: 17वीं शताब्दी में महाराजा छत्रसाल ने बनवाया था। धुबेला झील के पास स्थित है।

बुंदेलों के महल-किलों की मुख्य विशेषताएं:

- बुंदेल राजपूत शैली और मुगल शैली का संश्लेषण: पारंपरिक राजपूत विशेषताओं को बरकरार रखते हुए मुगल तत्वों को शामिल किया गया है।
- मुगल रूपांकनों व भित्ति चित्रों की स्थानीय पुनर्व्यख्या: मुगल शैली के साथ-साथ रागमाला और रासलीला जैसे प्रतीकात्मक विषयों से प्रेरित हैं।
- रक्षा और सौंदर्यशास्त्र का एकीकरण: अलंकरण तत्वों के साथ-साथ किलेबंदी रणनीतियों का समन्वय किया गया है।
- स्थापत्यकला: यह मंडल रूपी सममित योजना पर आधारित है। इसके केंद्र में एक खुला प्रांगण है, जो आसमान की ओर खुला है।

बुंदेलों के बारे में

- बुंदेला राजपूत मूल रूप से गहरवार क्षत्रिय हैं।
- राजा पंचम ने बुंदेल साम्राज्य की स्थापना 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में की थी।
- जब चंदेलों की सत्ता का पतन हो रहा था, तब बुंदेलों ने गढ़कुंडार को अपनी राजधानी बनाया था।

गढ़कुंडार किला



राजा महल ओरछा



8.1.6. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (बस्तर, छत्तीसगढ़) {KANGER VALLEY NATIONAL PARK (NP) (BASTAR, CHHATTISGARH)}

- अवस्थिति: यह दक्कन प्रायद्वीप-पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है।
- स्थापित: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित।
- प्रमुख विशेषताएं:
 - प्रमुख नदी: कांगेर नदी।
 - अवस्थिति: खोलाबा नदी (गोदावरी की एक सहायक नदी) के तट पर स्थित है।
 - विविध स्थलाकृति: निम्न समतल भूमि, ढलान, पठार, गहरी खाइयां, घाटियां, घुमावदार जलधाराएं आदि।
 - वनस्पति: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वनों का समर्थन करता है।

- ◇ यह प्रायद्वीपीय भारत में साल और सागौन वनों के बीच एक प्राकृतिक संक्रमण क्षेत्र (इकोटोन क्षेत्र) बनाता है।
- भू-आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताएं: कार्स्ट स्थलाकृति- इसमें भूमिगत चूना पत्थर की गुफाएं पाई जाती हैं, जिनमें स्पेलोथेम्स पाए जाते हैं।
- तीन अद्वितीय गुफाएं: कुटुंबसर, कैलाश और दंडक पाई जाती हैं। यहां स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हैं।
- अन्य आकर्षण: तीर्थगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात (एक टेक्टोनिक घटना द्वारा निर्मित) आदि।
- मुख्य जीव-जंतु: तेंदुए, लकड़बग्घा और ढोल (जंगली कुत्ते); पूर्वी पहाड़ी मैना (छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी), विशाल गिलहरी आदि।
- ◇ उच्च स्तर की स्थानिकता: इस राष्ट्रीय उद्यान की चूना पत्थर की गुफाओं में मकड़ी की ऐसी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो केवल यहीं पाई जाती हैं।

8.2. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

8.2.1. विक्रमशिला विश्वविद्यालय (VIKRAMSHILA UNIVERSITY)

राजगीर के बाद बिहार में शिक्षा के एक अन्य प्राचीन केंद्र विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में

- **स्थापना:** इसका निर्माण पाल शासक धर्मपाल (8वीं-9वीं शताब्दी ई.) ने कराया था। यह नालंदा के साथ-साथ विकसित हुआ था।
 - धर्मपाल ने ही आधुनिक बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी।
- **वज्रयान/तंत्रयान बौद्ध धर्म, गुप्त विद्या (Occult studies) और धर्मशास्त्र** का अध्ययन कराया जाता था।
- **तिब्बत** से कई विद्वान यहां अध्ययन के लिए आते थे। कई पांडुलिपियों की संस्कृत में रचना की गई थी और उनका तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया गया था।
- **पाल साम्राज्य** के बौद्ध विद्वान आतिश दीपांकर (980-1054 ई.) विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे।
- 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था।

8.2.2. गीत गवाई (GEET GAWAI)

मॉरीशस की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री का स्वागत पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति गीत गावाई के साथ किया गया।

गीत गवाई के बारे में

- यह **विवाह-पूर्व समारोह** है। इसमें अनुष्ठान, प्रार्थना, गीत, संगीत और नृत्य शामिल होते हैं।
- इसे **यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची (2016) में भी शामिल** किया गया है।
- इसका प्रदर्शन मॉरीशस में भारतीय मूल के **भोजपुरी भाषी समुदायों** द्वारा किया जाता है।
 - **प्रतिभागी:** परिवार की महिला सदस्य और पड़ोसी।
- **मुख्य वाद्य यंत्र:** ढोलक।
- इसका प्रदर्शन **सार्वजनिक रूप से भी किया जा सकता है** और वर्तमान में **पुरुष भी इसमें भाग** लेते हैं।

8.2.3. ज्ञानपीठ पुरस्कार (JNANPITH AWARD)

विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में

- **ज्ञानपीठ पुरस्कार** भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1965 से हर साल भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है।
 - भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में हुई थी। यह भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं में से एक है।
- यह पुरस्कार भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक कृति के लेखक को हर साल दिया जाता है।
 - 2013 से अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्यिक कृतियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है।

8.2.4. भारत के पारंपरिक नववर्ष (INDIA'S TRADITIONAL NEW YEAR FESTIVALS)

भारत के अलग-अलग भागों में विविध पारंपरिक नववर्ष उत्सव मनाए जा रहे हैं।

- **चैत्र:** यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो चंद्र पंचांग (कैलेंडर) पर आधारित है।
- **सुक्लादी:** उत्तर भारत में प्रचलित विक्रम संवत भी चैत्र से ही शुरू होता है।
- **उगादी:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है।
 - "उगादी" शब्द "युग" (काल) और "आदि" (शुरुआत) से मिलकर बना है।
- **गुड़ी पड़वा:** मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा आदि में मनाया जाता है।
- **चेटी चंड:** यह सिंधी समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसे "झूलैलाल जयंती" भी कहा जाता है, जो सिंधी का धार्मिक पर्व है।
- **साजिबू चेइराओबा:** साजिबू नोंगमा पानबा चेइराओबा मेइतेइ नव वर्ष का प्रतीक है। यह मणिपुर में मनाया जाता है।
 - यह साजिबू माह (मार्च/अप्रैल) के प्रथम चंद्र दिवस पर आता है।



Vision Publication

Igniting Passion for Knowledge..!



Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

Explore Our Latest Publications



Empower Learners



Stay Current



Foster In-Depth Understanding



Support Last-Minute Prep

PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र

by

ANOOP KUMAR SINGH

Classroom Features:

- ☒ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
- ☒ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
- ☒ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
- ☒ Effective Answer Writing
- ☒ Revision Classes
- ☒ Printed Notes
- ☒ All India Test Series Included

Offline Classes @

JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD

हिन्दी माध्यम
में भी उपलब्ध

Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

Overall Quality Improvement for Philosophy Optional

Daily Tests:

- ☒ Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
- ☒ Focus on Concept Building & Language
- ☒ Introduction-Conclusion and overall answer format
- ☒ Doubt clearing session after every class

Mini Test:

- ☒ After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
- ☒ Copies will be evaluated within one week

नीतिशास्त्र (ETHICS)



9.1. अनुनय (PERSUASION)

परिचय

सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्मार्टफोन्स की पहुंच में भी बढ़ोतरी से समाज का एक बड़ा हिस्सा भ्रामक सूचनाओं की चपेट में आ गया है। ऐसे समय में अनुनय एक सामाजिक साधन के रूप में लोगों के विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करके भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है।

एक अवधारणा के रूप में अनुनय

- ➔ यह ऐसा प्रयास है जिसमें दूसरों के **विश्वासों या कार्यों को तर्क, भावना या विश्वास के जरिए बदलने** का प्रयास किया जाता है। इसमें जबर्न या सूचनाओं का हेरफेर करके अपनी बात मनवाना शामिल नहीं है।
- ➔ **विशेषताएं:** यह ज्यादातर जानबूझकर स्पष्ट, मौखिक और समानता तथा साझे हितों पर आधारित होता है।

अनुनय के तरीके (Modes of Persuasion)



एथोस (विश्वास और विश्वसनीयता संबंधी आग्रह)

उदाहरण: शोधकर्ता अपनी योग्यता और पिछले कामों का हवाला देते हैं, ताकि वे नए निष्कर्ष प्रस्तुत करने से पहले अपनी विश्वसनीयता साबित कर सकें।



पैथोस (भावना संबंधी आग्रह)

उदाहरण: राष्ट्रीय प्रतीकों या ऐतिहासिक घटनाओं का उपयोग करके गर्व और एकता की भावना जागृत करना।



लोगोस (तर्क संबंधी आग्रह)

उदाहरण: एंटी-टोबैको अभियान में धूम्रपान को रोकने के लिए फेफड़े के कैंसर के आंकड़े दिखाना।

अनुनय को प्रभावित करने वाले कारक

- ➔ **स्रोत:** स्रोत की विश्वसनीयता और अधिकार इसके स्रोत हैं। **उदाहरण के लिए,** डॉ. रणदीप गुलेरिया द्वारा कोविड-19 से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाना।
- ➔ **संदेश सामग्री:** दर्शकों के लिए संदेश की प्रासंगिकता, संदेश की स्पष्टता और अस्पष्टता, आदि। **उदाहरण के लिए,** स्वच्छ भारत अभियान का स्वास्थ्य और गरिमा पर संदेश।
- ➔ **दर्शकों की विशेषताएं:** दर्शकों का मौजूदा विश्वास और जानकारी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदि। **उदाहरण के लिए,** ग्रामीण बनाम शहरी समूहों के अनुरूप वित्तीय साक्षरता।
- ➔ **पारस्परिकता:** अनुरोध करने से पहले कुछ मूल्यवान चीज देना। **उदाहरण के लिए,** LPG सब्सिडी के लिए 'गिव इट अप' अभियान के बाद पी.एम. उज्ज्वला योजना लॉन्च करना।
- ➔ **सामाजिक प्रमाण:** यह प्रदर्शित करना कि दूसरे लोगों ने पहले से ही इस विश्वास या व्यवहार को अपना लिया है। **उदाहरण के लिए,** 'आदर्श ग्राम योजना' के मॉडल गांव।
- ➔ **समय और संदर्भ:** वह परिवेश जिसमें संदेश दिया जाता है, जैसे- वर्तमान मुद्दे, आदि। **उदाहरण के लिए,** महामारी-जनित आर्थिक चिंताओं के दौरान 'वोकल फॉर लोकल' अभियान।

भ्रामक सूचना के विरुद्ध अनुनय कैसे काम कर सकता है?

- ➔ **विश्वास बनाना और विरोध को कम करना:** अनुनयकारी संचार में सहानुभूति और भरोसेमंद संदेशवाहकों (जैसे- समुदाय के नेतृत्वकर्ता या परिचित लोग) का उपयोग करके अनुनय के लिए एक सामान्य आधार तैयार किया जाता है।

- ➔ **व्याप्त धारणाओं के विरुद्ध नई धारणाओं का सहारा लेना:** केवल आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, अनुनयकारी संचार में कहानियों, दृश्यों और भावनात्मक अपील का प्रयोग किया जाता है।
- ➔ **टकराव के बिना आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना:** सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग

गलत जानकारी के खतरे



हिंसा और अशांति

झूरी जानकारी के कारण हिंसा और अशांति फैलने की संभावना।



राजनीतिक हेरफेर

राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए गलत जानकारी का उपयोग।



पर्यावरणीय मुद्दों पर निष्क्रियता

पर्यावरणीय मुद्दों के कारण उपयुक्त कार्रवाई न करना।



आर्थिक कुप्रबंधन

गलत आंकड़ों के आधार पर खराब आर्थिक फैसले लेना।



सामाजिक सदभाव पर असर

झूठ और गलत जानकारी के कारण विश्वास की कमी एवं समुदाय की एकता के समक्ष बाधा।

और वैकल्पिक स्पष्टीकरण का उपयोग करते हुए बहस के बजाय संवाद के माध्यम से चिंतन को प्रोत्साहित करना। **उदाहरण के लिए**, चरमपंथी विश्वासों पर खुले प्रश्नों के माध्यम से कटुता को दूर करना।

- **समय के साथ निरंतर जुड़ाव**: यदि कोई व्यक्ति किसी **भ्रामक सूचना या विश्वास** को मानता है, तो वह **सिर्फ एक बार समझाने से नहीं समझेगा**। इसके लिए अनुनयकारी को बार-बार सम्मानजनक तरीके से उससे बात करनी होगी।

9.2. प्रसन्नता/ सुख (HAPPINESS)

परिचय

“प्रसन्नता एक चयन है जो कभी-कभी प्रयास की मांग करता है” - ऐस्चिलस। यह उद्धरण हाल ही में जारी **वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025** में भारत की स्थिति को देखते हुए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें **147 देशों की सूची में भारत 118वें स्थान** पर है। भारत की स्थिति इसके पड़ोसी देशों, जैसे- नेपाल और पाकिस्तान से भी खराब है।

प्रसन्नता क्या है?

- **प्रसन्नता** को आम तौर पर **“अपने संपूर्ण रूप से जीवन के व्यक्तिपरक आनंद”** के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति **अपने जीवन को कितना अनुकूल और आनंदमय** मानता है।

प्रसन्नता के दो मार्ग	
 हेडोनिक प्रसन्नता (जेरमी बेंथम) मुख्य विशेषताएं - आनंद को अधिकतम करना। - संवेदी और भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त करना। - आनंद और दुःख के बीच उपयोगितावादी गणना करना।	 यूडेमोनिक प्रसन्नता (अरस्तु) मुख्य विशेषताएं - व्यक्ति की ताकत, क्षमताओं और मूल्यों का उपयोग करना। - इसे मानसिक कुशलक्षेम (Psychological Well-Being) के नाम से भी जाना जाता है। - व्यक्तिगत विकास, अर्थ और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना।

प्रसन्नता की खोज: एक दार्शनिक यात्रा, पूर्व और पश्चिमी दृष्टिकोणों के आधार पर

भारतीय परिप्रेक्ष्य	पश्चिमी परिप्रेक्ष्य
चावक नीतिशास्त्र : काम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और अर्थ उस लक्ष्य को पाने का साधन है।	एपिक्यूरियनवाद (मध्यम सुखवाद) : शारीरिक दर्द और मानसिक चिंता से मुक्ति असली प्रसन्नता है।
भगवद् गीता (निष्काम कर्म) : तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं।	कांट (कर्तव्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य) : नैतिक कर्तव्य ही व्यक्ति को वास्तविक प्रसन्नता की ओर ले जाता है।
बौद्ध धर्म (मध्यम मार्ग) : सुख कहीं पहुँचने में नहीं, बल्कि जीवन को अनुभव करने में है।	जॉन लॉक : प्रसन्नता की खोज नैतिकता और सभ्यता की नींव है।
भक्ति परंपरा : भक्ति, प्रसाद और दिव्य प्रेम के माध्यम से सुख।	उपयोगितावाद : अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख।
गुरु नानक (संतोख) : संतोष शाश्वत सुख है।	स्टोइकवाद : केवल नियंत्रण योग्य को नियंत्रित करना।
पारलौकिक परिप्रेक्ष्य : जब व्यक्ति सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर या ब्रह्म से जुड़ जाता है तब उसे “आनंद” यानी परम सुख की प्राप्ति होती है।	ईसाई धर्मशास्त्र (सेंट ऑगस्टीन) : वास्तविक प्रसन्नता विश्वास और दिव्य अनुग्रह के माध्यम से ईश्वर के साथ अंतिम मिलन में निहित है।

वर्तमान जीवन-शैली में प्रसन्नता के समक्ष मौजूद बाधाएं

- **बाह्य कारक**
- **नकारात्मक सामाजिक तुलनाएं**: अवास्तविक मानक (जैसे- शरीर, सुंदरता, आदि) व्यक्तियों के आत्म-मूल्य और प्रसन्नता में कमी लाने का काम कर रहे हैं।
 - **सामाजिक समर्थन प्रणालियों की कमी**: दुनिया भर में 19% युवाओं ने बताया कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर वे सामाजिक सहयोग के लिए विश्वास कर सकें। (2023 में हुए एक सर्वे के अनुसार)
 - **वित्तीय दबाव**: उदाहरण के लिए, गरीबी एक ऐसा बोझ है जो व्यक्तियों की सोचने-समझने की शक्ति को कम कर देती है।
 - **हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना**: उदाहरण के लिए, मादक पदार्थों का सेवन मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है।
- **आंतरिक कारक**
- **आत्म-संदेह एवं आत्म-सम्मान में कमी**: इससे चिंता, अवसाद और दूसरों के प्रति कृतज्ञता की भावना कम हो जाती है।

- **वर्तमान क्षण में न जीना:** लगातार नकारात्मक सोचना, हर बात को ज्यादा सोचते रहना और अनसुलझे मानसिक आघात इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं।
- **अत्यधिक स्क्रीन टाइम:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, स्क्रीन टाइम में वृद्धि और खुले में खेलने के समय में कमी युवाओं को एक 'चिंतित पीढ़ी' के रूप में तब्दील कर रही है।

सिविल सेवक नागरिकों के बीच प्रसन्नता के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं

- **जन-केंद्रित गवर्नेंस** प्रणाली अपनाकर प्रसन्नता को बढ़ाया जा सकता है, जैसे ग्राम पंचायत विकास योजनाएं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** ई-गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा-परीक्षण आदि के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करना।
- **मानसिक और भावनात्मक कल्याण:** टेली-मानस (टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन), लचीले काम के घंटे आदि के प्रावधानों द्वारा वर्क-लाइफ संतुलन, आदि।
- **सामाजिक सद्भाव:** सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **प्रसन्नता को नीति का एक घटक बनाना:** शासन में प्रसन्नता को शामिल करना, उदाहरण के लिए, भूटान की सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता नीति या "हैप्पीनेस मिनिस्ट्री" का विचार।

निष्कर्ष

यद्यपि प्रसन्नता प्राप्त करना जटिल हो सकता है, लेकिन यह व्यक्तिगत अभ्यास, नीति निर्माताओं की सोच और समाज की संरचना में बदलाव लाकर संभव है। इसमें **सुख-समृद्धि** और **अर्थपूर्ण जीवन** दोनों का संतुलन होना चाहिए।

9.3. परोपकार: सामाजिक भलाई के लिए एक नैतिक अनिवार्यता (PHILANTHROPY: A MORAL IMPERATIVE FOR SOCIAL GOOD)

परिचय

"दूसरों की सेवा करना इस पृथ्वी पर हमारे रहने का किराया है" - मुहम्मद अली। यह उद्धरण भारत के बढ़ते **परोपकारी परिदृश्य में परिलक्षित होता है**, जिसका मुख्य कारण है- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत व्यय, अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ वाले व्यक्तियों (UHNIs) का योगदान, और मध्य वर्ग में परोपकारिता की बढ़ती की संस्कृति। **परोपकारिता प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक कई संस्कृतियों का हिस्सा रही है।**

आधुनिक संदर्भ में परोपकारिता

- इसका शाब्दिक अर्थ है **"मानवता के लिए प्रेम"**। इसमें सामाजिक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान आदि के लिए संस्थाओं को स्वैच्छिक दान शामिल है।
- दान की अल्पकालिक राहत के विपरीत, परोपकार का लक्ष्य **व्यापक स्तर पर और दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना** होता है।

परोपकारिता का दार्शनिक आधार

- **भारतीय परिप्रेक्ष्य**
 - **चाणक्य का अर्थशास्त्र:** राज्य को अपने राजस्व का 1/6 भाग दान करना चाहिए।
 - **विवेकानंद का 'दरिद्र नारायण' का विचार:** गरीबों की सेवा करना ईश्वर की पूजा करने के समान है।
 - **गांधीजी का न्यासिता का सिद्धांत:** धनवान व्यक्तियों को केवल सामाजिक धन के न्यासी के रूप में कार्य करना चाहिए।
 - **धार्मिक परंपराएँ: हिंदू धर्म:** दान और दक्षिणा की अवधारणाएं, **इस्लाम:** ज़कात (निर्धारित दान) और सदकात (स्वैच्छिक दान), **बौद्ध धर्म:** भिक्षा (भोजन या अन्य दान), **सिख धर्म:** लंगर (सामुदायिक रसोई)।
- **पश्चिमी परिप्रेक्ष्य**
 - **परिणामवादी दृष्टिकोण (सद्गुण नीतिशास्त्र):** उदारता और करुणा महत्वपूर्ण सद्गुण हैं।
 - **कांट का नीतिशास्त्र (नैतिक दायित्व):** परोपकारी होना हमारा कर्तव्य है।
 - **रॉल्स का सिद्धांत (निष्पक्षता के रूप में न्याय):** सबसे वंचित वर्गों को प्राथमिकता देना।
 - **उपयोगितावाद:** अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना।
 - **उदारवाद:** राज्य कल्याण की अपेक्षा परोपकार को प्राथमिकता दी जाती है।

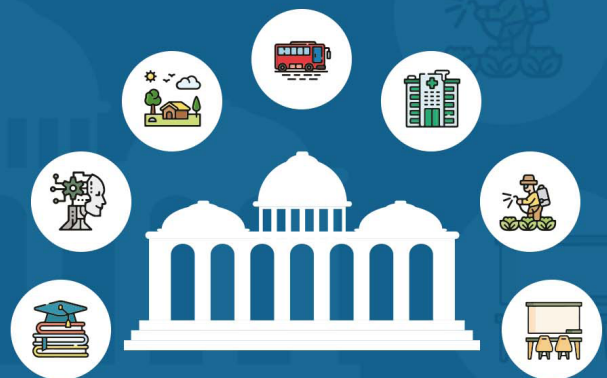
विकास के साधन के रूप में परोपकार का महत्व

- **वित्त-पोषण की कमी को समाप्त करना:** यह सरकारों द्वारा दी गई **बजटीय सहायता के पूरक** के रूप में कार्य करता है।
- **विकास संबंधी खामियों को दूर करना:** यह गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, **अजीम प्रेमजी फाउंडेशन** का ग्रामीण शिक्षा कार्य।
- **नवाचार को बढ़ावा देना:** विकास में तकनीक आधारित समाधान को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए, गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप स्वच्छता संबंधी नवाचारों को बढ़ावा दिया है।

परोपकारिता से जुड़ी नैतिक चुनौतियां

- **सामाजिक एजेंडे पर अभिजात वर्ग का कब्जा:** बड़े दानदाता नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। परोपकारिता का उपयोग प्रायः कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है।

मुख्तियों में रही योजनाएं



10.1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RASHTRIYA GOKUL MISSION)

मुख्तियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) को मंजूरी दी। इस मिशन के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि (वित्त-वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के बारे में

- ➔ शुभारंभ: वर्ष 2014 में राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत शुरू।
- ➔ मंत्रालय: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
- ➔ कार्यान्वयन विभाग: पशुपालन एवं डेयरी विभाग।
- ➔ वित्त पोषण: केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान (कुछ अपवादों को छोड़कर)।
- ➔ उद्देश्य: दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना, आनुवंशिक सुधार को बढ़ावा देना, ब्रीडिंग नेटवर्क को मजबूत करके कृत्रिम गर्भाधान के दायरे का विस्तार करना, वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करके देशी नस्ल की मवेशियों का संरक्षण करना।

मिशन में जोड़े गए नए घटक:

- ➔ बछिया पालन केंद्र: कुल 15000 बछियों की क्षमता वाले 30 आश्रय केंद्रों के निर्माण हेतु 35% सब्सिडी।
- ➔ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) सहायता: उच्च-आनुवंशिक गुणों वाली बछियों की खरीद के लिए 3% ब्याज अनुदान।

मिशन के तहत पहले से मौजूद घटक

- ➔ आनुवंशिक सुधार: इसमें वंश परीक्षण, IVF तकनीक, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार (MAITRIS के माध्यम से) शामिल हैं।
- ➔ स्वदेशी नस्लें: देशी नस्लों के संरक्षण हेतु गौशालाओं, गोकुल ग्रामों और राष्ट्रीय कामधेनु केंद्रों को समर्थन दिया जाता है।
- ➔ डिजिटल एकीकरण: इसके तहत ई-पशु हाट पोर्टल और राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन को भी विकसित किया गया है।
- ➔ क्षमता निर्माण: किसानों के प्रशिक्षण और गोपाल/कामधेनु पुरस्कार जैसी क्षमता निर्माण की पहलें भी चलाई जाती हैं।

प्रभाव

- ➔ दूध उत्पादन: 2014 से 2024 के बीच भारत में दूध उत्पादन में 63.55% की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 307 ग्राम से बढ़कर 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है।
- ➔ उत्पादकता: पिछले दस वर्षों में डेयरी उत्पादकता में 26.34% की वृद्धि दर्ज की गई है।



टॉपिक्स	प्रमुख तथ्य/ डेटा
न्यायिक जवाबदेही	जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रमुख तंत्र ➔ पद से हटाना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के अंतर्गत प्रावधान मौजूद हैं। ➔ 1999 की आंतरिक जांच प्रक्रिया: न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997) और न्यायिक आचरण संबंधी बेंगलूर सिद्धांत (2002) पर आधारित है। ➔ C.J. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त कर सकता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतों का निपटान कर सकता है। ➔ तीन सदस्यीय समिति शिकायत की जांच करती है और पद से हटाने या आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है (जैसे, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन)। ◊ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ: हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य हाई कोर्ट्स के दो मुख्य न्यायाधीश तथा एक न्यायाधीश शामिल होता है। ◊ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ: सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश तथा अन्य हाई कोर्ट्स के दो मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ◊ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ: सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीश शामिल।
बिग टेक कंपनियों का विनियमन	बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिए प्रमुख कानून ➔ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDPA) ➔ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) या आईटी नियम, 2021 ➔ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ➔ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ➔ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A
आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, 2025	मुख्य प्रावधान ➔ प्रवेश करने या ठहरने से रोकने के आधार: राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोक स्वास्थ्य या विदेशी संबंधों के लिए खतरा। ➔ विदेशियों की ट्रेकिंग: शैक्षणिक प्रतिष्ठान, अस्पताल और नर्सिंग होम जैसी संस्थाएं।
फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025	फ्री स्पीच के समर्थन के मामले में 33 देशों में से भारत को 24वां स्थान दिया गया।
द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)	द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) के बारे में ➔ इन्हें अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों (IIAs) के नाम से भी जाना जाता है। ये विदेशी निवेशकों को उन उपायों के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन प्रदान करने का एक उपकरण हैं, जो उनके निवेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही, ये समझौते यह संतुलन भी स्थापित करते हैं कि एक देश को अपने क्षेत्र में निवेश को विनियमित करने का संप्रभु अधिकार प्राप्त है। ➔ अवधारणा: ये निवेशकों को (निवेशक-राज्य विवाद निपटान के माध्यम से) या अमेरिका जैसे निवेश करने वाले राज्य (राज्य-राज्य विवाद निपटान के माध्यम से) जैसे गृह देश को मेजबान देश (जैसे- भारत, जहां विदेशी निवेश किया जाता है) के खिलाफ कानूनी दावा करने का अधिकार देती हैं।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)	IORA के बारे में - उत्पत्ति: यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका विज़न 1995 में नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान सामने आया था। - उद्देश्य: हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करना। - सचिवालय: मॉरीशस। - सदस्य: 23 सदस्य और 12 संवाद साझेदार।
भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध	महासागर के बारे में - महासागर/ MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) भारत की 2015 की समुद्री नीति, SAGAR/ सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) का एक विस्तारित संस्करण है। → 'सागर/ SAGAR' का ध्यान भारत के निकटतम पड़ोस पर केंद्रित है, महासागर का दायरा विशेष रूप से ग्लोबल साउथ तक विस्तृत है।
भारत - न्यूजीलैंड संबंध	हाल के घटनाक्रम - न्यूजीलैंड इंडो-पैसिफिक ओशनस इनिशिएटिव (IPOI) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल हुआ। - मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए भी वार्ता का शुभारंभ किया गया तथा पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए आवागमन संबंधी व्यवस्था पर वार्ता का शुभारंभ किया गया।
स्क्वाड एलायंस	स्क्वाड एलायंस के बारे में - यह एक अनौपचारिक मिनीलेटरल (लघुपक्षीय) गठबंधन है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं। - उद्देश्य: हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना, स्थिरता को बनाए रखना आदि। → यह क्वाड से अलग है, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
तरलता घाटा	प्रचलन में मुद्रा और बैंकिंग तरलता के बीच विपरीत संबंध है। तरलता घाटे के प्रबंधन के लिए RBI के पास विकल्प: नकद आरक्षित अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात, खुला बाजार परिचालन, आदि।
कम वैल्यू के BHIM-UPI ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना	- प्रोत्साहन: छोटे व्यापारियों के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 0.15% (अधिकतम 2000 रुपये)। - वैधानिक प्रावधान: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007.
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता	- वर्तमान स्थिति: वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 4% है। - भारत में बिकने वाले 99% स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण (PSL)	वैधानिक प्रावधान: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - PSL पर समितियां: गाइगिल समिति (1969), घोष समिति (1982) - PSL के लिए टारगेट्स - लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: 75% - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCBs): 60% (पहले 40%) - घरेलू वाणिज्यिक बैंक और विदेशी बैंक: 40%
माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष	- भारत में पहला माइक्रोफाइनेंस संस्थान: SEWA बैंक (1974) - बैंकों से जुड़े 88% स्वयं सहायता समूह महिलाओं के नेतृत्व में हैं। - शुरु की गई पहलें: स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, आदि।
भारत में विप्रेषण	- पांच देश जहां से भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त हुआ: संयुक्त राज्य अमेरिका (27.7%), UAE, यूनाइटेड किंगडम (UK), सऊदी अरब और सिंगापुर। - भारत के शीर्ष 3 राज्य (2023-24): महाराष्ट्र (20.5%), केरल और तमिलनाडु।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)	- वैधानिक प्रावधान: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 - योगदान: ग्राहक (मूल वेतन का 10%), सरकार (मूल वेतन का 8.5%)
इक्विलाइजेशन लेवी	वैधानिक प्रावधान: वित्त अधिनियम, 2016 और वित्त अधिनियम 2020
किसान उत्पादक संगठन (FPOs)	10,000 FPOs के गठन एवं संवर्धन की योजना: 2020 में शुरू की गई थी। - देश में लगभग 30 लाख किसान FPOs से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था	➔ पहल: बायोसारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव, बायो-नेस्ट स्कीम, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (BIG), सीड (SEED) फंड, आदि। ➔ भारत का लक्ष्य: 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था को 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना। ➔ वर्तमान स्थिति: 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर, GDP में 4.25% का योगदान देती है। ➔ नीतियां और योजनाएं: ➔ BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति 2024, ➔ राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन ➔ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, आदि।
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)	➔ वस्त्र बाजार: 12 सेगमेंट्स (जैसे, स्पोर्ट्स) ➔ तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम: वस्त्र क्षेत्रक के लिए PLI योजना, पी.एम. मित्र योजना, समर्थ योजना, आदि।
राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025	➔ राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई: 4,503 किलोमीटर (सबसे लंबा NW-1 (गंगा)-1,620 किलोमीटर है) ➔ भारत में केवल 3.5% व्यापार जलमार्गों से होता है, जबकि चीन में 47% व्यापार जलमार्गों से होता है। ➔ पहल: भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) 1986, जलमार्ग विकास परियोजना (2014), राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, आदि।
भारत के विकास के लिए कोयला क्षेत्रक	➔ विश्व में पांचवां सबसे अधिक कोयला भंडार भारत में है। साथ ही, भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ➔ भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में कोयले का योगदान: 46.88% (नवंबर 2024 तक) ➔ कोयला भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई राजस्व में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है (2022-23 में 49%)। ➔ शीर्ष तीन राज्य: ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़।
राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)	➔ NPDD: यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। ➔ भारत में दुग्ध उत्पादन: विश्व में सर्वाधिक (लगभग 24.76%) ➔ प्रत्यक्ष रोजगार: 8 करोड़ किसान (अधिकांश महिलाएं)
राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका	क्वांटम प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत द्वारा उठाए गए कदम ➔ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) (2023): इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी (QT) के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, उसका समर्थन करना तथा उसे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा, क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक जीवंत व नवीन इकोसिस्टम का निर्माण करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। ➔ क्वांटम-सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी (QuEST) कार्यक्रम (2018): इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय क्वांटम प्रयोगशालाओं को वित्त-पोषित करके अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना विकसित करना है।
क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन	क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CCM) के बारे में ➔ CCM एक अंतराष्ट्रीय संधि है। यह संधि क्लस्टर म्यूनिशंस/ हथियारों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। ➔ इसे क्लस्टर म्यूनिशंस पर ओस्लो घोषणा-पत्र (2007) के तहत अपनाया गया था। ➔ यह कन्वेंशन 2008 में अपनाया गया था और 2010 में लागू किया गया था। ➔ वैधानिक स्थिति: यह अंतराष्ट्रीय मानवतावादी विधि के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतराष्ट्रीय संधि है। ➔ भारत की स्थिति: भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
गोल्डन डोम	गोल्डन डोम के बारे में ➔ यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों तथा अन्य उन्नत हवाई हमलों के खतरों से अमेरिका की रक्षा करना है। ➔ इसका निर्माण इनरायल की 'आयरन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली से प्रभावित होकर किया जा रहा है। ➔ आयरन डोम एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली का विकास कम दूरी के खतरों से बचने के लिए किया गया है।
जैव ईंधन	➔ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन (Biofuel) उत्पादक देश बन गया है। ➔ जैव ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं, जिनका उत्पादन नवीकरणीय संसाधनों से किया जाता है और इन्हें अन्य जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर या उनके साथ मिश्रित कर उपयोग किया जाता है। ➔ प्रमुख उत्पादक देश: संयुक्त राज्य अमेरिका जैव ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद ब्राजील का स्थान आता है। ➔ इसमें एथेनॉल और बायोडीजल मिश्रण, संपीड़ित बायोगैस (CBG), सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) आदि शामिल हैं।

जैव विविधता विरासत स्थल (BHS)	- कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव को तमिलनाडु का दूसरा BHS घोषित किया गया है। यह डिंडीगुल जिले में अलगमल्लै रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थित है। - राज्य का पहला BHS मदुरै में अरिष्टापट्टी है। - राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव-विविधता महत्त्व वाले क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में BHS के रूप में अधिसूचित कर सकती है। - जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37(1) के तहत अधिसूचित।
भारतीय वन्यजीव संस्थान	- उत्पत्ति: इसे 1982 में स्थापित किया गया था और अप्रैल, 1986 में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। - मुख्यालय: देहरादून। - मंत्रालय: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - गवर्नेस: भारतीय वन्यजीव संस्थान केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता वाली सोसाइटी के तहत प्रशासित होता है।
ओकजोकुल/ ओह-युकुल	- ऐसा माना जाता है कि यह 2014 में जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक रूप से पूर्णतया डेड (मृत) घोषित किया जाने वाला पहला ग्लेशियर है। - अन्य ग्लेशियर जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है: एंडरसन ग्लेशियर, क्लार्क ग्लेशियर और ग्लिसन ग्लेशियर (संयुक्त राज्य अमेरिका); बाउमन ग्लेशियर (न्यूजीलैंड); काल्देरोन ग्लेशियर (इटली); मार्शल सूर ग्लेशियर (अर्जेंटीना); पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर (वेनेजुएला); पिजोल ग्लेशियर (स्विट्जरलैंड); सारेन ग्लेशियर (फ्रांस) और श्वीफनर ग्लेशियर (जर्मनी)।
ब्लू फ्लैग	- विशाखापत्तनम में रुशिकोंडा बीच ने फिर से ब्लू फ्लैग टैग हासिल किया। ज्ञातव्य है कि खराब रखरखाव के कारण रुशिकोंडा से यह टैग वापस ले लिया गया था। - यह आंध्र प्रदेश का एकमात्र ब्लू फ्लैग बीच है। यह भारत के 13 ब्लू फ्लैग बीचों में शामिल है। - कैसे दिया जाता है: समुद्र तटों, मरीनों और संधारणीय नौका विहार पर्यटन को। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग मानक होते हैं। - कौन देता है: डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) द्वारा।
सिनेमा और समाज	सिनेमा में विषय-वस्तु का विनियमन - भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: अश्लील कृत्यों को अपराध घोषित करती है, और इसके लिए जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान करती है। - स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986. - सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952: यह फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित करना अनिवार्य करता है। - भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) (स्व-नियमन).
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट	- रैंकिंग के लिए अपनाए गए मापदंड: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, आदि। - फिनलैंड (पहला स्थान), इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान है। जबकि भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)	IOC के बारे में - IOC एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र निकाय है, जो ओलंपिक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। - मुख्यालय: लॉज़ेन (ओलंपिक राजधानी), स्विट्जरलैंड। - उत्पत्ति: पेरिस में आयोजित प्रथम ओलंपिक कांग्रेस में स्थापित (1894)। - विज़न: खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना।
मानव संवर्धन	- परिभाषा: मानव संवर्धन के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक, कृत्रिम तथा तकनीकी माध्यमों से ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं, जो उसकी संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। - मुख्य विधियाँ/ तरीके: दवाइयों, हार्मोन, इम्प्लांट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आहार संबंधी सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक सर्जरी का उपयोग।
रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR)	- क्रिप्टोकॉरेसी: क्रिप्टोग्राफी और विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाली एक डिजिटल मुद्रा है; क्रिप्टोकॉरेसी पर किसी देश या सरकार या केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता है। - उदाहरण: बिटकॉइन (BTC), एथेरियम (ETH), रिपल (XRP), टैथर (USDT), आदि। - SCR के बारे में: आर्थिक लचीलापन, वित्तीय संप्रभुता को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा/स्वर्ण भंडार की बजाय एक डिजिटल मुद्रा भंडार के रूप में कार्य करता है।
लाइट सुपरसॉलिड	- परिभाषा: यह पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है, जो ठोस जैसी संरचना और घर्षण रहित प्रवाह दोनों को दर्शाती है। - क्वांटम व्यवहार: पार्टिकल्स एक सुव्यवस्थित व क्रिस्टल जैसी ठोस अवस्था में एकत्र या घनीभूत होते हैं, लेकिन वे श्यानता (Viscosity) रहित द्रव की भांति प्रवाह भी करते हैं। - तापमान की स्थिति: पदार्थ की पाँचवीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेन्सेट्स (BECs) बनाने के लिए निरपेक्ष शून्य (0 केल्विन या -273.15°C) के करीब तापमान की आवश्यकता होती है।

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) दवाइयां	परिभाषा: ART का मुख्य उद्देश्य शरीर में वायरस की मात्रा या प्रभाव को बहुत कम स्तर (अनडिटेक्टबल) तक लाना है, जिससे HIV के फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। → इसे "अनडिटेक्टबल=अनट्रांसमिटेबल" (U=U) कहा जाता है। उपचार: हाइली एक्टिव एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (HAART) के तहत 2-4 दवाओं का संयोजन किया जाता है; → उदाहरण: TLD टेबलेट (टेनोफोविर, लैमिवुडिन, और डोल्स्यूटेग्राविर)।
राष्ट्रीय जीन बैंक	जीन बैंक: जीन बैंक ऐसे जैव-भंडार होते हैं, जहां पादपों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित किया जाता है। इनका उद्देश्य जैव विविधता को बचाना और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। जीन बैंकों के प्रकार: → सीड बैंक (बीज बैंक) – जैसे स्वालबाई ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे। → फील्ड जीन बैंक – जीवित पादपों का संरक्षण। → क्रायो-प्रिजर्वेशन बैंक – ऊतक, भ्रूण आदि। पोलन (पराग) और DNA बैंक।
ट्रांसजेनिक जीव	परिभाषा: ट्रांसजेनिक से तात्पर्य ऐसे जीव या कोशिका से है, जिसके जीनोम को किसी अन्य प्रजाति से लिए गए एक या अधिक DNA अनुक्रमों के उस जीनोम में प्रवेश द्वारा उसे बदल दिया गया है। भारत में विनियमन: → पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'नियम, 1989; → जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा विनियमित।
उल्काभ	जब कोई उल्काभ वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर पृथ्वी के धरातल से टकराती है, तो उसे उल्कापिंड कहते हैं। जब उल्काभ पृथ्वी या किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो उल्कापिंड बनते हैं। जब कोई उल्काभ वायुमंडल से गुजरने के बाद भी बच जाता है और पृथ्वी के धरातल से टकराता है, तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है।
ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर एस्ट्रोफिजिक्स (GAIA) फॉर	GAIA के बारे में: उच्च परिशुद्धता के साथ मिल्की वे आकाशगंगा का त्रि-आयामी मानचित्र बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। उद्देश्य: इसे तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की अवस्थिति एवं गति की सटीक माप के माध्यम से एस्ट्रोमेट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था।
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल	2025 में भारत के लिए संभावित सूची में छह स्थलों/स्मारकों को शामिल किया गया। नवीनतम शामिल 6 स्थल/स्मारक निम्नलिखित हैं- → मुदुमल महापाषाण मेन्डिर (तेलंगाना); कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़); विविध राज्यों में स्थित अशोक के अभिलेख; मध्य प्रदेश और ओडिशा का चौसठ योगिनी मंदिर; उत्तर भारत में गुप्तकालीन मंदिर; तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलों के महल-किले।
अशोक के अभिलेख स्थल	मौर्य सम्राट अशोक (268 ई.पू. - 232 ई.पू.) ने अपने शासनकाल के दौरान प्रस्तर, स्तंभों, शिलाओं और गुफा की भित्तियों पर 30 से अधिक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। ये पहले लिखित अभिलेख हैं, जिनमें 14 वृहद शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख और कुछ लघु शिलालेख शामिल हैं। उद्देश्य: शाही आदेश (अधिकतर अभिलेख अशोक के शब्दों में उत्कीर्ण) सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित हैं। इनके माध्यम से अशोक ने कुलीनों, अधिकारियों तथा आम जनता को संबोधित किया था।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (बस्तर, छत्तीसगढ़)	अवस्थिति: यह दक्कन प्रायद्वीप-पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है। स्थापित: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित। प्रमुख नदी: कांगेर नदी। स्थिति: यह खोलाबा नदी के तट पर स्थित है। यह गोदावरी की एक सहायक नदी है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार	विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। 1965 से हर साल भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक कृति के लेखक को हर साल दिया जाता है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	RGM के बारे में यह मिशन 2014 में राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। मंत्रालय: यह केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की योजना है। कार्यान्वयन विभाग: पशुपालन एवं डेयरी विभाग। वित्त पोषण: कुछ अपवादों को छोड़कर, केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज

- ✓ भूगोल
- ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं
अंतर्राष्ट्रीय संबंध



2025

ENGLISH MEDIUM
23 MARCHहिन्दी माध्यम
23 मार्च

2026

ENGLISH MEDIUM
11 MAYहिन्दी माध्यम
11 मई

Live - online / Offline
Classes

Scan the QR CODE to
download VISION IAS app



“You are as strong as your Foundation”

FOUNDATION COURSE GENERAL STUDIES PRELIMS CUM MAINS 2026, 2027 & 2028

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam

- Includes Pre Foundation Classes
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2026, 2027 & 2028

DELHI : 7 MAY, 8 AM | 8 MAY, 11 AM | 16 MAY, 5 PM
20 MAY, 11 AM | 21 MAY, 2 PM | 29 MAY, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 20 MAY, 11 AM | 27 MAY, 6 PM

हिन्दी माध्यम DELHI: 27 मई, 11 AM

AHMEDABAD: 7 JUNE

BENGALURU: 28 MAY

BHOPAL: 26 MAY

CHANDIARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 11 JUNE

JAIPUR: 10 MAY, 18 MAY

JODHPUR: 15 MAY

LUCKNOW: 19 MAY

PUNE: 8 MAY

एक्टिविटी ब्लॉक



12.1. MCQS

1. भारत में क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- राष्ट्रपति कोर्ट-मार्शल के मामलों में क्षमादान प्रदान कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दोषी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई नहीं

2. संसद भाषिणी पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- इसका उद्देश्य संसदीय कार्यों के लिए रियल टाइम बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करना है।
- इस पहल को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- AI-संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म भाषिणी, संसद भाषिणी का समर्थन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

3. फाइव आइज इंटेलिजेंस (FVEY) एलायंस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस एलायंस के सदस्य हैं।
- फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल को 2016 में सदस्य देशों की "गैर-राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थाओं" के रूप में गठित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

4. ओटावा कन्वेंशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) इस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग हो गया है।
- कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज, स्टॉकपिलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी-पर्सनल माइंस एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन को ओटावा कन्वेंशन कहा जाता है।
- यह कन्वेंशन पक्षकार देशों पर किसी भी परिस्थिति में एंटी-पर्सनल माइंस का उपयोग, विकास और भंडारण न करने का दायित्व डालता है।
- भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 1, 2 और 4
- उपर्युक्त सभी

5. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध इंडो-पैसिफिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, इस संदर्भ में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- भारत-ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) पर हस्ताक्षर किए।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- पिच ब्लैक दोनों देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट तथा रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

6. भारत में विप्रेषण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 2023-24 में, भारत में विप्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत संयुक्त अरब अमीरात था।
- पिछले चार वर्षों में भारत में विप्रेषण में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी कम हुई है।
- 2021 में केरल के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विप्रेषण की भागीदारी 35% से अधिक थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3

7. 'इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2025' के अनुसार भारत के जैव-अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जैव-अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4% से अधिक का योगदान देती है।
2. 2024 में भारत में इथेनॉल मिश्रण 15% तक पहुँच गया।
3. भारत वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में 10% से भी कम का योगदान देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

8. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्वांटम-की-डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) एन्क्रिप्शन कीज़ के सुरक्षित संचरण को सक्षम बनाता है।
2. क्वांटम कंप्यूटिंग में स्वायत्त सैन्य प्रणालियों की बढ़ोतरी करने की क्षमता है।
3. पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) को परंपरागत कंप्यूटरों द्वारा हमलों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया है।
4. चीन का मिसाइल उपग्रह क्वांटम आधारित सुरक्षित संचार का प्रदर्शन करने वाला पहला उपग्रह है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) केवल 1, 2 और 4

9. 'भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024' रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 'प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020' के तहत संचालित किया गया था।
2. उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की डॉल्फिन की सबसे अधिक आबादी है, उसके बाद बिहार का स्थान है।
3. सिंधु नदी की डॉल्फिन की संख्या चिंताजनक रूप से कम है, जिसके लिए तत्काल संरक्षण उपायों की आवश्यकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

10. भारत में एशियाई शेरों के संरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IUCN ग्रीन स्टेटस असेसमेंट ने एशियाई शेरों को उनकी ऐतिहासिक सीमा में सीमित पारिस्थितिक कार्यक्षमता के कारण "बहुत अधिक गिरावट" के रूप में वर्गीकृत किया है।
2. प्रोजेक्ट लॉयन के तहत स्वीकृत नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ (NRC-W) वन्यजीवों से संबंधित रोगों की निगरानी करने और संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए गुजरात में स्थापित किया गया है।
3. गिर भू-क्षेत्र, एशियाई शेरों का एकमात्र वर्तमान पर्यावास है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसकी विशेषता है और मालधारी आदिवासी समुदाय इस क्षेत्र में निवास करते हैं।
4. उप-प्रजाति नोर्दन लायन (पैंथेरा लियो लियो), जिसमें एशियाई शेर शामिल हैं, उत्तरी और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1 और 4

11. फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट द्वारा जारी '2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विज़न (GFV)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट (FDA) को 2015 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स (NYDF) प्रोग्रेस असेसमेंट के रूप में स्थापित किया गया था।
2. NYDF एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जिसका समर्थन भारत ने 2014 के जलवायु शिखर सम्मेलन में किया था।
3. 2030 GFV की प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों में से एक में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) कोई नहीं

12. महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा फोकस क्षेत्र नहीं है?

- (a) डिजिटल क्रांति और डिजिटल लैंगिक अंतराल को दूर करना
- (b) बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से गरीबी से मुक्ति
- (c) समुदाय के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के माध्यम से शून्य हिंसा
- (d) महिलाओं की सुरक्षा का समर्थन करने के लिए सैन्य खर्च में वृद्धि

13. हाल की सरकारी पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य महिला छात्राओं के बीच मेंटरशिप, कौशल विकास और उद्यम निमण के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
2. पीएम-युवा 3.0 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों के बीच साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है।
3. राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) पीएम-युवा 3.0 कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

14. तकनीकी उद्योग में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द 'AI वॉशिंग', निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है?

- (a) पर्यवेक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से AI एल्गोरिदम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया
- (b) गैर-डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह से स्वायत्त AI फ्रेमवर्क से बदलना
- (c) निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI सिस्टम की इथिकल ऑडिटिंग
- (d) नवाचार की झूठी भावना पैदा करने के लिए AI के उपयोग के बारे में भ्रामक दावे

15. क्रिप्टोकॉरेसी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- क्रिप्टोकॉरेसी राष्ट्रीय बैंकों द्वारा प्रबंधित केंद्रीय रूप से जारी किए गए डिजिटल टोकन हैं।
- बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकॉरेसी ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती हैं और विकेंद्रीकृत, सीमा से परे लेनदेन प्रदान करती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

16. अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा लैंग्रैजियन पॉइंट्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

- सूर्य के निकट के क्षेत्र जहाँ उच्च-ऊर्जा युक्त सौर ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं
- पृथ्वी की कक्षा में सबसे मजबूत चुंबकीय दृष्टिकोण वाले स्थान
- ऐसे बिंदु जहाँ गुरुत्वाकर्षण और कक्षीय गति स्थिर स्थिति के लिए संतुलन बनाती हैं
- उच्च वेग के कारण अंतरग्रहीय मिशन लॉन्च करने के लिए आदर्श क्षेत्र

17. HIV और एड्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- HIV सुइयों के साझाकरण और असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है।
- एटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) HIV संक्रमण के प्रबंधन और इसके एड्स में परिवर्तित होने में देरी करने में मदद करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1, न ही 2

18. भारत में महापाषाण स्थलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- मुदुमल महापाषाण स्थल खगोलीय वेधशालाओं और उरसा मेजर जैसे नक्षत्रों के चित्रण के लिए जाना जाता है।
- लोहे की वस्तुओं के साथ सबसे पुराने महापाषाण समाधि स्थल

तेलंगाना में पाए गए थे।

- काले और लाल (BRW) रंग के मुदभांड आमतौर पर भारत में महापाषाण संस्कृतियों से जुड़े होते हैं।
- मेन्हिर जैसी महापाषाण संरचनाओं का उपयोग विशेष रूप से समाधि स्थलों के उद्देश्यों के लिए किया जाता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 4
- केवल 1, 2 और 3
- केवल 1, 3 और 4

19. ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- इसे पहली बार 1965 में दिया गया था, हालांकि भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना 1944 में हुई थी।
- यह पुरस्कार केवल भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।
- 2013 से अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्यिक कृतियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- केवल भारतीय नागरिक ही इस पुरस्कार को प्राप्त करने के पात्र हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1, 2 और 4
- केवल 1, 3 और 4
- केवल 2 और 3
- 1, 2, 3 और 4

20. राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन कौन-सा मंत्रालय कर रहा है?

- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (True/false Statements)

- बैंगलोर सिद्धांत भारत में कार्यकारी आचरण के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। (T/F)
- जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख पूर्व-उपाय है। (T/F)
- स्क्वाड एलायंस एक अनौपचारिक मिनिस्टरल गठबंधन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। (T/F)
- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 1997 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका विजन 1995 में नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान सामने आया था। (T/F)
- उज्बेकिस्तान (2024), संयुक्त अरब अमीरात (2024) वे देश हैं जिनके साथ भारत ने द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। (T/F)
- भारत वैश्विक स्तर पर विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, देश में 2024 में 100 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रवाह हुआ। (T/F)
- भारत में कोयला क्षेत्रक देश के ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, भारत की स्थापित क्षमता का 50% से अधिक कोयला आधारित

है। (T/F)

- कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए 'अपलिक इनिशिएटिव' की स्थापना 2020 में डेलॉइट और सेल्सफोर्स के सहयोग से विश्व आर्थिक मंच द्वारा की गई थी। (T/F)
- भारत अब तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है, जिसे यूक्रेन और रूस ने पीछे छोड़ दिया है। (T/F)
- C-DOT दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। (T/F)
- अश्विनी DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक सॉलिड स्टेट तकनीक पर आधारित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्केन्ड फेज़ एरे रडार है। (T/F)
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 की धारा 38V के तहत केंद्र सरकार द्वारा बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किया जाता है। (T/F)
- IQAir द्वारा वर्ष 2024 के लिए वायु गुणवत्ता की वैश्विक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई। (T/F)
- अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट (ACC) पृथ्वी पर सबसे मजबूत पवन-चालित धारा है, जो अंटार्कटिका के चारों ओर वामावर्त घूमती

है। (T/F)

15. सुपरसॉलिड पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है जो ठोस जैसी संरचना और घर्षण रहित प्रवाह दोनों को प्रदर्शित करती है। (T/F)
16. सैटेलाइट इंटरनेट अवसंरचना की सीमाओं के कारण दूरस्थ या अवस्थिति-स्वतंत्र क्षेत्रों में कवरेज प्रदान नहीं कर सकता है। (T/F)
17. जीन बैंक जैव-भंडार हैं जो जैव विविधता को बचाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पादपों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करते हैं। (T/F)
18. विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। (T/F)
19. चेटीचंड जैन समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, इसे झूलेलाल जयंती के रूप में भी जाना जाता है। (T/F)
20. गीत गावई को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। (T/F)

12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions)

1. भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्रों पर चर्चा कीजिए। उनसे जुड़ी चिंताओं को उजागर कीजिए तथा जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता दोनों को बनाए रखने के लिए एक संतुलित रूपरेखा का सुझाव दीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
2. द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) क्या है? यह निवेशक संरक्षण और राष्ट्र की संप्रभुता को कैसे संतुलित करती है? (150 शब्द, 10 अंक)
3. IORA की प्रमुख महत्वपूर्ण पहलें क्या हैं? वे क्षेत्रीय सहयोग में कैसे योगदान करती हैं? (150 शब्द, 10 अंक)
4. महासागर (MAHASAGAR) क्या है? यह भारत के मूल SAGAR विजन के दायरे का विस्तार कैसे करता है? (150 शब्द, 10 अंक)
5. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
6. कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भूमिका का आकलन कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
7. मरीन हीटवेक्स में हाल ही में हुई वृद्धि के कारणों और प्रभावों का परीक्षण कीजिए। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, आजीविका और भारतीय मानसून जैसे क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
8. सिनेमा समाज का दर्पण और निर्माता दोनों हैं। भारतीय समाज पर सिनेमा के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, सिनेमा द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का समाधान करने में नियामक तंत्र की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
9. भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में सैटेलाइट इंटरनेट की क्षमता पर चर्चा कीजिए। इसके व्यापक उपयोग से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ क्या हैं? (150 शब्द, 10 अंक)
10. यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल मानवता की साझा सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के साथ भारत के जुड़ाव का परीक्षण कीजिए और भारत की विविध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत की अनंतिम सूची में हाल ही में जोड़े गए स्थलों के महत्व पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
11. भारत में बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। इस संबंध में नियामकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द, 15 अंक)
12. भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (PSL) की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
13. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों को आकार देने में क्वांटम कंप्यूटिंग की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वांटम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और रणनीतिक तैयारियों के लिए रोडमैप सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
14. ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण आर्थिक विकास के संदर्भ में विश्व के तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक के रूप में भारत के उभरने के महत्व पर चर्चा कीजिए। जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाने में प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और इन चुनौतियों का समाधान करने में सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
15. भारत में भूवैज्ञानिक अनुसंधान और खनिज संसाधन के आकलन को आगे बढ़ाने में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की भूमिका के 175 वर्षों के योगदान के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। चर्चा कीजिए कि आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण में GSI की पहल राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित होती है। (250 शब्द, 15 अंक)
16. किशोरों का सोशल मीडिया स्पेस में अनियंत्रित संपर्क उनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। इससे संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और किशोरों के लिए डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
17. भारत में पारिवारिक संस्था में बदलाव के गहरे सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ हैं। इन परिवर्तनों को प्रेरित करने वाले कारकों और समाज पर उनके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इन परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के उपाय भी सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
18. मानव संवर्धन से संबंधित उभरती चिंताओं पर चर्चा कीजिए। नैतिक, समावेशी और संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए भारत को अपने विनियमन को किस तरह अपनाना चाहिए? (250 शब्द, 15 अंक)
19. डिजिटल वित्तीय लचीलेपन के लिए एक उपकरण के रूप में रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR) की अवधारणा को परखा जा रहा है। भारत में रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व को अपनाने के अवसरों और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
20. अशोक के शिलालेख भारतीय इतिहास के सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक हैं। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक विचारधारा, प्रशासनिक दृष्टि और सांस्कृतिक लोकाचार को समझने के लिए प्राथमिक स्रोतों के रूप में उनके महत्व का आकलन करने हेतु उनके भौगोलिक वितरण, भाषाई विविधता और सामग्री का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

12.4. एथिक्स केस स्टडी (Ethics Case Studies)

1. आप भारत के एक ग्रामीण जिले में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात हैं, जहाँ हाल ही में व्हाट्सएप पर एक झूठी अफवाह फैली है, जिसमें दावा किया गया है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए स्थानीय जल आपूर्ति में जहर मिला दिया है। इस गलत सूचना के कारण तनाव बढ़ गया है, कुछ ग्रामीण पानी पीने से इनकार कर रहे हैं और अन्य कई व्यक्ति आरोपी समुदाय के खिलाफ हिंसा की धमकी दे रहे हैं। स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है, और सांप्रदायिक हिंसा का खतरा बढ़ रहा है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस स्थिति में आपके सामने आने वाली नैतिक और प्रशासनिक चुनौतियों की पहचान कीजिए। इस संकट का समाधान करने के लिए आप अपनी कारवाइयों को किस प्रकार प्राथमिकता देंगे?
 - अनुनय के सिद्धांतों (लोकनीति, भावनात्मकता और तर्क) का उपयोग करते हुए, गलत सूचना का मुकाबला करने और ग्रामीणों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए एक रणनीति तैयार कीजिए।
 - शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, आप अपने जिले में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से दीर्घकालिक उपाय प्रस्तावित करेंगे?
2. XYZ जिले में पिछले दशक में तेजी से आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। औद्योगिक और तकनीकी प्रगति तथा शहरीकरण में पर्याप्त निवेश को इसका कारण बताया गया है। जिले की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और यह क्षेत्र व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र बन गया है। सरकारी पहलों से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। हालांकि, इन सकारात्मक रुझानों के बावजूद, हाल के अध्ययनों से यहां के निवासियों, विशेष रूप से युवाओं के बीच तनाव, चिंता संबंधी विकारों, अवसाद, सामाजिक अलगाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव, असफलता का डर और भावनात्मक लचीलेपन की कमी इस मानसिक स्वास्थ्य संकट को और बढ़ा रहे हैं।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, आर्थिक संवृद्धि के बावजूद अप्रसन्नता में हो रही वृद्धि को दूर करने के लिए कौन-कौन से नीतिगत हस्तक्षेप किए जा सकते हैं? गवर्नेंस, सार्वजनिक नीति और सामुदायिक विकास के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
- प्रसन्नता मानव विकास का एक अनिवार्य घटक है। नीतिगत लक्ष्य के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या नीतिगत फ्रेमवर्क में प्रसन्नता को भी आर्थिक संवृद्धि की तरह समान महत्व दिया जाना चाहिए?

HEARTIEST
Congratulations
TO ALL THE SELECTED CANDIDATES

10 IN TOP 10
Selections in CSE 2024
from various programs of
VisionIAS

AIR
1



SHAKTI DUBEY

AIR
2



HARSHITA GOYAL

AIR
3



DONGRE ARCHIT PARAG

AIR
4



SHAH MARGI CHIRAG

AIR
5



AAKASH GARG

AIR
6



KOMAL PUNIA

AIR
7



AAYUSHI BANSAL

AIR
8



Raj Krishna Jha

AIR
9



**ADITYA VIKRAM
AGARWAL**

AIR
10



MAYANK TRIPATHI

उत्तर और व्याख्या



13.1. MCQs के उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explanation)

1. उत्तर: A

व्याख्या:

- कथन 1: सही है, अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कोर्ट-मार्शल के मामलों तक फैली हुई है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161) कोर्ट-मार्शल के मामलों तक विस्तारित नहीं है।
- कथन 2: सही नहीं है, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से जुड़े मामलों में क्षमा प्रदान कर सकते हैं।
- कथन 3: सही नहीं है, दया याचिकाएं और क्षमादान अनुग्रह के विवेकाधीन कार्य करते हैं, ये लागू करने योग्य कानूनी अधिकार नहीं हैं।

2. उत्तर: B

व्याख्या:

- कथन 1: संसद भाषिणी पहल का उद्देश्य रियल टाइम भाषा अनुवाद और संचालन को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से संसद में बहुभाषी समर्थन को बढ़ाने हेतु AI का लाभ उठाना है।
- कथन 2: सही नहीं है, इस पहल को लोक सभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, न कि संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा।
- कथन 3: सही है, भाषिणी MeitY द्वारा निर्मित एक AI-संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है और यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है।

3. उत्तर: C

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस गठबंधन के सदस्य हैं।
- कथन 2 सही है: फाइव आइज इंटेलेजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल का 2016 में गठन किया गया ताकि सदस्य देशों की "गैर-राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थाओं" के रूप में कार्य किया जा सके।

4. उत्तर: B

व्याख्या:

- कथन 1 सही नहीं है: उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग नहीं हुआ है, केवल कुछ सदस्य ही अलग होने की योजना बना रहे हैं।
- कथन 2 सही है: 'कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज, स्टॉकपिलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी-पर्सनल माइंस एंड ऑन दैरर डिस्ट्रक्शन' को ओटावा कन्वेंशन कहा जाता है।
- कथन 3 सही है: यह कन्वेंशन पक्षकार देशों को किसी भी परिस्थिति में एंटी-पर्सनल माइंस का उपयोग, विकास या भंडारण न करने हेतु बाध्य करता है।

कथन 4 सही नहीं है: भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

5. उत्तर: A

व्याख्या:

- कथन 1 सही नहीं है: भारत - ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) पर हस्ताक्षर किए।
- कथन 2 सही है: भारत - ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- कथन 3 सही है: 'पिच ब्लैक' दोनों देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- कथन 4 सही है: भारत - ऑस्ट्रेलिया ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट तथा रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं।

6. उत्तर: B

व्याख्या:

- कथन 1 सही नहीं है: 2023-24 (27.7%) में संयुक्त अरब अमीरात नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा।
- कथन 2 सही है: GCC की हिस्सेदारी कम होकर 38% रह गई है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 50% से अधिक हो गई है।
- कथन 3 सही है: 2021 में, रेमिटेस केरल के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 36% से अधिक था।

7. उत्तर: A

व्याख्या:

- दुनिया की 65% वैक्सीन का उत्पादन भारत में होता है, जो 10% से कम नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, कथन 1 और 2 तथ्यात्मक रूप से सही हैं।

8. उत्तर: D

व्याख्या:

- कथन 1: सही है। QKD क्वांटम गुणों का उपयोग करके एन्क्रिप्शन कीज़ के सुरक्षित संचरण की अनुमति देता है।
- कथन 2: सही है। क्वांटम-आधारित AI स्वचालित सैन्य ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम्स के संचालन को बेहतर बना सकते हैं।
- कथन 3: सही नहीं है। PQC को क्वांटम कंप्यूटर हमलों का विरोध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि पारम्परिक हमलों का।
- कथन 4: सही है। चीन के मिसियस उपग्रह (2016) ने पहला क्वांटम आधारित सुरक्षित लंबी दूरी के संचार को संभव किया है। इसलिए, कथन 1, 2 और 4 सही हैं।

9. उत्तर: D

व्याख्या:

- जैसा कि आकलन में बताया गया है, यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 के तहत किया गया था।
- 'भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024' रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की सबसे ज्यादा आबादी दर्ज की गई है, इसके बाद बिहार का स्थान है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंधु नदी डॉल्फिन की संख्या चिंताजनक रूप से कम है। इसके संरक्षण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जो सही भी है।

10. उत्तर: A

व्याख्या:

- **सही है:** IUCN ग्रीन स्टेटस असेसमेंट में एशियाई शेरों को मानवीय प्रभावों के कारण उनकी पारिस्थितिक भूमिका को सीमित करने के कारण "बहुत अधिक गिरावट" श्रेणी में रखा है, जैसा कि आकलन से पता चला है।
- **सही है:** समाचारों के अनुसार, वन्यजीव रोगों पर नज़र रखने के लिए प्रोजेक्ट लॉयन के तहत गुजरात के जूनागढ़ जिले में **नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ (NRC-W)** की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।
- **सही नहीं है:** गिर क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, न कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जैसा कि गिर क्षेत्र खंड में बताया गया है। यहां वास्तव में मालधारी जनजातीय समुदाय निवास करता है, लेकिन पर्यावास का विवरण सही नहीं है।
- **सही नहीं है:** जबकि नॉर्डन लायन की उप-प्रजाति (पैंथेरा लियो लियो) में एशियाई शेर शामिल हैं, यह वर्तमान में उत्तरी और मध्य अफ्रीका में नहीं पाया जाता है; वितरण विवरण के अनुसार, एशियाई शेर गुजरात के गिर क्षेत्र तक ही सीमित हैं।

11. उत्तर: B

व्याख्या:

- **सही है:** **फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट (FDA)** को 2015 में **न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स (NYDF) प्रोग्रेस असेसमेंट** के रूप में स्थापित किया गया था, जैसा कि प्रदान की गई जानकारी में बताया गया है।
- **सही नहीं है:** NYDF स्वैच्छिक प्रकृति का है और भारत द्वारा अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया है, जैसा कि जानकारी में बताया गया है।
- **सही है:** देशज लोगों (IPs) और स्थानीय समुदायों (LCs) के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विज़न के अंतर्गत आठ प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों में से एक है।

12. उत्तर: D

व्याख्या:

- बीजिंग + 30 एक्शन एजेंडा डिजिटल क्रांति, गरीबी से मुक्ति, हिंसा की समाप्ति, निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण और समान शक्ति, शांति और सुरक्षा और क्लाइमेट जस्टिस सहित कई प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों पर प्रकाश डालता है।

13. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर स्वावलंबिनी कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को उद्यमिता कौशल, **संसाधन और मार्गदर्शन** उपलब्ध कराकर उन्हें सक्षम बनाना है। इसे NIESBUD द्वारा लागू किया जाएगा।
- **कथन 2 सही नहीं है:** युवा लेखकों को सलाह देने और पढ़ने व साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने PM-YUVA 3.0 लॉन्च किया।
- **कथन 3 सही नहीं है:** PM-YUVA 3.0 के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत है।

14. उत्तर: D

व्याख्या:

- AI वॉशिंग में AI एकीकरण को बढ़ा-चढ़ाकर या गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है - उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ताओं या निवेशकों को गुमराह करने के लिए बुनियादी स्वचालन उपकरण को "AI-संचालित" कहना, पर्यावरण क्षेत्र में ग्रीनवॉशिंग के समान है।

15. उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1:** सही नहीं है: क्रिप्टोकॉइन्स राष्ट्रीय बैंकों द्वारा केंद्रीय रूप से जारी या प्रबंधित नहीं की जाती हैं। वे विकेंद्रीकृत डिजिटल संपत्ति हैं। केंद्रीय बैंक CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) जारी करते हैं, जो क्रिप्टोकॉइन्स से अलग है।
- **कथन 2:** सही है: बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकॉइन्स ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती हैं, जो विकेंद्रीकृत है। वे बिचौलियों के बिना स्वतंत्र रूप से पीयर-टू-पीयर लेन-देन को सक्षम करते हैं।

16. उत्तर: C

व्याख्या:

- लैंग्जियन पॉइंट्स वे स्थान हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल और कक्षीय गति दोनों बराबर होते हैं, जिससे दो खगोलीय पिंडों के सापेक्ष उपग्रहों की स्थिर स्थिति बनती है।

17. उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1: सही है:** HIV असुरक्षित यौन संबंध, दूषित सुइयों को साझा करने, संक्रमित रक्त आधान और प्रसव या स्तनपान के दौरान संक्रमित मां से बच्चे में संक्रमण के माध्यम से फैलता है।
- **कथन 2: सही है:** एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) HIV के लिए मानक उपचार है। यह संक्रमण को ठीक नहीं करता है, लेकिन वायरस की मात्रा या प्रभाव को बहुत कम स्तर तक लाने, प्रतिरक्षा कार्य को बनाए रखने और एड्स की शुरुआत में देरी या रोकथाम में मदद करता है।

18. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** तेलंगाना के मुदुमल मेन्डिर में खगोलीय वेधशालाओं की विशेषता है और यह सप्तऋषि (Ursa Major), सिंह (Leo) तारामंडल जैसे नक्षत्रों को विशिष्ट रूप से दर्शाता है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** कर्नाटक के ब्रह्मगिरि क्षेत्र में स्थित पिकलीहल और हल्लूर नामक स्थानों पर ऐसे सबसे पुराने महापाषाणिक शवाधान खोजे गए हैं, जिनमें लौह युग की शुरुआती पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह तेलंगाना में नहीं खोजे गए।
- **कथन 3 सही है:** काले और लाल मृदभांड (BRW) भारत में महापाषाण संस्कृतियों से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता है।
- **कथन 4 सही नहीं है:** महापाषाण संरचनाओं ने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की - जबकि कुछ शवाधान थे, जैसे मेन्डिर का उपयोग स्मारक या खगोलीय वेधशालाओं के रूप में किया जाता था।

19. उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** ज्ञानपीठ पुरस्कार वास्तव में पहली बार 1965 में शुरू किया गया था, जबकि **भारतीय ज्ञानपीठ** की स्थापना **1944** में हुई थी।
- **कथन 2 गलत है:** यह पुरस्कार भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक कृति को मान्यता देता है, न कि केवल आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को।
- **कथन 3 सही है:** 2013 से **अंग्रेजी भाषा** में लिखित साहित्यिक कृतियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार में शामिल किया गया है।
- **कथन 4 सही है:** ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए पात्रता केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है।

20. उत्तर: A

व्याख्या:

- **विकल्प 1 सही है:** राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था।
- **मंत्रालय:** केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
- **कार्यान्वयन विभाग:** पशुपालन और डेयरी विभाग।

13.2. दृ/फाल्स स्टेटमेंट्स के उत्तर
(True/False Answers)

उत्तर:

1. F	2. F	3. F	4. T	5. T	6. T
7. F	8. T	9. F	10. T	11. T	12. F
13. T	14. F	15. T	16. F	17. T	18. T
19. F	20. T				

13.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण

1. दृष्टिकोण

परिचय: न्यायिक जवाबदेही के बारे में संक्षेप में बताइए।

मुख्य भाग: जवाबदेही को मजबूत करने के लिए मौजूदा तंत्र, चिंताओं और उपायों का उल्लेख कीजिए।

निष्कर्ष: संक्षेप में बताइए कि जन विश्वास और न्यायपालिका की वैधता बनाए रखने के लिए न्यायिक जवाबदेही कैसे अनिवार्य है।

2. दृष्टिकोण

परिचय: कुछ उदाहरणों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) को संक्षेप में परिभाषित कीजिए।

मुख्य भाग: द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) और निवेशक संरक्षण एवं राष्ट्र की संप्रभुता को संतुलित करने की इसकी आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष: द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के महत्व और सुधारों का उल्लेख कीजिए।

3. दृष्टिकोण

परिचय: IORA शब्द और इसकी पृष्ठभूमि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए।

मुख्य भाग:

➤ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) की प्रमुख प्रमुख पहलों और भारत के आस-पास के क्षेत्रीय सहयोग पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताइए।

➤ IORA और अन्य उपायों द्वारा प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दीजिए।

निष्कर्ष: IORA और भारत के SAGAR/सागर के साथ इसके संरेखण के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

4. दृष्टिकोण

परिचय: भारतीय समुद्री सहयोग की क्या पहल हैं और इसके विकास के बारे में लिखिए।

मुख्य भाग: महासागर/MAHASAGAR और सागर/SAGAR के बारे में तथा SAGAR की तुलना में MAHASAGAR की विस्तारित भूमिका के बारे में भी बताइए।

निष्कर्ष: कूटनीति में दोनों पहलों के महत्व का उल्लेख कीजिए।

5. दृष्टिकोण

परिचय: भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में लिखिए।

मुख्य भाग: चुनौतियों को शामिल करते हुए उपलब्ध अवसरों और इसे प्राप्त करने के उपायों का भी उल्लेख कीजिए।

निष्कर्ष: दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता पर जोर दीजिए।

6. दृष्टिकोण:

परिचय: FPOs को संक्षेप में परिभाषित कीजिए।

मुख्य भाग: कृषि में FPO की भूमिका, किसानों पर उनके प्रभाव और सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

निष्कर्ष: FPO की क्षमता और सरकारी सहायता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

7. दृष्टिकोण

परिचय: हाल ही में समुद्री हीटवेव में हुई वृद्धि का संदर्भ देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए, साथ ही इस शब्द को परिभाषित कीजिए।

मुख्य भाग: इस मुद्दे से निपटने के लिए अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों पर चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष: इससे निपटने के लिए मौजूदा नियमों का उल्लेख कीजिए, साथ ही सुझाव दीजिए कि क्या और किस प्रकार सुधार किया जा सकता है।

8. दृष्टिकोण

परिचय: सिनेमा क्या है, इसे परिभाषित कीजिए।

मुख्य भाग: सिनेमा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। इससे हुए परिवर्तनों से निपटने के लिए विनियामक तंत्र का भी उल्लेख कीजिए।

निष्कर्ष: सिनेमा के महत्व और इसकी उभरती भूमिका के बारे में संक्षेप में प्रकाश डालिए।

9. दृष्टिकोण

परिचय: सैटेलाइट इंटरनेट को संचार उपग्रहों के माध्यम से वितरित वायरलेस इंटरनेट के रूप में परिभाषित कीजिए, जो स्थान-स्वतंत्र वैश्विक कवरेज प्रदान करता है तथा दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

➤ ग्रामीण और दूरस्थ के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसे अवसरों पर प्रकाश डालिए, जहाँ फाइबर या सेलुलर नेटवर्क की कमी है, आदि।

➤ फिर वैज्ञानिक अवलोकन और तारों को देखने आदि को प्रभावित करने वाली खगोलीय घटनाओं जैसी चिंताओं को कवर कीजिए।

निष्कर्ष: उत्तर के अंत में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है - समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए उपग्रह इंटरनेट का लाभ उठाना, जबकि दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी, विनियामक और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना।

10. दृष्टिकोण:

परिचय: यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल क्या हैं, और इसके तहत भारत की स्थिति का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए।

मुख्य भाग: हाल ही में भारत से शामिल किए गए स्थलों का उल्लेख कीजिए, और इसके महत्व के बारे में लिखिए।

निष्कर्ष: संरक्षण प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा उल्लेख कीजिए कि और क्या किया जा सकता है।

11. दृष्टिकोण

परिचय: बिग टेक कंपनियों और हालिया मामलों के बारे में संक्षेप में बताइए।

मुख्य भाग: बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने की आवश्यकता

के बारे में चर्चा कीजिए। विनियामकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष: डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों के बारे में संक्षेप में प्रकाश डालिए।

12. दृष्टिकोण

परिचय: समावेशी विकास के लिए इसके उद्देश्य के साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण (PSL) को संक्षेप में परिभाषित कीजिए।

मुख्य भाग: PSL की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए इसकी चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए और सुधार भी सुझाइए।

निष्कर्ष: समावेशी विकास के लिए PSL के महत्व और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

13. दृष्टिकोण

परिचय: क्वांटम कंप्यूटिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी प्रासंगिकता को संक्षेप में परिभाषित कीजिए।

मुख्य भाग

- प्रभाव के प्रमुख क्षेत्र (जैसे, क्रिप्टोग्राफी, खुफिया जानकारी, रक्षा प्रणालियाँ)
- प्रमुख चुनौतियाँ (जैसे, कार्यबल, निवेश अंतराल, तकनीक अपरिपक्वता)
- सिफारिशें (जैसे, PQC को अपनाना, टारस्क फोर्स, वैश्विक सहयोग)

निष्कर्ष: भारत के भविष्य की सुरक्षा और विकास लक्ष्यों के लिए क्वांटम तकनीक के रणनीतिक महत्व पर जोर दीजिए।

14. दृष्टिकोण

परिचय: भारत के जैव ईंधन ऊर्जा के उत्पादन का संदर्भ प्रदान कीजिए।

मुख्य भाग: इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, तथा इससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

निष्कर्ष: जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए तथा आगे की राह का उल्लेख कीजिए।

15. दृष्टिकोण

परिचय: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसका उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए।

मुख्य भाग: भारत में अनुसंधान मूल्यांकन में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, तथा आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण में यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष: इसके आगे आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए तथा उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

16. दृष्टिकोण

परिचय: किशोरों के बीच सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग का संक्षेप में परिचय दीजिए।

मुख्य भाग: किशोरों पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा कीजिए।

इसकी चुनौतियों तथा आगे की राह पर भी चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष: किशोरों को सोशल मीडिया से संतुलन बनाने में मदद करने के लिए रणनीतियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

17. दृष्टिकोण

परिचय: परिवार संस्था की पारंपरिक और नवीन प्रवृत्तियों के बारे में संक्षेप में बताइए।

मुख्य भाग: परिवार संस्था में बदलाव के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। इस परिवर्तन के पीछे निहित कारणों पर भी चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष: सिनेमा के महत्व और उसकी उभरती भूमिका के बारे में संक्षेप में बताइए।

18. दृष्टिकोण

परिचय: मानव संवर्धन में प्राकृतिक सीमाओं से परे तकनीक-संचालित सुधार शामिल हैं; 2033 तक इस उद्योग का आकार बढ़कर 348.5 बिलियन डॉलर तक हो जाने की संभावना है

मुख्य भाग:

➤ **चिंताएं:** असमानता, पहचान का जोखिम, बिना सहमति के उपयोग, स्वास्थ्य प्रभाव, पर्यावरणीय दबाव और आनुवंशिक विविधता।

➤ **विनियामक आवश्यकता:** नैतिक निरीक्षण, कानूनी स्पष्टता, समावेशी पहुँच और वैश्विक संरक्षण आवश्यक हैं।

निष्कर्ष: एक संतुलित विनियामक मार्ग जिम्मेदार नवाचार को सक्षम करते हुए मानवीय मूल्यों की रक्षा कर सकता है।

19. दृष्टिकोण

परिचय: हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किए गए, रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR) को वित्तीय लचीलेपन और डिजिटल संप्रभुता के उद्देश्य से राज्य द्वारा आयोजित क्रिप्टो स्टॉकपाइल के रूप में परिभाषित कीजिए।

मुख्य भाग:

➤ **अवसर:** विविधीकरण, विप्रेषण क्षमता, तकनीकी रूप से अग्रणी और वैश्विक प्रणालियों पर निर्भरता में कमी पर प्रकाश डालिए।

➤ **चुनौतियाँ:** अस्थिरता, RBI की आपत्तियाँ, कानूनी कमियाँ, साइबर जोखिम और सार्वजनिक विश्वास के मुद्दों पर जोर देना।

➤ **आगे की राह:** पायलट आवंटन, स्पष्ट विनियमन, सुरक्षित अभिरक्षा अवसंरचना और वैश्विक प्रवृत्तियों के साथ संरेखण का सुझाव दीजिए।

निष्कर्ष: वित्तीय स्थिरता के साथ नवाचार को संतुलित करने के लिए एक सतर्क, उपयोगिता-संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दीजिए।

20. दृष्टिकोण:

परिचय: अशोक के शिलालेखों और उनकी अवस्थिति के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिए।

मुख्य भाग: मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक विचारधारा, प्रशासनिक दृष्टि और सांस्कृतिक लोकाचार को समझने के लिए इनका विश्लेषण कीजिए।

निष्कर्ष: आज के युग में शासन के लिए सीख का उल्लेख कीजिए।

13.4. केस स्टडीज़ के प्रति दृष्टिकोण

1. दृष्टिकोण

- **परिचय:** स्थिति को झूठी अफवाह से प्रेरित सांप्रदायिक हिंसा के मामले के रूप में परिभाषित कीजिए, जो सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय और उत्तरदायी शासन की नैतिक चिंताओं को बढ़ाता है।
- **मुख्य भाग:**
 - ➔ **चुनौतियां:** सामाजिक सद्भाव को नुकसान, निदोष समुदायों की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की आजादी और गलत सूचना नियंत्रण को संतुलित करना।
 - ➔ **तत्काल कार्रवाई:** तथ्यों को स्पष्ट कीजिए, सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, स्थानीय नेताओं को शामिल कीजिए और जनता को आश्वस्त करने के लिए जल की जांच करवाएं।
 - ➔ **अनुनय रणनीति:**
 - ❖ **लोकाचार:** विश्वसनीय अधिकारियों और डॉक्टरों को जांच में शामिल कीजिए।
 - ❖ **संवेदना:** एकता और साझा दुख की अपील।
 - ❖ **लोग्स:** सत्यापित जांच रिपोर्ट और तथ्य साझा कीजिए।
 - ➔ **दीर्घकालिक उपाय:** डिजिटल साक्षरता, सामुदायिक जागरूकता अभियान और प्रारंभिक अफवाह पहचान तंत्र को बढ़ावा देना।
 - ➔ **निष्कर्ष:** झूठी अफवाह से फैली हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय शासन और सामुदायिक जुड़ाव पर काम कीजिए।

2. दृष्टिकोण

- **परिचय:** उस मामले की व्याख्या कीजिए, जहां XYZ जिले में आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, विशेष रूप से युवाओं में।
- **मुख्य भाग:**
 - ➔ भौतिक प्रगति और भावनात्मक कल्याण के बीच दुविधा का उल्लेख कीजिए; समग्र विकास सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
 - ➔ परामर्श सेवाएँ, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और समावेशी सामुदायिक स्थान जैसे हस्तक्षेपों का सुझाव दीजिए।
 - ➔ आर्थिक विकास के साथ-साथ प्रसन्नता को एक मुख्य नीतिगत लक्ष्य के रूप में मानने की आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
- **निष्कर्ष:** शासन में कल्याण के संकेतकों को एकीकृत करने और लोगों पर केंद्रित, सहानुभूतिपूर्ण सार्वजनिक नीति को बढ़ावा देने का सुझाव दीजिए।

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल
- ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं
अंतर्राष्ट्रीय संबंध



2025

ENGLISH MEDIUM
23 MARCHहिन्दी माध्यम
23 मार्च

2026

ENGLISH MEDIUM
11 MAYहिन्दी माध्यम
11 मई

14. सेल्फ-इवेल्युएशन



प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

एक्टिविटी	कुल प्रश्न	सही उत्तर	अटेम्प्ट	स्कोर/परसेंटेज
MCQ's				
ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स				



मंथली लर्निंग समरी

टॉप 3 लर्निंग/ इनसाइट्स

1.

2.

3.



प्रोग्रेस की तुलना

पिछले महीने का स्कोर

इस महीने का स्कोर

किस क्षेत्र में सुधार हुआ



रिफ्लेक्शन सेक्शन

मजबूत पक्ष

सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्र

अगले महीने के लिए लक्ष्य



सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

27 मई, 11 AM

अवधि – 12 महीने



VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए



निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए



डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए



- ▶ सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- ▶ अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- ▶ इस कोर्स में पर्सनलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- ▶ 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- ▶ प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3-4 घंटे, सप्ताह में 5-6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र



नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है



सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री



नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ईमेल/लाइव चैट के माध्यम से "वन-टू-वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।



ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।



कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सज को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।



बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सज को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरूरत के अनुसार ऑर्गनाइज कर सकते हैं।

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

10

in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**

from various programs of **Vision IAS**

1

AIR



Shakti Dubey

2

AIR



Harshita Goyal

3

AIR



Dongre Archit Parag

4

AIR



Shah Margi Chirag

5

AIR



Aakash Garg

6

AIR



Komal Punia

7

AIR



Aayushi Bansal

8

AIR



Raj Krishna Jha

9

AIR



Aditya Vikram Agarwal

10

AIR



Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137

AIR



Ankita Kanti

182

AIR



Ravi Raaz

438

AIR



Mamata

448

AIR



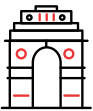
Sukh Ram

509

AIR



Amit Kumar Yadav



DELHI

HEAD OFFICE

Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor,
Near Gate-6 Karol Bagh
Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER

Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER

Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066



enquiry@visionias.in



[@visioniashindi](https://www.youtube.com/@visioniashindi)



[/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc)



[/vision_ias_hindi/](https://www.instagram.com/vision_ias_hindi/)



[/hindi_visionias](https://www.telegram.com/hindi_visionias)